वैश्विक संवाद

8.1

17 भाषाओं में प्रति वर्ष में 3 अंक

वर्जिनिया फोंटेस के साथ समाजशास्त्र पर बातचीत

गुइलहर्मे लेत गोसेलव्स

कनाडा में XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस

मार्गरेट अब्राहम
रीमा विल्केस
पेट्रिहिशया अल्बानीज
फ्रैकोइस लचापेले
पैट्रिक जॉन बरनेट
मिशेल मेकआइवर
मिकी वेली
एलिस मैआलिनो
केरी वू

लैंगिकता एवं हिंसा

मेगी वाल्टर
जोसलीन वाल्ट्रा–उलोआ
जेकब प्रेहन
केमिला नायडू
मैग्डलेना ग्रेजीब
स्लिविया वाल्जी

मार्क्स एवं आज का समाजशास्त्र

गेसपर मिकलोस तमास
एरिक ओलिन राइट
एलेक्जेन्द्रां शीले
स्टेफनी वोह्ल
बॉब जेसप
गुइलहर्मे लेत गोसेलव्स
सतीश देशपांडे
मिशेल विलियम्स
राजू दास
डेविड फेसनफेस्ट

खुला अनुभाग

> चीन में वर्ग असमानताएं
> भारत में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय
> नई एवं इतने नये नहीं संपादकों का परिचय

पत्रिका

International Sociological Association

GD
अंक 8 / क्रमांक 1 / अप्रेल 2018
http://globaldialogue.isa-sociology.org/

> सम्पादकीय

अर्थशास्त्र का दृष्टि यदि बाजार एवं उसका विस्तार है और राजनीति विज्ञान का दृष्टि राज्य और राजनैतिक स्थिरता की गारंटी है तो समाजशास्त्र को दृष्टिकोण नागरिक समाज और सामाजिक की रक्षा है। बाजार की निरंकुशता और राज्य तानाशाही के काल में समाजशास्त्र–विशेष रूप से उसका सार्वजनिक चेहरा–मानवता के हितों की रक्षा करता है।

माइकल बुरावे, ए एस ए अध्यक्षीय भाषण, 2004

वैश्विक समाजशास्त्र के लिए (...) तीन चुनौतियां हैं। यदि प्रथम चुनौती समाज के समाजशास्त्र की रचना करना और द्वितीय समाज में समाजशास्त्र का निर्माण करना है, तीसरी चुनौती समाज के लिए समाजशास्त्र का निर्माण करना। ऐसा करते समय नगारिक समाज, जो समाजशास्त्र का मूल आधार है, की रक्षा करना आवश्यक है।

माइकल बुरावे, आई एस ए अध्यक्षीय भाषण, 2014

वैश्विक संवाद के हमारे पहले अंक की माइकल बुरावे के दो कथनों से शुरूआत कर, हम नये संपादकों के रूप में लोक और वैश्विक समाजशास्त्र की इस अनूठी मैगजीन/पत्रिका के समृद्ध इतिहास को स्वीकार कर रहे हैं। (देखें जीडी 7.4 में उनका सम्पादकीय)

पहला कथन ए एस ए के अध्यक्ष के रूप में माइकल का कार्यक्रम संबंधी भाषण से लिया गया है जिसमें वे लोक समाजशास्त्र को मजबूत करने के लिए दमदार आवाज उठाते हैं। दूसरे कथन में, जो XVIII आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस के उनके अध्यक्षीय भाषण से लिया गया है, में वे वैश्विक समाजशास्त्र की रूपरेखा को विकसित करते हैं। ''सार्वजनिक होना – वैश्विक होना'', इस प्रकार से माइकल इन दो भाषणों के मध्य के दस वर्षों को संपुटित करते हैं। यह वह दशक था जिसमें समाजशास्त्र की उनकी समझ और यह प्रश्न कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी तीखी बहस हुई। इसके अलावा, इस दशक में माइकल ने अमरीका में शिक्षण और शोध करने के बावजूद (या इसलिए) प्राधान्य समाजशास्त्रों को विवेचनात्मक दृष्टि से देख वैश्विक संवाद को प्रारम्भ किया। सात वर्षों के अन्दर ही उन्होंने दुनिया भर के समाजशास्त्रियों के साथ, इसे लोक समाजशास्त्र की एक कामयाब पत्रिका के रूप में विकसित कर दिया। आपको इसे स्वीकार करने के लिए कि वे क्षेत्र के भीतर विमर्श के परे उसे आवाज देने में एवं दुनिया भर के समाजशास्त्रियों को अपने शोध–निष्कर्षों, दुनिया के मामलों से सम्बन्धित कथन और अपने सहभागी विषय पर चिंतन के लिए मंच प्रदान करने में सफल हुए है, माइकल के समाजशास्त्र के विचार से सहमत होने की जरूरत नहीं है।

जब माइकल ने हमें पूछा कि क्या हम वैश्विक संवाद में संपादक के रूप में उसकी जगह लेने हेतु आवेदन करेंगे, हमें यह जानकर गौरव और हर्ष हुआ कि वे हमें इस कार्य हेतु विश्वसनीय मानते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट में किस तरह की चुनौतियां आती है का पूर्वानुमान लगाते हुए, हमने इसका निर्णय बिना सोचे विचारे नहीं किया। विषय की महत्वपूर्ण परंपराओं से जुड़ाव महसूस करने वाले लोक समाजशास्त्री के रूप में हमें जिसने राजी किया वह माइकल के भाषण में वर्णित ''बाजार निरंकुशता और राज्य तानाशाही का समय'' में भयानक/वीभत्स यथार्थ है और जो नये तरीकों से बल प्राप्त करने की चेतावनी दे रहा है।

हमारे समाज 1970 के दशक के मध्य से गहन और दूरगामी सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाओं से गुजरें हैं। इन प्रक्रियाओं को वैश्विक उत्तर एवं वैश्विक दक्षिण के साथ पूर्व और पश्चिम दोनों में विशिष्ट यति द्वारा पहचाने जा सकती हैं। उसमें 1970 के दशक का नव मंदी, राज्य साम्यवाद का विध्वंस, वित्तीय–पूंजीवादी विस्तार एवं वैश्वीकरण, ब्रिक्स देशों का अभ्युदय और 2008–09 का वैश्विक वित्तीय संकट सम्मिलित हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विराम में 1980 के दशक से दुनिया के विभिन्न भागों से कल्याण राज्यों में चलायमान विखण्डन, पुनर्गठन, पुनःविन्यास; नये प्रतिरोध आंदोलन; संसाधन और आधिपत्य पर आर्थिक, राजनैतिक और धर्म प्रोत्साहित युद्ध; अभूतपूर्व पैमाने पर बलात् प्रवसन; भौतिक दरिद्रता और पारिस्थितिक आपदाओं के फलस्वरूप संपूर्ण क्षेत्रों और देशों में सामाजिक संकट सम्मिलित हैं। हम नये दक्षिण पंथी लोकलुभावनवाद के ''अनुसारक विद्रोह'' (एडोर्नो के शब्दों में) और राज्य शासन के सत्तावादी स्वरूप जो समाज में उभरते समान रूप से प्रासंगिक लोकतंत्रीकरण आंदोलनों के आवश्यक रूप से टकराते है, की प्रवृत्ति के भी साक्षी हैं।

ये प्रघटनाएँ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के अत्यधिक जटिल समूह द्वारा पनपे असमान विकास का अधिक महत्वपूर्ण रूप से – नाटकीय रूप से भिन्न परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी समय, यद्यपि, हम अंतर और पारराष्ट्रीय अन्त सम्बन्ध और अभिसरण प्रवृत्तियों जैसे अन्यथा विशिष्ट पूंजीवाद का बाजार–केन्द्रित पुनर्गठन; अमरीका, यूरोप, एशिया एवं लेटिन अमरीका में एक साथ उभर रहे लोकलुभावन धाराएँ; लगभग सभी ओ ई सी डी देशों में वर्ग–विशिष्ट असमानताओं का नये सिरे से विकास; और लिंग एवं जातीयता/राष्ट्रीयता संबंधित असमानता के अक्ष की जबरन वापसी को देखते हैं।

यद्यपि इन घटनाओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या गहन रूप से विजातीय और विरोधाभासी भी है, यहां एक आम सहमति है कि ये परिवर्तन विषय के मर्म को प्रभावित करते हैं। एक पोस्ट–ट्रूथ दुनिया में, मुख्य रूप से सिर्फ ''सच'' को ढूँढने को समर्पित समाजशास्त्र अपनी सामाजिक प्रासंगिकता को पूर्ण रूप से खो देती है। एक

> >

ऐसे विषय के रूप में जो प्रभुत्व से स्वतन्त्र विमर्श पर भरोसा करता है ताकि वह सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण, चिंतन और उनकी आलोचना करने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, यह बर्बाद हो जायेगा। अतः सभी मतभेदों को अलग हटा के, समाजशास्त्रियों को अकादमिक और गैर अकादमिक जनता के मध्य संवाद प्रारम्भ करने में साझा हित को विकसित करना चाहिए। यह वे अपने योगदानों/लेखों से और समान चर्चा में संलग्न हो कर सकते हैं। वैश्विक संवाद के नये संपादकों के रूप में, हमारा उद्देश्य दुनिया भर से समाजशास्त्रीय अंतदृष्टि को एक साथ लाने और सामाजिक घटनाओं के साथ साथ हमारे विषय की उन्नति के बारे में जीवंत चर्चा को प्रोत्साहित करना है।

वर्तमान अंक निर्भरता सिद्धान्त की प्रमुख सिद्धान्तकारों में से एक और लेटिन अमरीका की मार्क्सवादी चिंतक, वर्जिनिया फोंटस के साक्षात्कार से प्रारम्भ करते हैं। वे हमें ब्राजील में सैद्धान्तिक शोध के इन shrauds के इतिहास और राजनैतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना के लिए स्वामित्वहरण की मार्क्सवादी अवधारणा की प्रासंगिकता एवं 2016 के संसदीय तख्तापलट के बार में घटनाक्रम की समझ पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हैं।

हमें XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस में 5000 से अधिक समाजशास्त्रियों के आने की उम्मीद है। वे हमारे समय के अहम मुद्दों के समक्ष अपने निष्कर्ष एवं समाजशास्त्र के कार्य पर चर्चा करेंगे आई एस ए अध्यक्ष मार्गेट अब्राहम खुलासा करती हैं कि कांग्रेस की थीम शक्ति, हिंसा और न्याय : चिंतन, प्रतिक्रिया एवं उत्तरदायित्व क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। पेट्रिजिया अल्बानीज, स्थानीय आयोजन समिति की अध्यक्ष और रीमा विल्कस कनाडियाई समाजशास्त्र परिषद की अध्यक्ष के साथ सम्पूर्ण कनाडा से युवा विद्वान हमें कनाडा और कनाडियाई समाजशास्त्र में कुछ अंतदृष्टि प्रदान करती हैं।

हिंसा और लिंग अक्सर वर्णित विषयों हैं। इन्हें सार्वजनिक ध्यान में लाने के लिए लगातार प्रयास हुए है और समस्या का फैलाव उग्रता को बढाता है। पोलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से मार्गरेट अब्राहम द्वारा आमंत्रित लेखक इन देशों की घटनाओं के बारे में लिखते हैं।

कार्ल मार्क्स का 200 वां जन्मदिन इस बात पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है कि उनके सिद्धान्त और विचारों पर समाजशास्त्र में कैसे चर्चा की गई। हमारे द्वारा कुछ विद्वानों को परिचर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह परिचर्चा समाजशास्त्र के इतिहास के गहन विश्लेषण को मार्क्स के सिद्धान्त और उनके कृत्यों की भिन्न परिपेक्ष्यों से आलोचना को परस्पर मिला देती है। उनके शिक्षाप्रद लेख दिखाते हैं कि मार्क्स किस प्रकार समाज के सिद्धान्त के लिए एक सन्दर्भ और सामाजिक घटनाक्रम की वैकल्पिक दृष्टि पर चर्चा के लिए एक सन्दर्भ हो सकता है। या कैसे उनकी नारीवादी परिपेक्ष्य से आलोचना की गई, कैसे उनके सिद्धान्त का सामान्य तौर पर वर्तमान पूंजीवाद के विश्लेषण में प्रयोग में ले सकते हैं और कैसे राज्य या कानून के विकास को मार्क्सवादी परिपेक्ष्य से समझा जा सकता है और बहुत कुछ। हम विभिन्न देशों के लेखकों द्वारा उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान के बारे में जान सकते हैं।

खुले खण्ड में एक लेख भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के बाजारीकरण के प्रभाव पर चर्चा करता है और हम एक लेख चीन में कार्य की स्थितियों पर प्रकाशित कर रहे हैं। इसके अलावा, वैश्विक संवाद का नया सम्पादकीय दल के सदस्य जो इस कार्य से जुड़े है और/जो हमारे साथ कार्य करना जारी रख रहे हैं अपना परिचय देते हैं।

माइकल बुरावे का उदार सहयोग, पत्रिका के वैश्विक दल एवं आई एस ए से सम्मिलित सभी निकायों द्वारा गरम जोशी से स्वागत ने इस नई शुरूआत को आसान बना दिया है। हम प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहेंगे और इस वृहद विश्वास के साथ हम वैश्विक संवाद के अपने संयुक्त/साझा कार्य को और दुनिया भर से नये विचार एवं सुझावों के उम्मीद करते हैं। ■

ब्रिजिड आलनबाकर एवं **क्लास डोरे**
वैश्विक संवाद के आने वाले संपादक हैं।

> ***वैश्विक संवाद*** को आईएसए वैबसाइट पर 17 भाषाओं में देखा जा सकता है।
> प्रस्तुतियां globaldialogue.isa@gmail.com. पर भेजी जानी चाहिए।

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> संपादक मण्डल

सम्पादक: ब्रिगेट ऑलनबाचर, क्लाउस डोरे

उप–सम्पादक: जोहान्ना ग्रबनर, क्रिस्टीन शिर्कर्ट

सह–सम्पादक: अपर्णा सुंदर

प्रबन्ध–सम्पादक: लोला बुसुती, अगस्त बागा

परामर्शक: माइकल बुरावे

मीडिया परामर्शक: गुस्तावो तानीगति

परामर्श सम्पादक मण्डल:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

क्षेत्रीय सम्पादक

अरब दुनिया: Sari Hanafi, Mounir Saidani.

अर्जेंटीना: Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

बांग्लादेश: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury.

ब्राजील: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

फ्रांस/स्पेन: Lola Busuttil.

भारत: रश्मि जैन, ज्योति सिदाना, प्रज्ञा शर्मा, निधि बंसल, पंकज भटनागर

इंडोनेशिया: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

ईरान: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Mitra Daneshvar, Vahid Lenjanzade.

जापान: Satomi Yamamoto, Masaki Yokota, Yuko Masui, Kota Nakano, Riho Tanaka, Masaki Tokumaru, Marie Yamamoto.

कजाखिस्तान: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

पोलेण्ड: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Łukasz Dulniak, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Aleksandra Senn, Anna Wandzel, Jacek Zych.

रोमानिया: Cosima Rughiniş, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Maria-Loredana Arsene, Timea Barabaş, Denisa Dan, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Alina Hoară, Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana Lotrea, Anda-Olivia Marin, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Adriana Sohodoleanu, Elena Tudor.

रूस: Anastasia Daur, Andrei Sinelnikov, Elena Zdravomyslova.

ताईवान: Jing-Mao Ho.

टर्की: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

वर्जिनिया फोण्टस, लेटिन अमरीका की अग्रणी मार्क्सवादी सिद्धान्तकार राजनैतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना एवं ब्राजील के 2016 के संसदीय तख्तापलट के बाद के विकासक्रम को समझने में उसकी व्यावहारिकता के लिए स्वामित्वहरण के मार्क्सवादी अवधारणा के महत्व पर चिंतन करते हुए।

XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस जुलाई 2018 में टोरंटो, कनाडा में होगी। पेट्रिशिया अल्बानीज, स्थानीय आयोजन समिति की अध्यक्ष और पांच युवा विद्वान हमें समकालीन कनाडियाई समाजशास्त्र के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

मार्क्स के 200 वीं जन्मदिवस के वर्ष में, दुनिया भर से समाजशास्त्री राज्य और कानून से लेकर नस्लवाद और नारीवाद तक के क्षेत्रों में समकालीन विकास को समझने के लिए मार्क्सवादी सिद्धान्त की निरंतर प्रासंगिकता पर चिंतन करते हैं।

GD

सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से
वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

सम्पादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

पूंजी साम्राज्यवाद पर : वर्जिनिया फोंटेस के साथ एक साक्षात्कार
गुइलहर्मे लेत गोंसेलव्स, ब्राजील द्वारा 6

> XIX आईएसए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस, टोरोंटो

शक्ति, हिंसा और न्याय
मार्गेट अब्राहम, यू. एस. ए. द्वारा 10

कनाडियाई समाजशास्त्र एवं विश्व कांग्रेस
रीमा विल्केस, कनाडा द्वारा 12

कनाडा में एकजुट होकर समाजशास्त्र के विकास का अवसर
पेट्रिजिया अल्बानीस, कनाडा द्वारा 14

स्थानीयता और वैश्विकता के मध्य कनाडियाई विश्वविद्यालय
फ्रेंकोइस लचापेले एवं **पेट्रिक जॉन बर्नेट**, कनाडा द्वारा 16

नये कनाडियाई स्नातक छात्रों पर छात्र ऋण के प्रभाव
मिशेल मैकाइवर, कनाडा द्वारा 17

एक नागरिक वैज्ञानिक बनना
मिकी वाली, कनाडा द्वारा 18

कनाडा में अस्मिता केन्द्रित कार्य और राजनैतिक नेतृत्व
एलिस मैंओलिनो, कनाडा द्वारा 20

उच्च भरोसे वाले कनाडा में क्या अप्रवासी भरोसा जीत पाते हैं?
केरी वू, कनाडा द्वारा 21

> लैंगिकता एवं हिंसा

अंतरानुभागिता, देशजता, लैंगिकता एवं हिंसा
मेग्गी वाल्टर, जोसलिन बाल्ट्रा–उलोआ एवं **जेकब प्रेहन**, ऑस्ट्रेलिया 23

दक्षिण अफ्रीका में यौन हिंसा एवं ''सुधारात्मक बलात्कार''
केमिला नायडू, दक्षिण अफ्रीका 25

पोलैण्ड में घरेलू हिंसा की उपस्थिति
मैग्डलेना ग्रेजीब, पोलैण्ड 27

शून्य हिंसा की तरफ
स्लिविया वाल्बी, यू. के. 29

> मार्क्स एवं आज का समाजशास्त्र

मार्क्स के 200 वर्ष 31

मार्क्स एवं समाजशास्त्र, 2018
जी. एम. तमास, हंगरी द्वारा 32

बढ़ते हुए पूंजीवाद के लिए मार्क्सवादी परंपरा की निरंतर प्रासंगिकता
ऐरिक ओलिन राइट, यू. एस. ए. द्वारा 34

नारीवाद मार्क्सवाद का सामना करता है
एलेक्जेन्ड्रा शीले, जर्मनी एवं **स्टेफनी वोट्ल**, आस्ट्रिया द्वारा 36

मार्क्स और राज्य
बॉब जेसप, यू. के. द्वारा 38

पूंजीवादी विजय – कानून के प्रति एक नया मार्क्सवादी उपागम
गुइलहर्मे लेत गोंसेलव्स, ब्राजील द्वारा 40

भारत में मार्क्स एवं समाजशास्त्र
सतीश देशपांडे, भारत 42

इक्कीसवीं सदी में मार्क्स
मिशेल विलियम्स्, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 44

मार्क्स एवं वैश्विक दक्षिण
राजू दास, कनाडा एवं **डेविड फेसनफेस्ट**, यू. एस. ए. द्वारा 46

> खुला अनुभाग

चीन में वर्ग असमानताएं और सामाजिक संघर्ष
जेनी चान, हांग कांग द्वारा 48

भारत में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन
निहारिका जायसवाल, भारत द्वारा 50

नई एवं इतनी नई नहीं संपादकीय दल का परिचय 52

"इतिहास के इस कठिन दौर में, हम समाजशास्त्री अपने समय के संघर्षों एवं विवादों से एक उदासीन दूरी बनाये नहीं रख सकते, अन्यथा हम नागरिक समाज के लिए अप्रासंगिक होने का जोखिम उठायेंगे"

मार्गरेट अब्राहम

> पूंजी साम्राज्य-वाद पर

वर्जिनिया फोंटेस के साथ एक साक्षात्कार

वर्जिनिया फोंटेस

वर्जिनिया फोंटेस लेटिन अमरीका में आज सबसे प्रतिष्ठित मार्क्सवादी विचारकों में से एक है। वे रियो डी जिनारियो, ब्राजील के फ्लूमिनेन्जे संघीय विश्वविद्यालय (यू. एफ. ए.) में सामाजिक इतिहास की प्रोफेसर एवं ओस्वाल्डों क्रूज फाउंडेशन (फियोक्रूज) में वरिष्ठ शोधकर्ता थी। 2005 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रिफ्लेक्सोज इम पर्टिनेन्ट्स : हिस्टोरिया इ केपितालिस्मों कन्टेम्पोरानियो में, उन्होंने पूंजीवाद के विकास और उसके वस्तुकरण के नये स्वरूपों की सैद्धान्तिक मीमांसा एवं अनुभवजन्य विश्लेषण के संयोग से जांच की। स्वामित्वहरण की अवधारणा पर आधारित उनके शोध ने सामाजिक सिद्धान्त में राजनैतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की बहाली को प्रतिबिंबित किया। 2010 में प्रकाशित, व्यापक रूप से विख्यात ओ ब्राजील इ ओ केपिटल – इम्पीयरलीस्मो तियोरिया इ हिस्टोरिया ने उनकी सोच के चरमोत्कर्ष को अंकित किया। निर्भरता के मार्क्सवादी सिद्धान्त के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक, रूये मौरो मारिनी के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत में, उन्होंने साम्राज्यवाद के एक नये सिद्धान्त का प्रस्ताव रखा जिसने लेटिन अमरीकी मार्क्सवाद को 1960 के दशक की थीसिस से आगे जाने में मदद की। यहां रियो डी जिनारियो राज्य विश्वविद्यालय में विधि के समाजशास्त्र की **प्रोफेसर गुइलहर्मे लेत गोंसेलव्स** द्वारा लिया गया उनका साक्षात्कार प्रस्तुत है।

गुइलहर्मे लेत गोंसेलव्स : ज्ञान के निर्माण और प्रसार में निर्भरता का सिद्धान्त उल्लेखनीय रूप से लेटिन अमरीकी विचारों को परेशान करने वाली बौद्धिक अधीनस्थता पर काबू पाता है। वैश्विक स्तर पर यह अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया है। पूंजीवादी समाज के ढाँचों का विवरण और आलोचना करने की क्षमता के आलोक में क्या इस मान्यता की व्याख्याय करना संभव है?

वर्जिनिया फोंटेस : निर्भरता के मार्क्सवादी सिद्धान्त (एम टी डी) को पूंजीवादी विरोधी परिणामों के बजाय ''अनुकूलन'' वाले उपागमों से विलग करने के गंभीर सैद्धान्तिक प्रयास हो रहे हैं। डब्लू. डब्लू. रोस्टो की पुस्तक आर्थिक वृद्धि के चरण : एक गैर–साम्यवादी घोषणापत्र (1960), अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मंत्र बन गई। इसने, ''स्वयं को विकसित'' करने के लि ''अविकसित'' देशों को क्या कदम उठाने

> >

चाहिए, को उन पर थोपा। कई विश्लेषणों ने उन्हें गलत साबित किया है। इसी एलएसी/सीइपीएल जैसी संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं ने दर्शाया कि पूंजीवाद के विस्तार ने देर से आने वाले देशों के विकास को अवरूद्ध किया चूंकि ''असमान विनिमय'' ने इन देशों द्वारा उत्पादित धन सम्पदा को कम किया जिसने उनके औद्योगीकरण में बाधा डाली। अन्य लोगों ने परिधीय देशों में अल्प विकास को पूंजीवादी विकास के एक स्वरूप के रूप में माना। आलोचना के बावजूद, इस तरह के सिद्धान्त ''पूंजीवादी विकास'' के अन्तर्गत फँसे रहे।

एमटीडी इन उपागमों के परे चला गया। पूंजीवाद के विस्तार को असमानताओं के गहरे होने के लिए उत्तरदायी मानने के विश्लेषण के रूप में इसने पूंजीवादी सम्बन्धों की सम्पूर्णता को सम्बोधित किया और मूल्य सिद्धान्त के माध्यम से परिधि में पूंजीवाद के विस्तार के विशिष्ट स्वरूपों का विश्लेषण किया। पूंजीवाद के न सिर्फ अल्प विकास या निर्भरता के इसके विभिन्न स्वरूपों पर बल्कि पूंजीवाद स्वयं पर काबू पाने की जरूरत को दोहराने पर इसने वृहत सैद्धान्तिक और व्यवहारिक छलांग लगाई।

जी एल जी : आपके कार्य में, परिधीय पूंजीवाद पर रूये मौरो मारिनी की थीसीस की विवेचनात्मक/समीक्षात्मक अभिस्वीकृति है। मारिनी के लिए, लेटिन अमरीकी पूंजीपति वर्ग की निर्भरता श्रम के अत्यधिक शोषण के कारण मूल्य के नियम की निरू) प्रकार्य से क्षेत्र में विकृत पंजीवाद पनपेगा। अर्थात् श्रमिकों के उपभोग के लिये आवश्यक कोष से पूंजी संचय के कोष में परिवर्तित कर, परिधीय पूंजीपति वर्ग अधिशेष मूल्य का एक भाग अपने लिए और आंशिक भाग पूंजीवादी केन्द्र को सौंपने की व्यवस्था करता है। इस थीसिस के समक्ष क्या बाधाएं हैं?

वी एफ : इस विषय पर दोहरे दृष्टिकोण के साथ मारिनी एक मौलिक विचारक हैं। उनके लिए, किसी एक परिधीय देश द्वारा निभाई भूमिका का निश्चित तौर पर पता नहीं लगाया जा सकता है। साम्राज्यवाद, स्थानीय पूंजीवादी संचय, सामाजिक संघर्ष, राज्य इत्यादि से सम्बन्धित कई चर हैं। उनका विश्लेषण ऐतिहासिकता से परिपूर्ण है क्योंकि यह देशों के जड़ और कठोर पदानुक्रम और अन्य प्रकार के अपचयनवाद को खारिज करता है जिसके कारण वे अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद के परिवर्तन के संदर्भ में ब्राजील के उप–साम्राज्यवाद को समझने में सक्षम हुए। इसके अलावा, उन्होंने साम्राज्यवाद के तहत मूल्य के नियम के प्रति एक संरचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया : परिधीय देशों में श्रमिकों का अत्यधिक शोषण और उत्पादन एवं उपभोग के चक्रों के मध्य विभाजन ने पूंजीवादी केन्द्रों को मूल्य हस्तांतरण की व्याख्या की। इस प्रकार, मारिनी ने साम्राज्यवाद और मार्क्स के मूल्य के सिद्धान्त की सार्वभौमिकता के मध्य और राष्ट्रीय विशेषताओं एवं साम्राज्यवादी तनावों के मध्य विरोधाभासों को अपनी नजर में रखा।

इन निर्भीक कथनो के लगातार पुनर्व्याख्या की आवश्यकता होती है चूंकि वे पूंजीवादी सम्बन्धों के विस्तार और निर्भरता की असमान पुनर्स्थापना की प्रक्रियाओं दोनों को एक साथ संबोधित करते हैं। वे हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं कि निर्भरता देशों के मध्य स्थिर सम्बन्धों का उत्पादन नहीं करती है, न ही वह पूंजीवाद के भीतर निरंतर उप चक्र के रूप में आती है। इसके बजाय, यह अपने विरोधाभासों की गहनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैंने कृषकों के स्वामित्वहरण की तीव्र प्रक्रिया के बाद के काल में ब्राजील में पूंजीवादी सामाजिक सम्बन्धों के विस्तार का विश्लेषण किया हैं कृषकों के ''रिजर्व'' में कमी के साथ, मूल्य के नियम की फैलने की प्रवृत्ति बाधित नहीं अपितु मजबूत हुई है। ऐसा श्रम–शक्ति के पुनरूत्पादन की सामाजिक–ऐतिहासिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुआ। तीव्र संघर्ष के द्वारा श्रमिकों ने अपनी स्थिति में मामूली सुधार प्राप्त किया लेकिन ये जल्दी ही पूंजी द्वारा अग्रेषित/प्रोत्साहित दैतीयक स्वामित्वहरण के आक्रामक चक्र द्वारा अनुगामित हुए। ये दैतियक स्वामित्वहरण केन्द्रिय देशों को भी प्रभावित करते हैं, यही कारण हैं कि मारिनी की सुपर–शोषण की थीसिस की अंतरराष्ट्रीय स्थिति के आलोक में लगातार जांच होनी चाहिए।

उत्पादन और उपभोग के मध्य विभाजन के सम्बन्ध में भी कई परिवर्तन हुए हैं। 1960 के दशक में ब्राजील के उद्योग विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, जो मुख्य रूप से लघु सामाजिक वर्ग या फिर निर्यात के लिए नियत थे। हालांकि 1970 के बाद से, उपभोक्ता क्रेडिट ने ऐसी वस्तुओं तक पहुंच को विस्तारित किया जिसने उत्पादन और उपभोग के मध्य दूरी को परिवर्तित किया लेकिन साथ ही में असमानताओं को बढ़ाया। मारिनी ने दावा किया ब्राजील का उप–साम्राज्यवाद वस्तुओं के निर्यात (सुपर–शोषित श्रमिक वर्ग के कम उपभोग के परिणाम के कारण) द्वारा और राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता से परिभाषित होता है। इस अर्थ में, मैंने स्पष्ट किया है कि 1990 के दशक से ब्राजील की कम्पनियों का अन्य परिधीय देशों में विस्थापन और प्रत्यक्ष रूप से पूंजी का निर्यात या अन्य देशों में श्रम–शक्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने वाली ब्राजील की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना इस उप–साम्राज्यवाद के गवाह हैं। मुझे मारिनी के लेखन में परिधीय देशों में ''विकृत पूंजीवाद'' की प्राकल्पना दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि इस विचार का अर्थ है कि यह पूर्व चरण 'सामान्यीकृत पूंजीवाद' में विकसित हो सकती थी, जो कि गलत/झूठी मान्यता है।

जी एल जी : मारिनी के उप–साम्राज्यवाद और आपके पूंजी साम्राज्यवाद की अवधारणा में क्या अंतर है? 'पूंजी साम्राज्यवाद' क्यों?

वी एफ : हमारे विश्लेषण में कई दशकों का अंतर है। जहां मारिनी मूल्य हस्तान्तरण के संरचनात्मक प्रक्रिया पर जोर देती हैं, मैं श्रम के लिए उपलब्ध मानवों के सामाजिक उत्पादन (स्वामित्वहरण), सपत्ति के संकेन्द्रीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के विशिष्ट स्वरूपों, मूल्य निष्कर्षण के नये तरीकों और राज्यों एवं राजनीति के पुनर्रचना (ग्राम्शी से विलग होते हुए) के मध्य सहसम्बद्ध देखती हूं। सामाजिक विरोधाभासों में तेजी पूंजी और श्रम के मध्य विरोध को उत्तरोत्तर प्रत्युत्तर देती है, तब भी जब वह अन्तर–पूंजीवादी–साम्राज्यवादी तनावों में विस्थापित होती है।

मैंने पूंजी साम्राज्यवाद विस्तार को पूंजीवाद की एक नयी श्रेणी कहा है जिसमें केंद्रित और प्रतिस्पर्धी पूंजी संघ में कार्य करती है। पूंजी के आंतरिक वर्चस्व को बाजार, निर्यात, पूंजी संचलन के माध्यम से बाह्य विस्तार के आवश्यकता है और यह भूमि, अधिकारों और पर्यावरण की अस्तित्व संबंधी परिस्थितियों और सम्पूर्ण आबादी के जीव विज्ञान के स्वामित्वहरण को बढ़ावा देती है। पूंजी के लिए आधारभूत सामाजिक सम्बन्धों को तीव्र साम्यवाद–विरोध के आधार पर सामान्यीकृत किया जाता है। पूंजीपति वर्ग के नये भाग और कुछ परिधीय देशों मजबूत होते हैं लेकिन उनके राजनैतिक संगठनों की विविधता नाममात्र के ''लोकतांत्रिक'' ढांचे में सिकुड़ती है। एवं कुछ छोरों पर केन्द्र पूंजी के केन्द्रीकरण और सघनता का पैमाना ''शुद्ध सम्पत्ति'' के अश्लील संलयन में बदलता है जो अधिकाधिक ''अमूर्त'' और ''सामाजिक'' है। पूंजी के मुट्ठीभर बड़े मालिक पूंजी का मूल्यवर्धन करने के लिए दौड़ते हैं और ''कार्यशील पूंजीपतियों'' को मूल्य निष्कर्षण के अधिक विविध, यहां तक कि क्रूर तरीकों से धकेलते हैं। उत्पादन के सामाजिक संसाधनों (मूल्य के निष्कर्ष्ण के लिए उत्पादन के साधनों और श्रम–शक्ति को एकत्रित करने की क्षमता) की निजी सम्पत्ति निरपेक्ष हो जाती है। एकाधिक स्वामित्वहरण तीव्र होते हैं जो प्रत्येक मानवीय गतिविधि के औद्योगीकरण और श्रमिकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को तेज कर श्रम के नये और भयानक रूपों को उत्तेजित करते हैं।

>>

मैंने नवउदारवाद और संकट जैसे शब्दों से बचने की कोशिश की है। नवउदारवाद ''सभ्य'' पूंजीवाद का पतन नहीं है क्योंकि यह पूंजी–साम्राज्यवाद के विस्तार का परिणाम है न कि उसके संकट का। हम उसके नाटकीय विस्तार के तहत रह रहे हैं : संकट ''शुद्ध'' सम्पत्ति को छुए बिना श्रमिकों के बढ़ते जनसमूह को प्रभावित करते हैं। पूंजी का स्थानिक विस्तार राष्ट्रीय स्पेस में श्रमिक वर्ग के राजनैतिक संपुटीकरण के विरोधाभास के साथ मेल खाता है। मानवता का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादन और/या परिसंचरण की प्रक्रिया को एकीकृत करता है जिससे असमानताएँ ताजा हो जाती हैं। प्रतिनिधित्वपूर्ण–चुनावी प्रारूप फैलाया जाता है लेकिन लोकतंत्र को धन–आधारित निरंकुश प्रारूप के रूप में कमतर किया जाता है। राजनैतिक कार्यवाही द्विध्रुवी हो जाती है : पूंजी के लिए अंतरराष्ट्रीय और श्रम के लिए विखंडित/या तो आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष), अनौपचारिक राजनीति (गैर लाभकारी संस्थाओं के प्रसार) या राज्यों के मध्य औपचारिक राजनीति के माध्यम से तीव्र/गहन बुर्जुआ सक्रियतावाद होता है। विशेषज्ञ आयोगों और संवैधानिक अवरोधों से पूंजीपति वर्ग पूंजीवाद पर काबू पाने के किसी भी लोकप्रिय प्रयास को रोकने की कोशिश करता है। राज्यों के अंतर्गत पूंजी से पोषित से पोषित नौकरशाही लोक प्रशासन में हावी होती है जो लोकतांत्रिक पहलुओं और हाशिये के लोगों की कार्यवाही के अंतर में कमी लाती है। पूंजी–साम्राज्यवाद विस्तार–न कि संकट–सामाजिक वर्गों और पूंजी–साम्राज्यवादी देशों के मध्य नये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तनावों को अग्रेषित करता है।

जी एल जी : पूंजी–साम्राज्यवाद की धारणा की जड़ों में स्वामित्वहरण के बारे में चर्चा पाई जाती है जो तथाकथित आदिम संचय पर मार्क्स के चिंतन को संदर्भित करती है। रोजा लक्समबर्ग तक पीछे जा कर इस बहस की लंबी परम्परा है। आप इस परम्परा में कैसे फिट होती हो? स्वामित्वहरण का अर्थ क्या है और अधिशेष मूल्य के निष्कर्षण से इसका क्या सम्बन्ध है?

वी एफ : मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि स्वामित्वहरण पूंजीवादी सामाजिक गतिशीलता को एकीकृत करता है। वे सिर्फ उसके ''पूर्व के क्षण'' नहीं है। स्वतन्त्र श्रमिकों का अस्तित्व उसके महत्वपूर्ण सामाजिक सम्बन्धों के विस्तार का सामाजिक आधार है जिसमें मूल्य निष्कर्षण के लिए पूंजी और श्रम सन्निहित हैं (मूल्य का मूल्यवर्धन)। आजकल यह भीमकाय अवशिष्टता पूरी आबादी तक पहुंच जाती है। इससे एकल प्राणी आधारभूत आवश्यकता में बदल जाता है, किसी भी स्थिति में श्रम–शक्ति की बिक्री के लिए अनिवार्य अवशिष्ट/व्यापक स्वामित्वहरण पूंजीवादी विस्तार की प्रारंभिक सामाजिक स्थिति और परिणाम है।

अभी हाल तक, दुनिया की आबादी का विशाल बहुमत ग्रामीण इलाकों में पूर्व–पूंजीवादी परिस्थितियों में निवास कर रहा था। ग्रामीण दुनिया शहरी पूंजीवाद की तुलना में एक प्रभावी बाध्यता के रूप में दिखाई देती थी लेकिन यह बदल गया है। रोजा लक्समबर्ग का मानना था कि पूंजी के विस्तार को पूंजीवादी समाजों की सख्त सीमाओं के अन्तर्गत व्यापारिक उपलब्धियों की असंभवता के कारण गैर–पूंजीवादी सरहदों की आवश्यकता होती है। डेविड़ हार्वे ने इस निरूपण को रूपांतरित करते हुए कहा कि आज पूंजीवाद इस तरह के बाहरी कारक (बेदखली जो ''सामान्यीकृत'' पूंजीवाद के ओर खुलने को दर्शाती है) पैदा करता है। मैं इससे असहमत हूं : कभी भी ''सामान्यीकृत'' पूंजीवाद नहीं रहा है, और जिन देशों में लगा कि ऐसा हुआ, उन्होंने मूल्य निष्कर्षण के लिए बर्बर और साम्राज्यवादी तरीके प्रयोग के लिए। ये विचारोत्तेजक प्रस्ताव हैं लेकिन हमें जोर देना होगा कि पूंजी के लिए आंतरिक बुनियादी सामाजिक सम्बन्ध आवश्यकताओं का उत्पादन है और उनमें से प्रथम है सामाजिक प्राणियों का उत्पादन जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए बाजार की आवश्यकता है। रोजा लक्समबर्ग हमें पूंजीवादी सामाजिक संबंधों के निरंतर विस्तार की भारी भूमिका की याद दिलाती हैं।

जी एल जी : स्वामित्वहरण की अवधारणा किस हद तक राजनैतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना के रूप में मार्क्सवादी विश्लेषण को समझने के लिए आधारभूत है?

वी एफ : स्वामित्वहरण की अनदेखी करना अब संभव नहीं है। जहां (पुराना) भूमि स्वामित्वहरण अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, सदियों से शहरी आबादी पर नये प्रकार के स्वामित्वहरण ने हमला किया है। मैं इसे दैतियक स्वामित्वहरण कहती हूं। वे उत्पादन के साधन के उपर सम्पत्ति का ह्रास जैसे भूमि का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वर्तमान में, दैतीयक स्वामित्वहरण दो तरह से कार्य करते हैं : 1) सोलहवीं और अठारहवीं सदी के अंग्रेजी संसदीय स्वामित्वहरण के समान जैसे अधिकारों का चालू पलटाव जिसमें श्रम अनुबंध से सम्बन्धित भी थे, जिन्होंने कई मामलों में अनुबंधों को खुद दबा दिया; सरकारी उपक्रमों का निजीकरण; और मूल्य के निष्कर्षण के लिए गतिविधि के बड़े क्षेत्रों को खोलना, विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य; 2) प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और जंगल जो सामाजिक उपयोग के लिए थे और दशकों पूर्व जिनका एकाधिकार स्वामित्व अकल्पनीय था, का स्वामित्वहरण। वास्तव में, जीव प्रजनन की स्थितियों पर जैविक और मानवीय जीवन के पेंटेर के और अंतक ट्रांसजेनिक बीजों के माध्यम से एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है।

उत्पादन के सामाजिक संसाधनों के संकेंद्रण और स्वामित्वहरण के मध्य सहसम्बन्ध दिखाने से यह चिन्हांकित होता है कि कैसे पूंजीवाद बिना श्रम और मूल्य निष्कर्षण के अस्तित्व में नहीं रह सकता हैं यह सबसे बर्बर से अंतरराष्ट्रीय टकराव से वंचित श्रमिकों पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय टकराव से वंचित श्रमिकों पर बढघते अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को थोपकर सर्वाधिक नवाचार वाले बहुल और संबद्ध रूपों को ग्रहण करता है। ''वित्तीयकरण'' के बारे में बात करना काफी नहीं है, जैसे कि वहां अच्छे (उत्पादक) और बुरे (वित्तीय) पूंजीपति थे : वे एकजुट हैं और अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में एक साथ काम करते हैं और दोनों श्रमिकों से मूल्य के निष्कर्षण पर निर्भर हैं।

जी एल जी : आप 2016 के ब्राजील के संसदीय तख्तापलट की व्याख्या कैसे करती हैं?

वी एफ : प्रचलित सामाजिक सम्बन्धों (बड़े पैमाने पर प्राथमिक और दैतीयक स्वामित्वहरण और मूल्य निष्कर्षण के विविध तरीकों से पूंजी का संकेन्द्रीकरण) के कारण ब्राजील एक पूंजीवादी देश है और इसमें पूंजी साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी औद्योगीकरण की प्रक्रिया है। पूंजी–साम्राज्यवाद की रक्षा में ब्राजील के पूंजीपति वर्ग की सक्रिय भूमिका रही है; उन्हें कार्डोसा (पी एस डी बी) सरकार में निजीकरण और पूंजी दान के माध्यम से प्राप्त स्थायी वृद्धि से लाभ हुआ। वर्कर पार्टी के नेतृत्व में आने वाली सरकार ने भी अधिकारों का स्वामित्वहरण किया लेकिन परिष्कृत रूप से। उन वर्षों के दौरान, ब्राजील के पूंजीपति वर्गों के भागों ने राजनैतिक कार्यवाही के आधिकारिक (चुनावी अभियान कोष पोषण के द्वारा) और अतिरिक्त आधिकारिक स्वरूपों को अमल में लिया। गैर–लाभकारी संगठनों के द्वारा उन्होंने सहभागिता के साधनों, संसाधनों की कमी, और अपराधीकरण के माध्यम से श्रमिक वर्ग के प्रयासों को बेअसर करने की कोशिश की।

2016 का तख्तापलट 2013–14 से प्रारम्भ आर्थिक संकट के द्वारा प्रोत्साहित था और उसने प्रचलित व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया।

>>

भ्रष्टाचार राष्ट्रीय खुलासे में था जिसने कमजोर बुर्जुआ अंशों को एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्राजील की कुछ कम्पनियां बहुराष्ट्रीय बन गई जिसने अंदर और बाहर तनाव को बढ़ा दिया। उनके स्थानीय प्रबन्ध विदेशी प्रतिस्पर्धियों द्वारा सूचित किये जाते थे। और न्यायिक उत्पीडन ने दर्शाया कि आंतरिक और बाहय पुनः प्रबंधन की आवश्यकता थी। इन प्रभुत्वशील वर्गों का एकीकरण श्रमिकों के क्रूर और तीव्र दैतीयक स्वामित्वहरण पर आधारित था।

पूंजी–साम्राज्यवाद के तहत् हाल ही में ब्राजील के लोकतंत्र ने आबादी को संतुष्ट करने की पूर्वधारणा को मानते हुए ब्राजील की राजधानी के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए समर्थन आश्वस्त किया है। इस तरह एक पूंजीवादी समर्थक वाम (पी टी) को प्रक्रिया सुरक्षित करने के लिए अनुमति दी गई। हालांकि इसने चुनावी प्रतिस्पर्धा को और उसकी लागत को बढा दिया। अपने अति–दक्षिणपंथी अमरीकी समकक्षों के समर्थन से ब्राजील के समूहों ने पी टी का अपराधीकरण कर किसी भी वाम दल को राजनैतिक प्रमुखता तक पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से तीव्र साम्यवादी विरोधी अभियान को वित्तपोषित किया। टेलीविजन प्रसारण के उपर एकाधिकार ने एकतरफा फरमान जारी किया जिसे सामान्य तौर पर आबादी के अडियल क्षेत्रों के खिलाफ पुलिस और अर्द्धसैनिक हिंसा का साथ मिला। यह सब बुर्जुआ संस्थाओं के शासन और उनके नियंत्रण के तहत हुआ। हम पूंजी के हितों के त्वरित संवैधानिकरण को देख रहे हैं जो स्वामित्वहरण और मूल्य निष्कर्षण के उपद्रवी स्वरूपों जिसमें सार्वजनिक ऋण के राजस्व के मालिक (देशज या नहीं) का आश्वासन देती है। संविधान को तब लागू किया जाता है जब वह पूंजीपतियों (ब्राजील के या विदेशी) के हितों से मेल खाता है। ■

सीधा संपर्क करे :
गुइलहर्मे लेत गोंसेलव्स <guilherme.leite@uerj.br>
वर्जिनिया फोंटेस <virginia.fontes@gmail.com>

> शक्ति, हिंसा और न्याय

मार्गरेट अब्राहम, होफस्ट्रा विश्वविद्यालय, अमरीका, आई.एस.ए. अध्यक्ष और XIX आई.एस.ए. समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस की कार्यक्रम समिति की अध्यक्ष

मेट्रो कन्वेंशन सेंटर जुलाई 15–21, 2018 तक आयोजित XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस, का स्थान होगा।

यह कल्पना करना कठिन है कि हम टोरंटो, कनाडा में होने वाली XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस से कुछ ही महीने दूर हैं। विषय के प्रारम्भ से ही, समाजशास्त्री शक्ति, हिंसा और न्याय एवं समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभाव से चिंताकुल रहे हैं। वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों ने इस समाजशास्त्रीय चिंताओं की प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। हमारे आज के समय में अधिक तात्कालिकता से इन मुद्दों के साथ पुनः सम्बद्ध होने की आवश्यकता है। ''शक्ति, हिंसा और न्याय : चिंतन, प्रतिक्रिया और उत्तरदायित्व'' की थीम के साथ यह कांग्रेस समाजशास्त्रियों एवं अन्य समाज वैज्ञानिकों को संवाद करने, बहस करने और हमारे जीवन को विविध प्रकार से प्रभावित करने वाली इन मुख्य चिंताओं को संबोधित करने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

इस कांग्रेस में लगभग 1200 सत्रों का आयोजन किया गया है और 10,000 से भी अधिक सारांश सबमिट हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया भर से 5000 से अधिक प्रतिभागी 15 से 21 जुलाई, 2018 में टोरंटो, कनाडा में ज्ञान को साझा करने, विचारों को आदान प्रदान और चिंतन करने और कांग्रेस की थीम पर उठने वाले मुद्दों पर दृष्टिकोणों की विस्तृत श्रंखला को प्रदान करने आयेंगे। XIX आई एस ए विश्व कांग्रेस की थीम, शक्ति–राजनैतिक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक–जो समाज को गढ़ने और बदलने में प्रबल ताकत है, की तरफ संकेत करती है। विषयों की समाविष्ट व्यापक श्रृंखला हमारे समक्ष की चुनौतियों की तरफ इशारा करती है लेकिन साथ ही में यह हमारी दुनिया को प्रभावित करने वाली हिंसा और अन्याय के समाधान खोजने की प्रतिबद्धता को भी दिखाती हैं।

> >

> समाजशास्त्र और समाज की मुख्य चिंताएं

हम जानते हैं कि समाजशास्त्रियों की एक प्रमुख चिंता सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन करना है। हालांकि, यह समझना कि चीजें जैसी है वैसी क्यों हैं, काफी नहीं हैं। हमें अपने समाजशास्त्रीय ज्ञान को विश्व को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लेने की आवश्यकता है। इस कोशिश में हमें सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करना होगा और अपने समय की मुख्य चुनौतियों पर आम जनता के साथ संलग्न होना होगा। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र को शक्ति एवं शक्तिशाली के बारे में प्रश्न करने; उदाहरण के लिए औपनिवेशिक इतिहास और समकालीन भूमि विनियोग की जांच एवं आलोचना करने; देशज और अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हिंसा को जारी रखने वाली संरचना और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर चिंतन करने, पितृसत्ता और महिलाओं के विरूद्ध सतत हिंसा और भेदभाव को पुनः देखने; युद्ध और युद्ध–पश्चात् संघर्षों, गरीबी, नस्लवाल, लिंग और प्रतिच्छेदन हिंसा और बलात् प्रवसन और बेदखली का अध्ययन करने और एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ समाजशास्त्र को लामबंद करना होगा। इस संदर्भ में ''शक्ति'', ''हिंसा'' और ''न्याय'' प्रभावी सम्बोध हैं जो आज की दुनिया की प्रमुख चिंताओं, जिन्हें हमें सम्बोधित करने की आवश्यकता है, संपुटित करते हैं और इसलिये ये एकसाथ इस XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस की सामयिक और संगत थीम बनाते हैं।

हम हिंसा, युद्ध, संघर्ष और घृणा के देग के मध्य हैं और ऐसे समय में भी हैं जहां मौजूदा व्यवस्था हलचल में है, एक समय में पूजनीय संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं और लोकतंत्र स्वयं भी संकट में है। दुनिया के कई हिस्सों में, एक संस्था के रूप में राज्य को अति राष्ट्रवाद और अज्ञात व्यक्ति भीत आवेगों को प्रोत्साहित करने और अल्पसंख्यकों एवं असहमत गैर–अनुसारक समूहों पर अत्याचार करने हेतु अपनी शक्तियों के दुरूपयों करने वाले तंत्र के रूप में देखा गया हैं। यहां छोटे कमजोर राष्ट्रों पर अनियंत्रित हिंसा बरसाने वाले प्राधान्य कुलीन तंत्र है और अंतराष्ट्रीय व्यवस्था बनाये रखने वाली संस्थाएँ उन्हें असहाय होकर देखती है या अप्रभावी रहती है। समतावादी आदर्शों को शक्तिशाली की सेवा करने हेतु लचीले उपकरणों में तब्दील कर दिया है एवं ''लोकतंत्र को प्रोत्साहित'' करने के नाम पर पूरे राज्यों को तबाह किया जा रहा है। ''आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध'' को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और अधिकारों में कटौती हेतु उपयुक्त बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हैं। इसका स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र के लिए क्या अर्थ है? दुनिया को प्रताडित करने वाले हिंसा, घृणा और क्रोध के केन्द्र में बाजार में लाभप्रदता पर एकचित्त ध्यान केन्द्रित नवउदारवादी आर्थिक शासन द्वारा पैदा स्पष्ट अन्याय और असमानताएं हैं। इसके साथ–साथ राष्ट्रों में राज्य शक्ति को अभिजात वर्ग के प्राधान्य की रक्षा हेतु और यथास्थिति बनाये रखने के लिए नियमित रूप से काम में लिया जा रहा है। न तो राज्य की प्रधानता और न ही बाजार की शक्ति एक बेहतर दुनिया को बनाने में सफल हुए हैं। इस हिंसक, विवादास्पद दुनिया में समाजशास्त्री के रूप हमारा उत्तरदायित्व असमानता और अन्याय को उत्तेजित करने वाली प्रधान संस्थाओं, विश्वासों विचार धाराओं और प्रथाओं की जांच और प्रश्न उठाना है।

निराश के मध्य, आशा की एक किरण उन समूहों, अहिंसक आंदोलनों, मानवीय हस्तक्षेपों और शांति प्रक्रियाओं द्वारा दिखाई देती है जिन्होंने समुदायों को सशक्त किया, हिंसा में कमी और न्याय को प्रोत्साहित किया है। अत्याचार के खिलाफ विरोध, विशेषाधिकार प्राप्त और अन्य के मध्य खाई, पर्यावरणीय क्षति, बेरोजगारी और अन्य अन्यायों के इर्द गिर्द घूमने वाले प्रतिरोध आंदोलनों ने शक्ति दलालों को चुनौती दी है। यद्यपि, जब प्रतिरोध खत्म हो जाता है या आंदोलन संस्थागत परिवर्तन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने तक कायम नहीं रहते हैं तो अभिजात वर्ग और यथास्थिति की बहाली लगभग अपरिहार्य होती है और यह अक्सर दमन की तीव्रीकरण के साथ होती है। नागरिक प्रतिरोधों का प्रक्षेपवक्र इस बात की याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य अन्तहीन, अक्सर निराशायुक्त खोज है लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। लोकहित सम्बन्धित मौलिक मुद्दों को उठाने से, यह कांग्रेस नागरिक समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

कांग्रेस की थीम इस बात का जोरदार दावा करती है कि इतिहास के इस मुश्किल दौर में, हम समाजशास्त्री संघर्ष और हमारे समय के विवादों से एक उदासीन दूरी बनाये रखने का जोखिम वहन नहीं कर सकते हैं। अन्यथा हम मुख्य साझेदार, नागरिक समाज के लिए अप्रासंगिक होने का जोखिम उठायेंगे। इसका अर्थ है हमें अडिग प्रासंगिक वैश्विक लोक समाजशास्त्र कीपेशकश करनी होगी जो हमारे अत्यन्त परेशान दुनिया के जटिल मुद्दों के समाधान में सक्रिय रूप से संलग्न होगा। समाजशास्त्रियों, साथी समाज वैज्ञानिकों, पत्रकारों और कार्यकर्त्ताओं का इतना बड़ा जनसमूह नागरिक समाज को प्रभावित करने वाले घुमावदार राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रवाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। असमानता, प्रजातिकेन्द्रिकता, अति राष्ट्रवाद, अज्ञात जन भीति, और मानवाधिकार से सम्बन्धित हिंसा और सामाजिक न्याय के मुद्दे हमारे विचार विमर्श के मूल में होने चाहिए।

समाजशास्त्र अन्य विषयों की अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है और इसलिए यह समाज की सबसे अहम् चिंताओं के समाधानों की खोज में अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु विलक्षण रूप से स्थित है। ''शक्ति, हिंसा और न्याय'' की हमारी थीम राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, मनेविज्ञान और इतिहास जैसे विषय जो हमारी दुनिया के बारे में भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं और सामाजिक न्याय के इस कभी खत्म न होने वाले संघर्ष में महत्वपूर्ण भागीदार है, के लिए भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान अर्जन और साझा करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयासों में संलग्न होने के इस वैश्विक प्रयास में, XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस समाजशास्त्रियों और विभिन्न विषयों के वक्ताओं के लिए सत्रों की व्यापक श्रंखला के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अपने दृष्टिकोणों को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करेगी। मैं आपको टोरंटों में देखने के लिए उत्सकुक हूं। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर अपनी परेशान दुनिया के जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों की समझ को गहरा करेंगे और हिंसा को अंजाम देने वाली और समानता एवं न्याय को विध्वंस करने ताकतों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी तरीके ढूंढेंगे। ■

सीधा संपर्क करे : **मार्गरिट अब्राहम** <Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

> कनाडियाई समाजशास्त्र एवं विश्व कांग्रेस

रीमा विल्केस, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, कनाडा समाजशास्त्र संघ की अध्यक्ष, आई एस ए विश्व कांग्रेस कार्यक्रम संयोजन एवं तर्क और पद्धतिशास्त्र की आई एस ए शोध समिति (आरसी 33) की उपाध्यक्ष एवं XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस की स्थानीय आयोजन समिति की सदस्य

कनाडाई समाजशास्त्री एवं कनाडा समाजशास्त्र संघ (http://www.csa-scs.ca/) के सदस्य XIX आई एस ए समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए अत्यन्त उत्सुक है। कांग्रेस टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में 15 जुलाई से 21 जुलाई 2018 में आयोजित होगी। परिणामस्वरूप, प्रतिभागी वेदांत, अनीशीनाबेक राष्ट्र और हॉदेनोसोनी कान्फ्रेड्रेसी की भूमि पर मिलेंगे। यह भूमि डिश विद वन स्पून वेमपन बेल्ट कोवेनान्ट जो ग्रेट लेक्स क्षेत्र और साथ ही न्यू क्रेडिट फर्स्ट नेशन का मिसिसुआगा क्षेत्र को शांतिपूर्ण ढंग से साझा करने और रक्षा करने का सहमति पत्र है, के अंतर्गत है।

जैसे क्षेत्रीय आभारोक्ति कनाडा के सार्वजनिक घटनाओं का उत्तरोत्तर भाग बन रही है, उनका स्पष्टीकरण देना उचित है। आभारोक्ति की जड़ों में पुराना देशज सक्रियता है और हाल ही में, इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल ट्रूथ एवं रिकन्सीलियेशन कमीशन 2008 से 2015 द्वारा एकत्रित ध्यान है। जहां आभारोक्ति भूत एवं वर्तमान नुकसान का समाधान नहीं है, जिन मुद्दों को यह परिपाटी उठाती है, वे समाजशास्त्र विश्व कांग्रेस की थीम–शक्ति, हिंसा और न्याय : चिंतन, प्रतिक्रिया एवं उत्तरदायित्व के अंतर्गत फिट

कनाडा के समाजशास्त्री दुनिया भर से आने वाले विद्वानों का स्वागत करने के लिए आतुर हैं।

> >

बैठते हैं। कनाडियाई संदर्भ में आभारोक्ति कभी कभी सराहना और कृतज्ञता प्रकट करने के साथ लोगों एवं प्रादेशिक इतिहास के प्रति जागरूकता दर्शाने के लिए भी काम में ली जाती है। आभारोक्ति एक राजनैतिक परिपाटी भी है–जो विशेष तौर पर गैर–देशज लोगों को अधिवासी उपनिवेशवाद के बारे में, संधि अनुग्रहों के बारे में और कनाडा का उनका अनुमोदन करने में विफलता के सम्बन्ध में एक कड़ा अनुस्मारक है।

आई एस ए विश्व कांग्रेस में दुनिया भर के हजारों विद्वानों के साथ आभारोक्ति जैसी परिपाटियों और अन्य कई द्वारा उठाये गये अत्यावश्यक मुद्दों पर सुनने, सीखने और संवाद कायम करने को असमानांतर सुअवसर प्रदान करेगी। जहां कुछ प्रतिभागी आई एस ए से प्रथम बार जुड़ेंगे, कईयों को दशकों का अनुभव होगा। आई एस ए के साथ जुड़ाव और विशेष तौर पर विश्व कांग्रेस से, हमें इस प्रकार के तरीकों से निकट लाता है जो मिलने की इस अनूठे अवसर के बिना संभव नहीं हो पाता।

कांग्रेस कनाडियाई समाजशास्त्रियों को भी दुनिया के साथ सम्बद्ध होने का अवसर प्रदान करती है। कनाडियाई समाजशास्त्र की अनेक गुणों में से एक सैद्धान्तिक और पद्धतिशास्त्रीय बहुलता के प्रति वास्तविक और सच्ची प्रतिबद्धता है। अन्य देशों के अपने प्रतिस्थानीयों की तरह कनाडियाई समाजशास्त्री निरंतर बदलने वाली और विविध आनुभाविक यथार्थ के लिए तैयार है। इस तरह, संघ के 1000 सदस्य व्यवहारिक समाजशास्त्र से लेकर सामाजिक सिद्धांत, संबंधपरक समाजशास्त्र या विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान का समाजशास्त्र तक फैले 28 से भी अधिक शोध समूहों के सदस्य हैं। सदस्यों एवं शोध समूहों द्वारा प्रदत्त कुछ सशक्त लेखों को कनाडियाई रिव्यू ऑफ सोशियोलोजी/रेव्यू कनाडियने दे सोशियोलोजी https://www.csa-scs.ca/canadian-review/, कनाडियाई समाजशास्त्र संघ की प्रमुख शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है।

शोध पत्रिका को पढ़ कर एवं आई एस ए बैठकों में लोगों से मिलकर आप देखेंगे कि कनाडियाई समाजशास्त्री भी सामाजिक न्याय के साथ गहनता से चिंति है और व्यवहारिक नीति संगत योगदान देते हैं और लोक समाजशास्त्री की भूमिका निभाते हैं। यह कहने के पश्चात, काफी कार्य बचता है। विश्व कांग्रेस दुनिया भर के समाजशास्त्रियों के लिए शक्ति, हिसा और न्याय के साथ अपने अनुभवों और प्रतिक्रिया में समानता और भिन्नता को खोजने का अवसर प्राप्त होगा। हम इस गर्मी आगमन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। ■

सीधा संपर्क करे : **रीमा विल्केस** <wilkesr@mail.ubc.ca>

> कनाडा में एकजुट होकर समाजशास्त्र के विकास के अवसर

पैट्रिजिया अल्बानीज, रीयर्सन विश्वविद्यालय कनाडा एवं समाजशास्त्र के XIX आई. एस. ए. विश्व सम्मेलन की स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष

1 जुलाई 2017 को कनाडा ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनायी। वर्ष भर कनाडा के लोग इस बात की खुशी मनाने के लिए उत्साहित थे कि वे कनाडा के निवासी थे और एक ऐसे देश में रह रहे थे, जो जी डी पी (GDP), साक्षरता दर, महिलाओं की श्रम शक्ति के रूप में सहभागिता, उत्तर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वली जनसंख्या का अनुपात इत्यादि की दृष्टि से एक अच्छे देश की श्रेणी में आता है। हालांकि यहां जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ हैं तो भी आलोचना करने के लिए भी यहां बहुत कुछ है।

> कनाडा का विरोधाभास

हमारे समग्र मापनों और वैश्विक स्थिति के प्रभावों को नकारने का कोई अर्थ नहीं है, बेशक आप हाल ही में कनाडा के आप्रवासी बने हो, कोई किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है, स्वदेशी है, एकल मां बच्चों का पालन–पोषण कर रही हैं, एक नस्लीय समूह के सदस्य हैं, कोई कनाडा के उत्तरी भाग में रह रहा है या एक परिवार के एक मुखिया को अनेक अंशकालिक नौकरियां प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ रही है ताकि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा उन्हें भोजन उपलब्ध करा सके। यदि ऐसा है तो इस बात की अधिक संभावना है कि भेदभाव, अनिश्चितता, निर्धनता और प्रतिरोध क्षमता आपकी जिन्दगी का हिस्सा हो।

ग्लोबल डायलॉग (वैश्विक संवाद) के इस अंक में कनेडियन समाजशास्त्र के उभरते विद्वानों में से 5 के लेखों को एक साथ लिया गया है, जिन्होंने कनाडा को एक विरोधाभास के रूप में चित्रित किया है। उदाहरण के लिए वू (Wu) लिखते हैं कि कनाडा 'अन्य' लोगों के लिए ''उच्च विश्वास'' का स्थान है तथापि मैकीवर (McIvor) महत्वपूर्ण असमानताओं तथा उच्च छात्र ऋण भार की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। माओलिनो (Maiolino) के अनुसार यह एक ऐसी जगह है जहां लोग एक युवा और नाममात्र के प्रगतिशील उम्मीदवार जस्टिन ट्रुडु (Justin Trudeau) को वोट देते हैं परंतु कनाडा के सर्वाधिक नस्लीय विविधता वाले शहरों में से एक टोरंटो में एक अल्पसंख्यक महिला मेयर उम्मीदवार–ओलिविया चाओ को निरंतर बातचीत करने और पहचान बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसके विपक्षी श्वेत पुरूष से भिन्न हो। हम सदैव अपने आपको अमेरिका से पृथक करने का प्रयास करते हैं परंतु लचापेले एवं बर्नेट (Lachapelle & Burnett) की टिप्पणी के अनुसार हम उन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते और काम करते हैं जहां अमेरिका की वैज्ञानिक पूंजी का शासन चलता है। वैले (Vallee) का कार्य हमें न केवल कनाडा की प्राकृतिक सुंदरता की बल्कि उसकी लुप्तप्राय प्रजातियों और तनावपूर्ण वातावरण की भी याद दिलाता है।

कनाडा एक शक्तिशाली देश है परंतु इसके अनेक निवासियों का जीवन असमानताओं के जाल में गहनता से फंसा हुआ है। हालांकि, इन कमियों को अनदेखा न करते हुए कनाडाई समाजशास्त्र ने अक्सर इन असमानताओं पर चर्चा करने का प्रयास किया है। कनाडा के पूर्व (रूढ़िवादी) प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भी इसकी अनदेखी नहीं की।

> >

> कनाडा में और उसके परे समाजशास्त्र का विकास

वर्ष 2013 में एक लोकल ट्रेन पर हुए आतंकवादी हमले को विफल करने के विषय में सवालों के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने घोषणा की कि 'यह समाजशास्त्र के विकास का समय नहीं है। इसी तरह 2017 के अंत में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने समाजशास्त्र के संपूर्ण विषय के साथ उत्पन्न विवाद को 'समाजशास्त्रियों का भव्य शब्दजाल' कहकर इस तर्क को खारिज कर दिया। ऐसा प्रहार करना कोई नई बात नहीं है क्योंकि जब भी हम अपने अनुसंधान, शिक्षण और सामाजिक क्रियाओं के द्वारा शक्ति, हिंसा और (अ) न्याय के मुद्दों पर बहस करते हैं तब हम समाजशास्त्री अक्सर सत्ता को चुनौती देते नजर आते हैं।

इसलिए, हार्पर के इस कथन 'अभी समाजशास्त्र के विकास के लिए समय नहीं है' के जवाब में हम सम्मानपूर्वक पृथक होने की मांग करते हैं। पृथ्वी को असहनीय कष्ट देने वाले सामाजिक–राजनीतिक पर्यावरण और पर्यावरणीय अनिश्चितताओं को देखते हुए अब उचित समय आ गया हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ (ISA) और कनाडाई समाजशास्त्रीय संघ (CSA) का मानना है कि हम वैश्विक पैमाने पर ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसलिए हम आपका और अन्य हजारों प्रतिभागियों का जुलाई 2018 में टोरंटो में आयोजित होने वाले समाजशास्त्र के XIX आई. एस. ए. विश्व सम्मेलन में स्वागत करते हैं।

आई. एस. ए. के प्रेरणादायी और अविश्वसनीय रूप से मेहनती अध्यक्ष डॉ. मार्गरेट अब्राहम ने समाजशास्त्र के XIX आई. एस. ए. विश्व सम्मेलन के लिए 'शक्ति, हिंसा एवं न्याय : विचार, प्रतिक्रिया एवं उत्तरदायित्व' विषय का चुनाव करते हुए विशेष रूप से इस अशांत या उथल–पुथल वाले समय में दुनिया भर के समाजशास्त्रियों को कार्यवाही और परिवर्तन लाने के लिए आमंत्रित किया है। यह आयोजन और इसका समयोचित विषय विश्व भर के कार्यकर्त्ताओं और विद्वानों के साथ नेटवर्क स्थापित करने और अनुसंधान, सिद्धांतों, नीतिगत अनुशंसाओं एवं सामाजिक गतिविधियों का आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।

> XIX आई.एस.ए. विश्व सम्मेलन में कनाडाई समाजशास्त्र

XIX आई एस ए विश्व सम्मेलन कनाडाई समाजशास्त्रियों को कैनेडियन छात्रवृत्ति और सहयोग के लिए सह–मेजबानी व प्रदर्शन करने का भी अवसर प्रदान करता है। विश्व सम्मेलन में सक्रिय रूप से सहभागिता करने वाले सैंकड़ों कनाडाई समाजशास्त्रियों के अतिरिक्त आई. एच. ए. ने सी. एस. ए. को विश्व सम्मेलन में कनाडाई विषयगत सत्रों पर कार्यक्रम करने के लिए प्रमुख चार सत्र उपलब्ध कराये हैं। ये सत्र संपूर्ण कनाडा से प्रस्तावों और प्रतिस्पर्धी समीक्षा प्रक्रिया के आह्वान का ही परिणाम है। उनका चयन उनकी समयबद्धता और प्रासंगिकता, उनके वक्ताओं की अखिल कनाडा तक पहुंच और उनके सामाजिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों के आधार पर किया गया था। वे 20 से अधिक प्रमुख और उभरते कनाडाई विद्वानों के लेखों अथवा कार्यों को प्रस्तुत करते हैं जिन पर हमें विश्वास है कि वे आई. एस. ए. विश्व सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को कनाडाई समाजशास्त्र का 'स्वाद' चखा सकेंगे। कृपया निम्नलिखित में से एक या अधिक कनाडाई विषय आधारित सत्र में हमारे साथ शामिल हों :

- क्या समाजशास्त्र हमें शरणार्थी बच्चों और युवाओं के पुनर्वास के बारे में सिखा सकता है?
- राज्य कैसे सामाजिक आंदोलनों को आकार देता है?
- अनिश्चितता के दौर में कनाडाई समाजशास्त्रः अतीत को प्रतिबिंबित कर रहा है/भविष्य का सामना कर रहा है
- कनाडा में स्वदेशी महिलाओं का लापता होना और हत्या : क्या समाजशास्त्र इसे स्पष्ट कर सकता है?

सी. एस. ए. के प्रशासक शेरी फॉक्स, ट्रेंट विश्वविद्यालय के डॉ. जिम कोनली, सेंट मेरी विश्वविद्यालय के डॉ. ईवी टेस्टसोगलु, रीयर्सन विश्वविद्यालय के पी एच डी शोधार्थी मार्गरेट बैंसर, मेमोरियल विश्वविद्यालय के डॉ. मार्क स्टोडडार्ट, लावाल विश्वविद्यालय के डॉ. साइमन लैंग्लाइस, लैथब्रिज विश्वविद्यालय के डॉ. सुसान मैकडेनली एवं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की डॉ. रिमा विल्केस तथा गेलफ विश्वविद्यालय की डॉ. मिर्ना डावसन से निर्मित अखिल कनाडाई स्थानीय आयोजन समिति का मानना है कि शक्ति, हिंसा, और अन्याय को उजागर करना महत्वपूर्ण है जो हमारे देश के संघर्षों और स्वदेशी लोगों के सामूहिक रूप से जुड़ाव में प्रकट होता है। हमने इस प्रभावी विषय को विश्व सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया जिसे कनाडाई कलाकार लिडियन प्रिंस ने तैयार किया है। विश्व सम्मेलन कनाडा के विद्वानों एवं कार्यकर्त्ताओं के योगदान को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है जो समाधान और बेहतर भविष्य की राह तैयार कर रहे हैं।

XIX आई.एस.ए. विश्व सम्मेलन विचारों को एक साथ साझा करने तथा शक्तिहीनता, हिंसा और अन्याय को प्रत्युत्तर देने का एक अवसर है जो समुदायों को सशक्त बनाता है, हिंसा को कम करता है और न्याय को प्रोत्साहित करता है। यह बहस करने, विचार मंथन करने, नेटवर्क बनाने आथ्र अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने की योजना बनाने का समय है। हम जो कुछ भी हैं और एक समाजशास्त्री के रूप में जो कुछ भी करते हैं, के लिए जश्न मनाने का समय है। हमारे साथ जुड़े। हम बेसब्री से जुलाई में टोरंटो में आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। ■

सीधा संपर्क करे : **पैट्रिजिया अल्बानीज** <palbanes@soc.ryerson.ca>

>स्थानीयता और वैश्विकता के मध्य
कनाडाई विश्वविद्यालय

फ्रैंकोइस लचापेले एवं **पैट्रिक जॉन बर्नेट,** ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा

पी एच डी विनिमय के नेटवर्क। अधिक जानकारी के लिए देखें http://www.relational-academia.ca/canada-network.html.
रिलेशनल अकेडिमिया द्वारा चित्र

हाल के वर्षों में वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में कनाडा के शीर्ष शोध विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रशंसा की गई, जबकि देश के शीर्ष विद्यालयों ने गर्व से सर्वाधिक योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए अपनी विश्व–व्यापी खोज की घोषणा की है। अमेरिका और ब्रिटेन में हाल की राजनीतिक अस्थिरता के बाद कनाडाई विश्वविद्यालय ट्रम्प और ब्रेक्सिट जैसे चालबाजों के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए तथा अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा एवं उत्कृष्टता की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

1960 के दशक के अंत में और आज के कनाडा में 'अच्छा' विश्वविद्यालय होने का क्या मतलब है, रिलेशनल अकादमिक प्रोजेक्ट (www.relational-academia.ca) इस बदलाव की जांच करता है। 1960 के दशक के अंत से 1990 के दशक के मध्य तक कनाडा में बढ़ते राष्ट्रवाद और कथित अमेरिकी वर्चस्व की अवधि एक ''अच्छा'' विश्वविद्यालय कनाडा के प्रशिक्षकों को नियुक्त करने और अपनी नागरिकता के आर्थिक, नैतिक और नागरिक लाभ के लिए कनाडाई विषयवस्तु को सिखाने के लिए प्रतिबद्ध था (अर्थात् कनाडाईकरण के आंदोलन हेतु)। इसके विपरीत पिछले दो दशकों में ''अच्छा'' विश्वविद्यालय के उद्देश्यों (मिशन) में बदलाव आया है। यह अब छात्रों, कर्मचारियों, संकाय और पूर्व छात्रों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ा रहा है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। इस बदलाव की प्रकृति को स्थानीयता से लेकर वैश्विकता तक दर्ज करने के लिए हमने 1977 से 2017 तक के कनाडा के शीर्ष 15 शोध–गहन विश्वविद्यालयों (यू 15 समूह) में काम करने वले 4934 समाज वैज्ञानिकों के अकादमिक प्रमाण पत्रों को एकत्र किया।

संकाय सदस्यों की डॉक्टरेट डिग्रियों की राष्ट्रीयता की जांच करते समय प्राप्त परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि पिछले 40 वर्षों में कम और मध्य स्तरीय अंग्रेजी बोलने वाले प्रभावी रूप से कनाडाई या गैर–अमेरिकी सदस्य–यू 15 स्कूलों के समाज विज्ञान संकायों में कनाडाई प्रशिक्षित नियुक्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हालांकि इसी दौरान टोरंटो विश्वविद्यालय, मैक्रि विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालयों में अमेरिका में प्रशिक्षित संकाय (70 प्रतिशत से अधिक) सदस्यों का व्यापक प्रभाव बना रहा। 1917 और 2017 के मध्य तीन अंग्रेजी भाषी राष्ट्र–कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन–सभी संकायों में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों की पी एच डी के लिए उत्तरदायी थे, दो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश अर्थात्–दक्षिण अफ्रीक (6 सीट) एवं भारत (4 सीट) द्वारा संचालित ग्लोबल दक्षिण स्कूलों का स्थान यू–15 स्कूलों में मात्र 19 पी एच डी (0.5 प्रतिशत से कम) तक सीमित था।

वैश्विक उत्तर की बदलती राजनीतिक अर्थव्यवस्था से परे जो शोध–गहन विश्वविद्यालय अंतराष्ट्रीय छात्रों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए उत्सुक है, क्या वास्तव में कनाडा के यू–15 स्कूलों में ''अंतराष्ट्रीय संकाय'' के बारे में सोचा जा सकता है? संकाय सदस्यों की पहली राष्ट्रीय मूल की डिग्री से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों में विद्वानों का अनुपात, जिन्होंने एंग्लो–अमरीकी देशों से बाहर स्नातक की डिग्री अर्जित की है, 9% से 18% तक दोगुना हो गया है। 2017 में इनमें से आधे 34 ग्लोबल दक्षिण देशों के संकाय सदस्य थे, जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. अर्जित की थी।

कनाडाई शिक्षा जगत के उच्च विभागों में अंतर्राष्ट्रीयकरण के दो अर्थ हो सकते हैं : या तो यह अमेरिकीकरण अथवा अमेरिका–निर्देशित अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारा शोध दुनिया भर में ज्ञान, छात्रों और विद्वानों के विषय परिसंचरण में अमेरिका की केंद्रीय स्थिति पर प्रकाश डालता है। लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण है कि यह कनाडाई स्कूलों का प्रभावशाली प्रभुत्व है जो समाजविज्ञान के वैश्विक क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व में योगदान देता है, जबकि उसी समय में यह एक प्रभावी राष्ट्रीय स्थिति के अधीन होता है जहां अमेरिकी वैज्ञानिक पूंजी का शासन होता है। ■

सीधा संपर्क करे :
फ्रैंकोइस लचापेले <f.lachapelle@alumni.ubc.ca>
पैट्रिक जॉन बर्नेट <pjb@sociologix.ca>

> नये कनाडाई स्नातक छात्रों पर

छात्र ऋण के प्रभाव

मिशेल मैकाइवर, टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा

क्विन डोम्ब्रोवस्की, 2017 द्वारा चित्र
https://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906.
सीसी एसए 2.0 द्वारा

कई देशों में, उत्तर–माध्यमिक शिक्षा श्रम बाजार समृद्धि का पर्याय बन चुकी है और उच्च शिक्षा वर्ग गतिशीलता में बड़े समकारी के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, उच्च शिक्षा समृद्धि के लिये हमेशा ही महत्वपूर्ण है फिर भी बढ़ती टयूशन दरों ने छात्र ऋण में घातीय वृद्धि की है। यह प्रवृत्ति दस्तावेजों में स्पष्ट है, परंतु शोधकर्ता यह निश्चित करने में पीछे रह गये हैं कि छात्र ऋण कैसे विश्वविद्यालयी स्नातकों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से, एक प्रश्न उत्तर की याचना करता है: किस तरह छात्र ऋण नये स्नातकों के श्रम बाजार में परिवर्तन को प्रभावित करता है? 2010 के विश्वविद्यालय स्नातकों से स्नातक के तीन साल बाद इकट्ठा किये गये राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि कनाडाई आंकड़ों का उपयोग करते हुये, यह प्रश्न, साथ ही क्या सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि छात्र ऋण के प्रभावों को कम करती है, मेरे शोध प्रबंध का केन्द्र–बिंदु है।

द्वितीय–पीढी के छात्रों की तुलना में प्रथम–पीढी के विश्वविद्यालय छात्र वित्तिय, सामाजिक, और सांस्कृतिक पूंजी के नुकसान में हैं। उनके पास स्नातक के बाद प्रासंगिक रोजगार पाने के लिये कम सामाजिक नेटवर्क, संपर्क, विश्वविद्यालय क्षेत्र में संचालन और रिस्यूम निर्माण का कम ज्ञान, और छात्र ऋण पर अधिक निर्भरता के ओर ले जाने वाली परिवार से कम वित्तिय सहायता हैं। इस प्रकार, यह जानना आश्चर्य की बात नहीं है कि छात्र ऋण द्वितीय–पीढी की तुलना में प्रथम–पीढी के विश्वविद्यालय स्नातकों के श्रम बाजार में परिवर्तन को अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। उन्नत प्रतिगमन तकनीकों का उपयोग करते हुये, मैंने पाया कि उच्च स्तर के छात्र ऋण प्रथम–पीढी के स्नातकों से जुडे हुये हैं, जो बताते हैं कि वे स्नातक के बाद, जो नौकरी वे चाहते थे, उसका इंतजार नहीं कर सके, कि उनकी वर्तमान नौकरी वह नहीं है जिसकी वे आशा करते थे, और उन्हें रोजगार पाने के लिये अन्य शहरों या देशों में जाना पडा। आगे, द्वितीय–पीढी के छात्रों की तुलना में, ऋणी प्रथम–पीढी के स्नातकों की अस्थायी रोजगार प्रस्थिति की एक उच्च संभाव्यता है, स्नातक के बाद उनके नियोक्ताओं की अधिक संख्या थी, नौकरी के लाभ कम थे, और स्नातक के दो और तीन वर्षों दोनों के बाद कम आय थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है, स्नातक के बाद रोजगार पाने की अधिक बेताबी और श्रम बाजार में अधिक पराधीनता के अनुभव को देखते हुये, मैंने यह भी पाया कि ऋणी प्रथम–पीढी के छात्रों ने नौकरी से कम संतुष्टि, कम जीवन संतुष्टि का विवरण दिया, और बिना ऋण के प्रथम–पीढी छात्रों और ऋण के साथ और बिना ऋण वाले द्वितीय–पीढी के छात्रों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से वे कम कह सके कि वे अपनी डिग्री फिर से करेंगे यदि वे समय में वापिस जा सके। ये निष्कर्ष एक बड़े समकारी के रूप में विश्वविद्यालय के आधुनिक मूल्यांकन में महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं।

ये निष्कर्ष बताते हैं कि जब छात्र ऋण उच्च शिक्षा की पहुंच प्रदान करने के लिये उपयोग किये जाते हैं, ये असमानता बढातें हैं और विश्वविद्यालय के समकारी प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। छात्र ऋण प्रथम–पीढी के विश्वविद्यालय स्नातकों में नौकरी की तलाश की बेताबी पैदा करते हैं और इस बेताबी का नतीजा नौकरी की अधिक अनिश्चितता होती है जो कि नौकरी की घटी हुयी गुणवत्ता और आय के ओर ले जाता है। ये निष्कर्ष कि ऋणी प्रथम–पीढ़ी के स्नातक वर्णन करते हैं कि वे उसी शिक्षा को नहीं लेंगें यदि वे समय में वापिस जा सकें, विशेष रूप से चिंतनीय है। संक्षेप में, यह शोध उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के साधनों के रूप में छात्र ऋण से दूर होने और अनुदानों और कम टयूशन के माध्यम से पहुंच प्रदान करने की सरकारी नीति का समर्थन करता है। ■

सीधा संपर्क करे : **मिशेल मैकाइवर** <mitchell.mcivor@mail.utoronto.ca>

> एक नागरिक वैज्ञानिक बनना

मिकी वाली, एथाबास्का विश्वविद्यालय, कनाडा

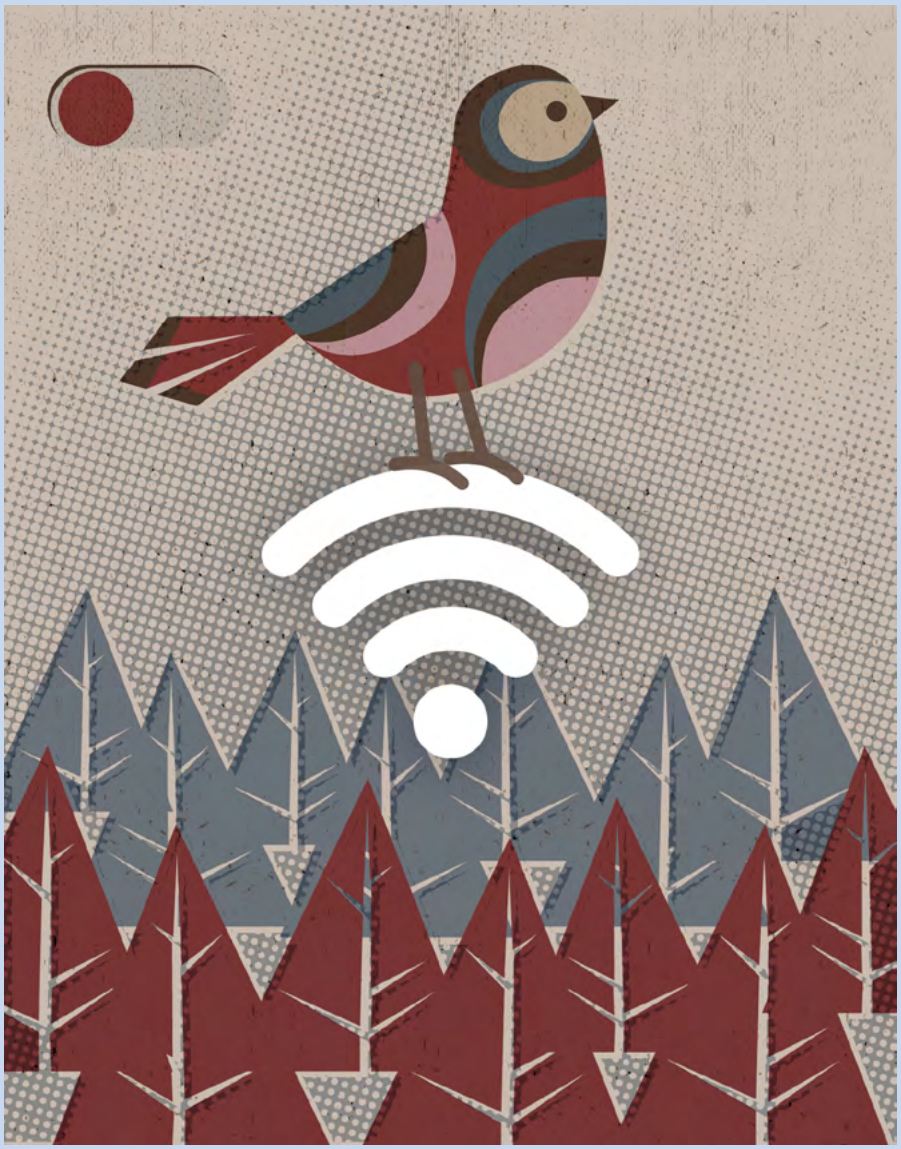

अर्बु द्वारा चित्रण

जब मैं लेखन कार्य में अटग जाता हूं, मैं पद यात्रा पर निकल जाता हूं। मैं कनाडा के एक दूरस्थ इलाके में रहता हूं जहां से नाले, नदियां, पहाड़ और वन्य जीवन पैदल की दूरी पर हैं। मैं इन पदयात्राओं पर पक्षियों को सुनना पसंद करता हूं। लाल पंखों वाली काली चिड़ियां, नैरजा, काग, कौअे और पीली गवैया वृक्षों से अपनी टेर और गीत सुनाते हैं जो दृश्यमान की तुलना में अधिक श्रवणीय हैं। इन गतिशील संगीत रचना को प्रग्रहण करने के इरादे से मैंने हाल ही में अपने आईफोन पर एक एप साँग स्लूयथ डाउनलोड किया है जो पक्षियों की टेर को स्वतः ही पहचान कर रिकार्ड करता है। यह वाइल्डलाइफ अकोस्टिक्स, जो बोस्टन मैसाचुसेट्स में स्थित है, द्वारा डिजाइन किया गया है। इस एप से मैं पक्षीयों को रिकार्ड कर सकता हूं, पहचान सकता हूं और इन रिकार्ड कर सकता हूं, पहचान सकता हूं और इन रिकार्ड की गई ध्वनियों (जी पी एस कोओरडिनेट सहित) को अन्य को ईमेल या संदेश द्वारा भेज सकता हूं। ऐसा करके मैं इन प्रस्तुत और उच्च प्रकार

> >

के निजी अनुभवों को जीव–श्रवण विज्ञान शोधकर्त्ताओं के वैश्विक नेटवर्क और मेरे जैसे शौकिया पक्षी–श्रोता से कनेक्ट करता हूं।

यह एप सरल जीव–श्रवण प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लेता हैं जो संरक्षणवादी हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली प्रजातियों के बारे में पूर्व चेतावनी देने का एक प्रभावी अभिज्ञान यंत्र है। पक्षियों की आवाजों को ट्रेक करने से वैश्विक शोधकर्ताओं को जोखिम वाली आबादी, प्रवसन पैटर्न और सहवास–चयन व्यवहार के बारे में ''बिग पिक्चर'' देखना आसान होता है। अतः सुनने, स्थिर रहने और अपने आसपास की ध्वनियों का ध्यान रखने का साधारण कृत्य का पेशेवर वैज्ञानिक शोध पर त्वरित और दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।

जीव–श्रवण में अकादमिक और पेशेवर शोध दल में कई वित्त पोषित शोधकर्त्ता है जो आंकड़ों को संग्रहित करते हैं और विश्लेषण करते हैं एवं अपने शोध निष्कर्षों को प्रसारित करते हैं। हालांकि मेरे जैसे नागरिक–वैज्ञानिक, जो अपने अवकाश के समय में रिकार्ड किये गये डाटा को अपलोड करते है, को वैश्विक पैमाने पर व्यापक होते शोध दलों में अब मुख्य खिलाड़ी के रूप में देख जा रहा है। वे शोध दल जो नागरिक–विज्ञान से काफी बड़ी मात्रा में डाटा को प्रयोग में लेते हैं, जैसे कारनेल विश्वविद्यालय का मैकाले पुस्तकालय, पुष्टि करते हैं कि आम जनता के योगदानों से शोध डाटा पहले से कहीं तेज दर से आता है।

अपने वैज्ञानिक योगदान के बावजूद, नागरिक वैज्ञानिक भी उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ का भी अनुभव करते हैं : वे बाहर पदयात्रा करते हैं और ऐसे जीवों को देखने, सुनने और रिकॉर्ड करने का विशेषा–धिकार का मजा लेते है जिनका अस्तित्व खतरे में हैं और जिनकी उपस्थिति दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। बच्चें, विशेष तौर पर, प्रकृति के साथ समृद्ध कनेक्शन का अनुभव करते हैं और व्यस्क अपने अवकाश के समय को शारीरिक रूप से सक्रिय रह कर बिताते हैं। नागरिक विज्ञान इस तरह गैर–निष्क्रिय जीवन शैली में योगदान देता है।

अच्छे स्वास्थ्य के अलावा, कुछ शोध कर्त्ता नागरिक विज्ञान की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए प्रशंसा करते हैं। अन्य शोधकर्ता बहस करते हैं कि जहां जागरूकता नागरिक विज्ञान का एक आदर्श परिणाम है, यह विरोधाभासी तरीके से इसे मापना एक चुनौती है। कई अध्ययनों ने हालांकि यह साबित किया है कि आनुभाविक अन्वेषण की ध्वनि आधारित पद्धति जैसे जीव–श्रवण स्पेस के अर्थपूर्ण जागरूकता से जुड़ी है। अतः जीव–श्रवण स्पेस के अर्थपूर्ण जागरूकता से जुड़ी है। अतः जीव–श्रवण शोध में नागरिक वैज्ञानिकों को शामिल करना वैश्विक और स्थानीय आबादी को ऐसी पद्धति में शामिल करना जो स्थानिक (और उसके विस्तार से पर्यावरणीय) जागरूकता में योगदान देती है, का व्यवहारिक और लागत प्रभावी उपाय है।

क्या हम अपनी यात्राओं में जैव विविधता के अंत में योगदान दे रहें हैं? क्या हमें इस बात का पता है कि हमारे स्मार्टफोन्स किसे समाविष्ट और साझा करने में सक्षम हैं? या, प्रकृति के जीवों के साथ हमारी फिसलते सम्बन्धों में क्या हम ऐसी जिम्मेदारी को संभालने के अनिच्छुक हैं? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समाजशास्त्रीय कल्पना का उपयोग करने की, जीवनी, इतिहास, सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी के प्रतिच्छेदन पर परिवर्तन लाने के अवसर ढूंढने की कई नई संभावनाओं में से एक है। ■

सीधा संपर्क करे : **मिकी वाली**
<mjvallee@gmail.com>

> कनाडा में अस्मिता केन्द्रित कार्य और राजनीतिक नेतृत्व

एलिस मैंओलिनो, टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा

पिछले पांच वर्षों का राजनीतिक माहौल कनाडाई राजनीति में अस्मिता (पहचान) की राजनीति और नई उम्मीदवारियों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त समय था। इस अवधि में कनाडा के तीन सबसे महत्वपूर्ण राजनेता देश के सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक पदों के लिए होने वाले चुनावी परिदृश्य में सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी सार्वजनिक अस्मिता स्थापित करने के लिए गंभीर वार्ता की आवश्यकता थी। जबकि किए गए अनेक बदलावों से समाजशास्त्री परिचित हैं परन्तु अस्मिता प्रदर्शन का पैमाना और क्षेत्र कनाडा और विदेशों में समाजशास्त्रियों के लिए नई अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है।

जस्टिन ट्रुडु ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। कनाडा की लिबरल पार्टी का नेता बनने से कुछ समय पहले जस्टिन ट्रुडु ने मुक्केबाजी के एक मैच में एक रूढ़िवादी सीनेटर से मुकाबला किया था। उनका पौरूष दाव पर लगा था। मैच पर प्रकाशित 222 अखबारों के लेखों के विश्लेषण के आधार पर मेरा शोध यह तर्क देता है कि जस्टिन ट्रुडु की वीरता/प्रसिद्धि अनिश्चितता से व्यापकता में बदल गयी जिसने उनकी कथित नेतृत्व क्षमता को काफी प्रभावित किया। ट्रुडु की यह घटना स्वास्थ्यवर्धक लैंगिक रणनीति की अवधारणा को उत्पन्न करती है और यह बताती है कि राजनीतिक नेता किस प्रकार अपनी सार्वजनिक लैंगिक अस्मिताओं को पुनर्स्थापित करते हैं।

ट्रुडु के साहस और पौरूष के प्रदर्शन के एक साल बाद कैथलीन बाइन ने ओंटेरियो के निवासियों से कहा कि क्या वे एक समलैंगिक प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं? उसने खुलेआम ओंटेरियो की पहली महिला और समलैंगिक प्रधानमंत्री बनकर एक इतिहास रच डाला। नारीवादी एवं एल जी बी टी क्यू (LGBTQ) समुदायों में सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक आंदोलन के आयोजनों के साथ हुए साक्षात्कार पर आधारित मेरे शोध से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक नेताओं की सफलता के लिए स्थानीय स्तर पर उनकी अस्मिता और भाषण के आधार पर उनकी स्वीकृति की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके बजाय, सामाजिक आंदोलन भी एक राजनीतिज्ञ की सुसंगत और मूर्त नीतिगत परिणाम देने की क्षमता पर अधिक बल देते हैं। मैं बहस करने के लिए ऐसे शब्दों और कार्यों को प्रस्तुत करने का तर्क देता हूं कि सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्त्ताओं का मूल्यांकन राजनीतिज्ञों के गठबंधन और संदेश के प्रति निष्ठा उनकी अस्मिता, भाषण एवं कार्यों पर निर्भर करता है।

इसी समय जब प्रधानमंत्री वायन अपनी अदृश्य बाधाओं को तोड़ रही थी, ओलिविया चाओ–जो एक अनुभवी प्रगतिशील राजनीतिज्ञ है, को कनाडा के सबसे बड़े प्रांत का नेतृत्व करने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बनने की राह में कुछ आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। संघीय राजनीति में अपना पद छोड़ने के बाद टोरंटो का मेयर बनने की दौड़ में शामिल होकर चाओ ने पूर्व मेयर रॉब फोर्ड के रूढ़िवादी एजेंडे को चुनौती दी तथा चुनाव अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बाधाओं, जबरदस्त नस्लवाद एवं लिंगभेद का सामना करना पड़ा। 20 मेयरों के साथ बहस में सहभागिता अवलोकन पर आधारित मेरा यह शोध अभियान के दौरान अस्मिता कार्य की चुनौती पर प्रकाश डालता है और यह तर्क देता है कि अल्पसंख्यक उम्मीदवार के रूप में चाओ को बातचीत करने और पहचान बनाने के ऐसे तरीकों की आवश्यकता थी जो उसके विपक्षी सफेद पुरूषों उम्मीदवारों से भिन्न थे।

अनेक उम्मीदवारों के मैदान में उतरने और विभिन्न अस्मिताओं की बढ़ती राजनीतिक और सार्वजनिक चेतना ने दिखावें/प्रदर्शन की अधिकता को उत्पन्न किया, जो शासन और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह शोध उच्च पदों को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को उजागर करेगा, परंतु बाधाओं को अवसर में बदलने की मांग करने वाले जमीनी कर्त्ताओं के लिए एक ब्लूप्रिंट (खाका) भी प्रदान करेगा। ■

सीधा संपर्क करे : **एलिस मैंओलिनो** <elise.maiolino@mail.utoronto.ca>

> उच्च भरोसे वाले कनाडा में

क्या अप्रवासी भरोसा जीत पाते हैं?

केरी वू, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, कनाडा

चित्र 1

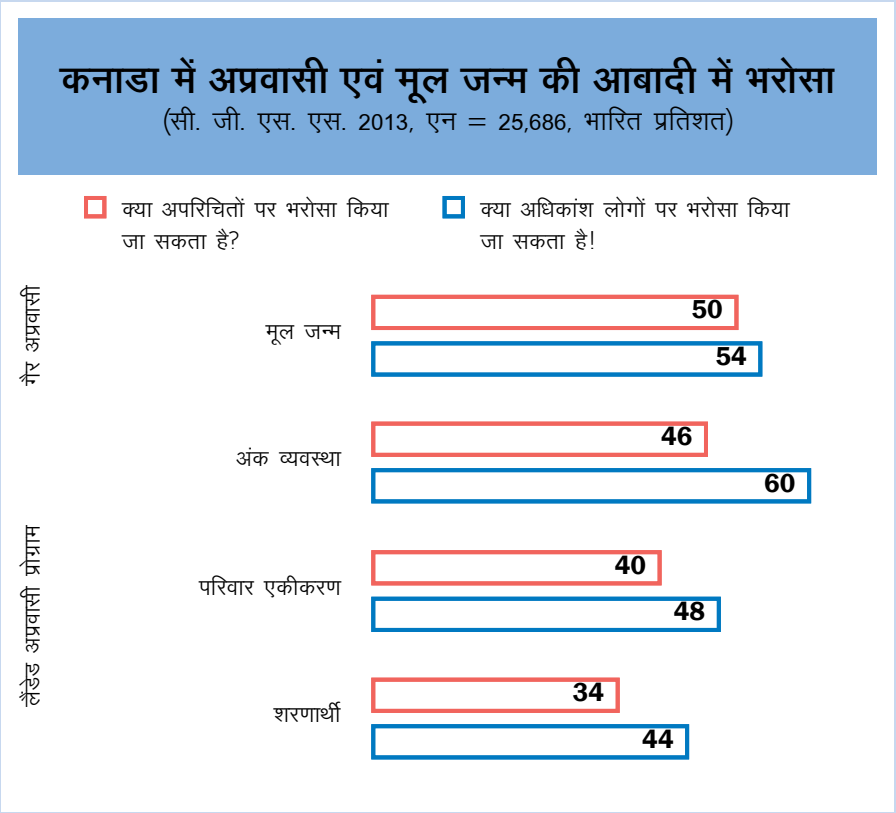

भरोसा सद्भावना और दूसरों से सौम्य आशय की व्यक्ति की अवधारणा को दर्शाता है। एक दूसरे पर भरोसा करने वाले लोग न सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए बल्कि सामाजिक एकता, आर्थिक वृद्धि और लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक हैं। भरोसा विशेष तौर पर अप्रवासियों और वृहद विदेशी मूल की आबादी वाले समाजों में, सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने वाली अपनी भूमिका के कारण महत्वपूर्ण है।

कनाडा अपेक्षाकृत रूप से उच्च भरोसे वाला देश है। स्टेटिस्टिक्स कनाडा के 2003, 2008 और 2013 के सामान्य सामाजिक सर्वेक्षण (जी एस एस) लगाता प्रदर्शित करते हैं कि आधे से अधिक कनाडियाइयों का मानना है कि "अधिकतर लोगों पर भरोसा किया जा सकता है।" इसके विपरीत जब यही प्रश्न वैश्विक स्तर पर पूछा जाता है केवल 37% को अन्य में इस प्रकार का विश्वास दिखाई देता है (विश्व मूल्य सर्वेक्षण 2010–2014)।

कनाडा अप्रवासियों वाला एक देश भी है। प्रत्येक पांच में से एक व्यक्ति या कनाडा की कुल आबादी का 21% विदेश में जन्मे व्यक्ति हैं। जहां कनाडा की पाइन्ट व्यवस्था ज्यादा भरोसे वाले अप्रवासियों के समूह को चुनने में मदद करती है, शरणार्थी और परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले लोगों में से कई लोगों में देशी की तुलना में कम भरोसा पाया जाता है। (देखें चित्र 1)

यदि अप्रवासी कम भरोसे के साथ शुरूआत करते हैं तो क्या वे कनाडा में, जहां लोगा अपेक्षाकृत अधिक भरोसेमंद है, रहने के बाद भरोसा जीत पाते हैं? जब भरोसें की उत्पत्ति की बात आती है तो वहां दो सैद्धान्तिक तर्क हैं : सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और अनुभवात्मक परिप्रेक्ष्य/सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विद्वानों का मानना है कि लोग प्रारंभिक जीवन में प्राथमिक सामाजीकरण द्वारा भरोसा सीखते हैं और यह सीखा हुआ भरोसा व्यस्कता और जीवन भर में बहुत कम बदलता है। अनुभवात्मक दृष्टिकोण से विद्वान तर्क देते हैं कि लोग

> >

चित्र 2 अ और 2 ब : बच्चों/किशोर अप्रवासियों एवं व्यस्क प्रवासियों के मध्य ट्रस्ट अंतर का पूर्वानुमान

(जी. एस. एस. 2014; भारित सांख्यिकी आंकड़े)

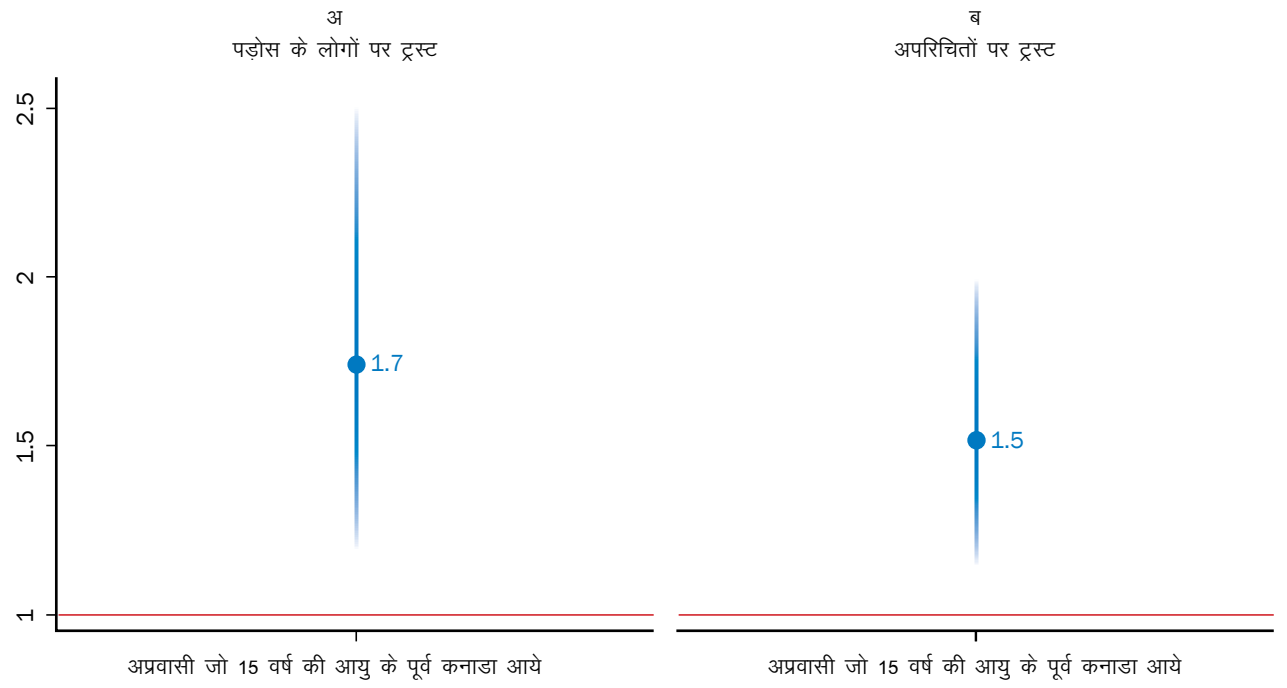

चित्र 2 अ, 2 ब

अपने सामाजिक अनुभवों के आधार पर भरोसे का निर्णय लेते हैं और इसलिए भिन्न सामाजिक परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में भरोसा परिवर्तित/बदल जाता है। इस बहस के केन्द्र में यह प्रश्न है कि लोग भरोसा कब सीखते हैं और क्या सीखा हुआ भरोसा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलता है।

तदनुसार, यह निर्धारित करना कि क्या कनाडा का उच्च विश्वास वाली संस्कृति का अप्रवासियों पर कोई प्रभाव होता है, उन अप्रवासियों के मध्य अंतर करना जो वयस्क के रूप में आये और जो बच्चे या किशोर अवस्था में आये और इसलिए अभी प्राथमिक सामाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आवश्यक है। यदि भरोसा सांस्कृतिक है, हम उम्मीद करेंगे कि जो अप्रवासी कम उम्र में आये और जिनका सामाजीकरण कनाडा की उच्च भरोसे वाली संस्कृति में हुआ, वे अधिक भरोसामंद होंगे जबकि केवल वे जो अधिक उम्र में आये और जिनका प्राथमिक सामाजीकरण कनाडा के बाहर हो चुका था, में अपने मूल देश की संस्कृति की छाप को दर्शाते हुए, कम भरोसा होगा। यदि भरोसा अनुभवात्मक है, तो अप्रवासियों से कनाडियाई अनुभव के प्रति समान रूप से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है, भले ही वे किस उम्र में यहां स्थाई रूप से रहने आये। अतः भरोसे में अंतर रहने की संभावना कम है।

स्टेटिस्टिक्स कनाडा के 2014 जी एस एस से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करने पर मैंने पया कि पन्द्रह वर्ष की उम्र से पहले आने वाले अप्रवासियों की जो पन्द्रह वर्ष की आयु या उसके बाद आये की तुलना में मुहल्ले के लोगों पर भरोसा करने के 70% अधिक संभावना, अपरिचितों पर भरोसा करने की 50% से अधिक संभावना है। इसमें अन्य जनसांख्यिकीय कारकों पर नियन्त्रण रखा गया है (देखें चित्र 2अ और 2ब)

इकट्ठे लेने पर, उल्लेखनीय अंतर दर्शाता है कि कनाडा की उच्च भरोसे वाली संस्कृति का सकारात्मक प्रभाव है लेकिन यह प्रभाव केवल उन बच्चों एवं किशोर अप्रवासियों तक सीमित है जो अपने प्राथमिक सामाजीकरण की अवधि के दौरान कनाडा आये। कुल परिणाम भरोसे के सांस्कृतिक सिद्धान्त के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करते हैं। ■

सीधा संपर्क करे : **केरी वू** <carywooruc@gmail.com>

> अंतरानुभागिता, देशजता, लैंगिकता एवं हिंसा

मैग्गी वाल्टर, तस्मानिया विश्वविद्यालय में एबोरिजनल रिसर्च एंड लीडरशिप के उपकुलपति,
जोसलिन बाल्ट्रा–उलोआ, तस्मानिया विश्वविद्यालय तथा **जेकब प्रेहन** आस्ट्रेलिया के तस्मानिया विश्वविद्यालय में एबोरिजनल रिसर्च एंड लीडरशिप के उपकुलपति।

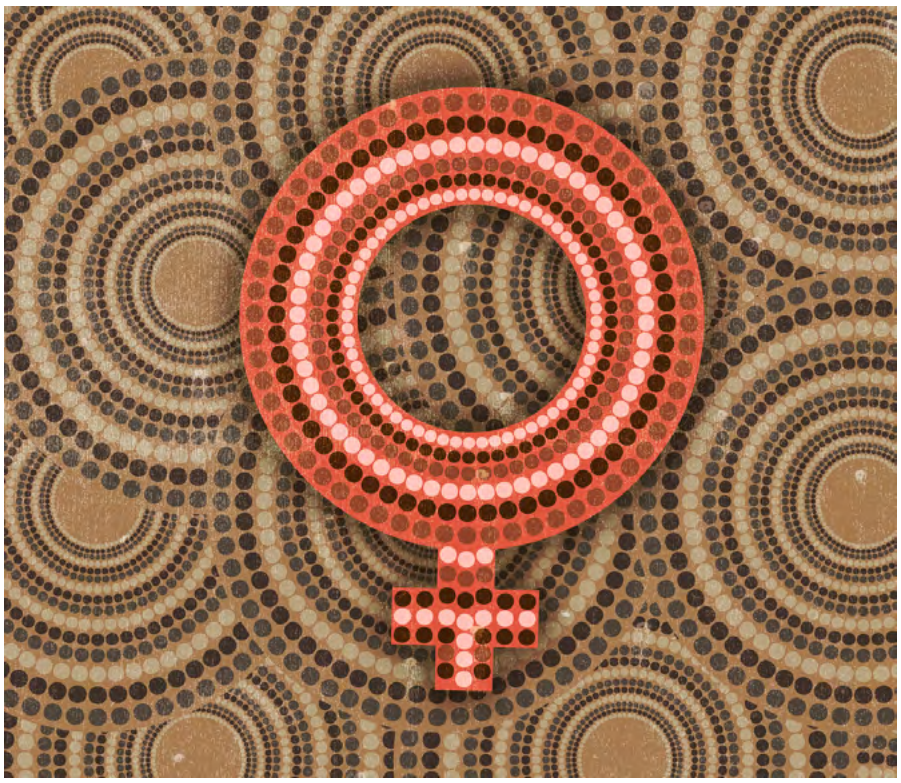

अर्बु द्वारा चित्रण

आॅस्ट्रेलियाई मूल निवासी/आदिवासी एवं टोरेस जलसंधि द्वीप की महिलाओं से जुड़े लैंगिक हिंसा के आंकड़े बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अपने गैर–देशज समकक्षों की तुलना में देशज महिलाओं एवं लड़कियों में पारिवारिक हिंसा संबंधी हमलों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 31 गुना अधिक है तथा आधे से अधिक आदिवासी महिलाओं की हत्याएं घरेलू हिंसा के कारण होती है। इस हिंसक जीवंत यथार्थ की गहराई की पुष्टि अध्ययनों से हो चुकी है जिनसे स्पष्ट होता है कि पिछले 12 महीनों से लगभग सभी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी महिलाओं को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। राज्य व क्षेत्रीय आंकड़े इस भयावह राष्ट्रीय घटना को दोहराते हैं। 95% आदिवासी बच्चे पारिवारिक हिंसा के कारण विक्टोरिया में रह रहे हैं जिन्हें घर से बाहर देखभाल के लिए रखा गया था, पश्चिमी आस्ट्रेलिया में आदिवासी महिलाएं गैर–देशज महिलाओं की तुलना में 17 गुना अधिक हत्याओं की शिकार होती हैं। हम यह तर्क दे सकते हैं कि इस हिंसा में अंतर्निहित देशजता और लैंगिकता आधारित विभाजन न ही तटस्थ, अ–ऐतिहासिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से अनिश्चित है और न ही नस्लीय दृष्टि से पृथक है।

लैंगिक हिंसा के आंकड़ों में अन्य एंग्लो–उपनिवेशित राष्ट्र–राज्यों की अपेक्षा देशज महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक है। एओटेयरोआ न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में गैर–देशज महिलाओं की तुलना में देशज महिलाओं के लैंगिक हिंसा के शिकार होने की संभावना अधिक है। यह साझा स्थिति दर्शाती है कि आदिवासी एवं टोरेस जलसंधि द्वीप, माओरी, अमेरिकी मूल और स्वयं प्रथम राष्ट्र के लोगों के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। ब्रिटिश अलग–अलग चार जातियों के साथ अलग–अलग चार भौगोलिक क्षेत्रों को उपनिवेश बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे इसलिए अन्य लोगों की तुलना में वे महिलाओं के प्रति स्वाभाविक रूप से अधिक हिंसक हो गए। न केवल आदिवासी और टोरेस जलसंधि द्वीप निवासी महिलाएं देशज पुरुषों के हाथों लैंगिक हिंसा का शिकार हैं, बाहरी भागीदारी की उच्च दर के साथ गैर–देशज अपराधियों का भी एक पर्याप्त अनुपात है।

> >

“कुल देशज महिलाओं की लगभग एक चौथाई महिलाएं पिछले बारह महीनों में शारीरिक या यौन हिंसा अनुभव करना रिपोर्ट करती हैं।”

बल्कि लैंगिक और प्रजातीय श्रेणियों के भीतर देशज महिलाओं की दोहरी स्थिति का संख्यात्मक दृष्टि से अति–प्रतिनिधित्व एक सामाजिक–सांस्कृतिक अवधारणा है। आंग्ल अधिवासी उपनिवेशवाद के द्वारा सीमित और परिभाषित शक्ति के लैंगिक संबंधों के साथ मिलकर देशज महिलाओं के प्रतिदिन के जीवन में दोहरी हिंसा उत्पन्न करते हैं।

आदिवासी एवं टोरेस जलसंधि द्वीप की महिलाएं उपनिवेशवादी हिंसा में हमेशा ही आगे रही हैं। निर्वासन के सीमांत युद्ध के दौरान नरसंहार के शिकार लोगों में महिलाएं ही प्रमुख थीं। अन्य महिलाओं जैसे तस्मानीयाई वेलेमर (आदिवासी विद्रोही महिला नेता) ने आक्रमणकारी शक्तियों के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रयासों का नेतृत्व किया। जैसे–जैसे औपनिवेशिक निर्वासन में वृद्धि हुई, महिलाओं की यौनिक हिंसा के साथ–साथ शारीरिक हिंसा में भी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, बास जलसंधि के फर्नोक्स द्वीप में 1800 के बाद से यूरोपियन जहाजों द्वारा महिलाओं का व्यवस्थित तरीके से अपहरण कर लिया जाता था तथा उन्हें रखैलों (उप स्त्री) व श्रमिकों के रूप में रखा जाता था, इसने तटीय जिलों के आदिवासी कबीलों में महिलाओं की प्रसव की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

एक बार जो आस्ट्रेलिया महाद्वीप पर औपनिवेशिक कब्जा हुआ तबसे लैंगिक हिंसा–यौनिक व शारीरिक हिंसा दोनों–समाप्त नहीं हुई, केवल उसका स्वरूप बदलता गया। अधिकांश 20वीं शताब्दी के दौरान देशज महिलाओं, जो अक्सर यौन–हिंसा का शिकार होती हैं, के हल्की चमड़ी वाले बच्चों को जबरदस्ती ले लिया जाता था और उन्हें राज्य की कठोर देखभाल में रखा जाता था। आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से छीन लेने की स्वीकृति देने वाली सरकारी नीतियों, जिन्हें ‘चोरी की पीढ़ियां’ नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य आदिवासी लोगों को श्वेत समाज में आत्मसात करना था। बच्चों को उनकी संस्कृति का अभ्यास करने, उनके परिवारों से संपर्क करने अथवा उनकी मूल भाषा बोलने की अनुमति नहीं थी। ऐसा अनुमान है कि 1910 से 1970 के बीच प्रत्येक 10 आदिवासी बच्चों में से 1 को ले लिया गया था। इन नीतियों के प्रभाव वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। पारिवारिक सदस्य छीनने के इतिहास वाले परिवारों की तुलना में अन्य देशज परिवारों में इस बात की अधिक संभावना है कि वे अपने बच्चों को राज्य की देखभाल में रख सकें। और पूरे देश में औपनिवेशिक हिंसा के परिणामस्वरूप अतः पीढ़ी निर्धनता तथा सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सीमांतीकरण की प्रक्रिया जारी है। परिणामस्वरूप परिवार की शिथिलता आदिवासी और टोरेस जलसंधि द्वीप की महिलाओं की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा के प्रति भय एक अंतरानुभागीय क्षेत्र के माध्यम से समाप्त होता है।

अतः आस्ट्रेलियाई समाज, विशेषतः आस्ट्रेलियाई समाजशास्त्र, आदिवासी एवं टोरेस जलसंधि द्वीप की महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा के प्रतिमानों का किस प्रकार जवाब देते हैं? दुर्भाग्यवश व्यापक रूप से तटस्थ बने रहे। जिस प्रकार आस्ट्रेलियाई समाज अब भी अपनी औपनिवेशिक, व्यापक रूप से, आंग्ल–विरासत को प्रस्तुत करते हैं वैसा ही आस्ट्रेलियाई समाजशास्त्र भी करता है। आस्ट्रेलियाई समाजशास्त्रीय साहित्य में ऐसा कोई नहीं है जो आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा को संबोधित करे, वास्तव में वहां बहुत कम देशज समाजशास्त्री उपस्थित है। ऐसा लगता है कि उपनिवेशवाद पर निर्भर प्रजातीय एवं लैंगिक शक्ति संबंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में उपनिवेशवाद के लाभार्थियों की कोई अधिक रूचि नहीं है। आस्ट्रेलियाई मूल के निवासी–अर्थात् आदिवासी एवं टोरेस जलसंधि द्वीप के लोगों की अप्रिय विरासत पर अब राष्ट्र राज्य का कब्जा हो गया था जिनसे उनकी समृद्धि और पहचान को आंका जाता था और जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावित हुई। संरचनात्मक स्तर पर, यह अतिसंवेदनशीलता लैंगिक शक्ति संबंधों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करती है, देशज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रतिक्रिया और अपमानजनक भाषा से भिन्न समझ उत्पन्न करती है। सामान्यतः एक अन्य देशज समस्या की तरह ही यह घटना आज भी व्यापक स्तर पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से उपेक्षित है। ■

सीधा संपर्क करे :
मैग्गी वाल्टर
<Margaret.Walter@utas.edu.au>
जोसलिन बाल्ट्रा–उलोआ
<Joselynn.BaltraUlloa@utas.edu.au>
जेकब प्रेहन
<jacob.prehn@utas.edu.au>

> दक्षिण अफ्रीका में यौन हिंसा एवं 'सुधारात्मक बलात्कार'

केमिला नायडू, जोहांसबर्ग विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका तथा आईएसए की शोध समितियों–वूमन इन सोसायटी (आरसी 32), बॉयोग्राफी एंड सोसायटी (आरसी 38) तथा क्लीनिकल सोशियोलॉजी (आरसी 46) के सदस्य

अर्बु द्वारा चित्रण

> ख्वेजी की कहानी को याद करते हुए

वर्ष 2005 में फेजेकिल नटसुकेला कुजवेओ (जिन्हें ख्वेजी उपनाम से जाना जाता था) नामक एक समलैंगिक महिला ने जैकब जूमा पर बलात्कार का आरोप लगाया जो बाद में रंगभेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका के तीसरे राष्ट्रपति बने। 2006 की बलात्कार की घटना की जांच ने जूमा के राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं को समाप्त करने के बजाय उनके लिए एक मंच तैयार किया जो जुलू की प्रथाओं और पारंपरिक पुरूषत्क के आवश्यक संस्करणों को लोकप्रिय बनाने में सक्षम थ। अपनी गवाही में उन्होंने दावा किया कि उनकी सांस्कृतिक समझ के अनुसार ख्वेजी की वेशभूषा/पहनावा सेक्स के लिए निमंत्रण था। ख्वेजी द्वारा पुरूष पर आरोप लगाने तथा न्याय प्राप्त करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप अदालती नाटक और गहन सार्वजनिक एवं मीडिया जांच में उसके यौन इतिहास, यौन अभिविन्यास, जीवन–शैली और हिंसा के पूर्व अनुभवों को केन्द्र में रखकर उसका तिरस्कार किया गया। अदालत के बाहर जूमा के समर्थकों ने समलैंगिक विरोधी, महिला विरोधी और नारीवाद विरोधी भावनाओं को फैलाया, जो ख्वेजी के समर्थकों, जिसमें वन–इन–नाइन (One-in-Nine) नामक महिला समूह सम्मिलित था, का विरोध कर रहे थे। ऋण सहायता देने के अलावा इस समूह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नौ में से एक दक्षिणी अफ्रीकी महिला अपने जीवन काल में बलात्कार का सामना करती है। अनेक लोगों के लिए न्यायिक मुकदमों के परिणाम काफी निराशाजनक थे, जूमा को बरी कर दिया गया था और ख्वेजी को देश छोड़ कर जाना पड़ा तथा असंख्य बार मौत की धमकियां मिलने के बाद उन्हें निर्वासित जीवन जीना पड़ा। वर्षों तक गुप्त और एकाकी जीवन जीने के बाद वर्ष 2016 में उनका निधन हो गया।

ख्वेजी की कहानी असंख्य समस्यात्मक वास्तविकताओं को उजागर करती है जिसमें वे कठिनाईयां जिनका बलात्कार पीड़िता को सामना करना पड़ता है जब अपराधियों (विशेषकर शक्तिशाली व राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों) को गिरफ्तार करने

>>

का प्रयास किया जाता है, समलैंगिकता के प्रति भय उत्पन्न करने वाली चर्चा/विचार समलैंगिकों के बलात्कार के प्रति दृष्टिकोण को आकार देती है तथा एक प्रगतिशील संविधान एवं 20 वर्षों से अधिक समय तक दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों और लैंगिक समानता का जश्न मनाने के बावजूद एक पुरूषवादी विषम संस्कृति का विस्तार–इत्यादि सम्मिलित है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा तथा बलात्कार के सभी अध्ययनों में अन्तरानुभागीय उपागम हमें विभिन्न पहचानों–उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में जाति, नृवंशीयता, यौन अभिवियांस, आयु, शरीर, वर्ग और राजनीतिक स्थिति इत्यादि के प्रभावों और विशेष संदर्भों में महिलाओं के अनेक नुकसानों के बारे में चेतावनी देते हैं। अतः यह विचचार आई एस ए (ISA) की अध्यक्ष मार्गरेट अब्राहम के द्वारा लैंगिकता और अन्तरानुभागीय हिंसा पर विश्व के कई हिस्सों से विभिन्न दृष्टिकोणों को निर्मित करने के प्रयास के संदर्भ में साझा किया गया है।

> हिंसा पुरूष मानसिकता

दक्षिण अफ्रीका में अपराधियों की गिरफ्तारी सामान्यतः नहीं होती और सजा की दर भी बहुत कम होती है, दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेव के वर्ष 2016 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार 2015–16 की अवधि में दक्षिण अफ्रीकी पुलिस थाने पर बलात्कार की 43000 घटनाएं दर्ज हुयी। हालांकि कुछ विश्लेषक का कहना है कि दर्ज मामलों में 13 दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं में से केवल 1 के साथ बलात्कार उसके साथी ने नहीं किया था और 25 में से 1 महिला के साथ उसके पति द्वारा बलात्कार किया गया था। जज/न्यायाधीश और जूमा के वकीलों द्वारा ख्वेजी के प्रति रूखे व्यवहार को देखते हुए बलात्कार पीड़ितों के लिए यह संदेश स्पष्ट हो गया था कि दुर्व्यवहार करने वालों के विरूद्ध आवाज उठाने का मतलब है कि जब आप अपराधिक मामला दर्ज करेंगे तो आपके व्यक्तिगत और सार्वजनिक इतिहास के सभी पहलुओं की छानबीन व पूछताछ की जायेगी। इस तरह राज्य की संस्थाएं एक प्रचलित मर्दवादी संस्कृति के ढांचे के भीतर गैर–रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने में सहयोग कर रही है। और मीडिया व सामाजिक चर्चाओं में बलात्कार के सामान्यीकरण को इसका समर्थन प्राप्त होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में पुरूषों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने एक समय पर बलात्कार के कृत्यों में सहभागिता की थी।

दक्षिण अफ्रीकी विद्वान/बुद्धिजीवी पुरूषत्व पर संकट की चिंता के रूप में हिंसक पुरूष मानसिकता की प्रबलता को समझाने का प्रयास करते हैं परंतु वे अपराधियों के रूप में मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के पुरूषों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टि से, बदलती राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं और ऐतिहासिक विरासतों के साथ–साथ परंपरागत पुरूषत्ववादी आदर्श और प्रतिमान लैंगिक समानता को बनाए रखने वाले संस्थानों के द्वारा बाधित हुए हैं जिन्होंने पुरूषों की प्रस्थिति को कमजोर किया है और (उनके लिए) लैंगिक पहचान के संकट को उत्पन्न किया है। सार्वजनिक और सामाजिक–आर्थिक सीमांतीकरण ने शक्तिहीन/प्रभावहीन पुरूषों की विभिन्न श्रेणियों में गिरोह का निर्माण, क्रूरता की छुटपुट घटनाएं और यथास्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर हिंसा का पुनर्मूल्यांकन करने में योगदान किया है। इस पृष्ठभूमि के विरूद्ध, महिलाओं के शरीर को यंत्र माना जाता है जिसके माध्यम से पुरूषत्व की शक्ति और नियंत्रण को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस तर्क को वर्तमान युग में नए सिरे से स्थापित किया गया क्योंकि समलैंगिकों (समलैंगिक पुरूष एवं समलैंगिक महिलाएं) ने समलैंगिक हिंसा को संबोधित करने के लिए संघर्ष किया है। विशेष रूप से ''सुधारात्मक बलात्कार'' (corrective rape) काफी कुख्यात हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न इस अनोखी अवधारणा से अभिप्राय समलैंगिक महिलाओं के साथ बलात्कार से है।

> 'सुधारात्मक बलात्कार'

वर्ष 2000 के बाद से लगभग 40 समलैंगिक महिलाओं की हत्या हो चुकी है और हर हफ्ते लगभग 10 समलैंगिक महिलाओं का उन पुरूषों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, जो यह मानते हैं कि वे महिलाओं के यौन–अभिमुखन को ''सुधार'' रहे हैं।

गुणात्मक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अपराधियों का दावा है कि बलात्कार समलैंगिक महिलाओं (उनकी समलैंगिकता की प्रवृत्ति) का ''इलाज'' करेगा और उन्हें विषम लैंगिक बनायेगा। इसके अतिरिक्त अध्ययन में कुछ पुरूष सहभागियों ने कहा कि बलात्कार उन पुरूषों की रक्षात्मक कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐसी महिलाओं पर हमला करते हैं ''जो पुरूषों की तरह बनने की कोशिश करती है'' और कहा कि पुरूषों की कार्यवाही उचित है क्योंकि वे ऐसा करके अपनी ''प्रामाणिकता'' (प्रासंगिकता) की रक्षा कर रहे हैं। पिछले दो दशकों से इस तरह के उभरते विचार समलैंगिक महिलाओं के साथ बलात्कार के प्रति सहिष्णुता का सुझाव देते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के अतीत के मुक्ति आंदोलन की भावना से मेल नहीं खाते, जिसमें महिलाओं की मुक्ति की मांग की गई थी। दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद की समाप्ति के बाद का संविधान यौन अभिमुखन के आधार पर भेदभाव को रोकने वाला दुनिया का सबसे पहला संविधान थ। दक्षिण अफ्रीका ही समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला भी पहला अफ्रीकी देश था। इस प्रकार राज्य के शक्तिशाली पुरूषों सहित कुछ अन्य लोगों के विचार इस बात का समर्थन करते हैं कि आज की महिलाएं गहन समलैंगिकता और नारीवाद विरोधी प्रतिक्रियाओं का सामना कर रही हैं जिससे यौनिकता एवं स्त्रीत्वता के नियम–कायदे भंग होते हैं और जो उनकी सत्ता को बनाए रखने की भावना को चुनौती देती हैं इसलिए उनमें सुधार की आवश्यकता है।

> निष्कर्ष

यह विडंबना है कि दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में बलात्कार एवं अन्य लिंग आधारित अपराध तथा हिंसा की घटनाएं हो रही है जहां लैंगिक सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पूर्णतः राज्य का सार्वजनिक एजेण्डा है। वास्तव में शक्तिशाली लोगों के समूहों ने हाल ही में वर्ष 2019 में एक महिला राष्ट्रपति की संभावना की घोषणा की है। हालांकि, यौन हिंसा को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जुटाने व संगठित करने के लिए ठोस/व्यवस्थित प्रयासों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए साहसिक कदमों की भी आवश्यकता होगी जैसा कि 4 महिलाओं ने उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति जूमा के भाषण का शांति के साथ व तख्तियों के साथ विरोध किया था जिस पर लिखा था 'ख्वेजी को याद करो।' इसके लिए अकादमिक संस्थानों, राज्य की संरचनाओं और नागरिक समाज के भीतर एक महत्वपूर्ण और मजबूत नारीवादी नेतृत्व के नवीनीकरण एवं पुनः उभार की आवश्यकता होगी। ■

सीधा संपर्क करे : **केमिला नायडू**
<kammilan@uj.ac.za>

> पोलैंड में घरेलू हिंसा की उपस्थिति

मैग्डलेना ग्रेजीब, जगियेलियन विश्वविद्यालय, पोलैंड

> पियास्की कांड

अप्रेल 2017 में जब सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस पार्टी के एक स्थानीय राजनीतिज्ञ/नेता की पत्नी ने यू ट्यूब पर एक रिकॉर्डिंग प्रकाशित की तो पॉलिश जनता नाराज हो गयी। रिकॉर्डिंग में घरेलू हिंसा की एक घटना दिखाई गई कि बाइटगोस्जकज के राजनेता राफल पियास्की (Rafal Piosecki) अपनी पत्नी करोलिना (Karolina) पर शादी के प्रारंभ से ही अत्याचार कर रहे थे। राफल और करोलिना किशोरावस्था के दौरान चर्च में मिले थे, दोनों ही कैथोलिक धर्म में विश्वास रखते थे। तस्वीरों में वे दो सुंदर बेटियों के साथ एक आदर्श युवा और खुशहाल पॉलिश परिवार नजर आते हैं। करोलिना पियास्की ने वर्ष 2013 में अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा करने की सूचना दी परंतु पुलिस अधिकारियों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, बाद में राफल द्वारा आश्वासन दिये जाने पर उसने अपने आरोप वापस ले लिए।

करोलिना पियास्की के समर्थन में आयी जनता ने दो तरह से अभूतपूर्व बदलाव किये। सबसे पहला, अपने प्रिय पति के हाथों से पीड़ित दुर्व्यवहार और यातनाओं पर उनकी गवाही ने न केवल पॉलिश समाज में घरेलू हिंसा और उसके प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर व्यापक प्रभाव डाला अपितु इस आम धारणा को भी चुनौती दी कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं होती हैं और न केवल वंचित सामाजिक समूहों के गरीब और विघटित परिवारों में ही होती है। दूसरा, इसने लॉ एंड जस्टिस पार्टी की अति–रूढ़िवादी दक्षिण पंथी राजनीति और उसकी स्पष्ट रूप से महिला–विरोधी राजनीति के असली चेहरे को सामने ला दिया।

> अतीत की ओर लौटना : पिछले दशक में महिलाओं के अधिकार

2015 में लॉ एंड जस्टिस पार्टी के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के मुद्दों पर एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई (ग्लोब डायलॉग 7.1 में जूलिया कुबिसा का लेख देखें)। 2012 में सत्ता में आने से पहले पार्टी ने घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने और उनका मुकाबला करने के सम्मेलन का यूरोपियन परिषद के अनुसमर्थन का जोरदार विरोध किया, यह ''लैंगिक विचारधारा'' के विरूद्ध पॉलिश कैथोलिक चर्च द्वारा शुरू किये गये अभियानों में शामिल हुआ जिसे पॉलिश परिवार, पारंपरिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए एक खतरा समझा गया था, मुख्य चिंता यह थी कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के संरचनात्मक कारणों पर इस्तंबूल सम्मेलन में हुई वार्ता पॉलिश संस्कृति के लिए हानिकारक होगी तथा अभिभावकों को अपने बच्चों को अपने मूल्यों के अनुरूप पालने–पोसने के अधिकार से वंचित करेगी और इसलिए हानिकारक लैंगिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने का दायित्व राज्य का है, जो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को उत्पन्न करते हैं। लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नेता पोलैंड में घरेलू हिंसा की गंभीरता से इंकार करते हैं और दावा करते हैं कि पॉलिश पुरूष महिलाओं के साथ महिलाओं जैसा ही व्यवहार करते हैं तथा पॉलिश कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव करता है। उनका तर्क है कि ऐसी हिंसा/दुर्व्यवहार शायद ही कभी होता है और केवल तब जब पुरूष शराब के प्रभाव में होते हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की आर्थिक सहायता में कटौती करते हुए आरोप लगाया कि केवल महिलाओं की मदद करने के कारण उनकी सेवाएं भेदभावपूर्ण हैं तथा फरवरी 2017 में वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रजज दुदा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि इस्तांबुल सम्मेलन सार्वजनिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

पोलैंड में कैथोलिक परंपर काफी मजबूत है और साम्यवाद के पतन के बाद से राजनीति में कैथोलिक चर्च एवं प्रभावी विचारधारा के रूप में विद्यमान रहा है। 1945–1989 के साम्यवादी युग में लैंगिक समानता के बावजूद, जब महिलाओं को श्रम, शिक्षा और प्रजनन संबंधी अधिकारों, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं–विशेष रूप से पारिवारिक संबंधों और अंतरंग संबधों में–पहुंच प्रदान की गई थी, पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति लगातार निम्न स्तर पर बनी रही। समानता की राजनीति की प्रतिक्रिया स्वरूप वर्ष 2012 में कैथोलिक चर्च के पुरोहितों ने ''लैंगिक विचारधारा'' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य वास्तव में पुरोहितों द्वारा किये गये बाल यौन शोषण घोटाले/कांड से जनता का ध्यान हटाना था और परिणामस्वरूप कैथोलिक चर्च को संस्थागत रूप से जवाबदेह बनाने की मांग की गई।

यह एक ऐसे राजनीतिक माहौल में हुआ था कि करोलिना पियास्की ने अपनी स्वयं की कहानी के साथ जनता के बीच जाने और समस्या के सार्वजनिक अस्वीकरण को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक बार जब रिकॉर्डिंग प्रकाशित हो गई तब राफल पियास्की ने अपनी पत्नी को मारने से इंकार कर दिया और कहा कि वह एक पारंपरिक परिवार में पले–बढ़े हैं, ईसाई मूल्यों का

> >

> “इस मामले ने बोलने के खिलाफ प्रबल सामाजिक वर्जना को तोड़ दिया।”

पालन करते हैं और परिवार में परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं में विश्वास करते हैं, अपने व्यवहार और अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार को उचित ठहराते हुए यह सुझाव देते हैं कि वह एक अच्छी पत्नी की परंपरागत लैंगिक भूमिका को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर रही थी।

> पोलैंड में पियास्की कांड का प्रभाव

पियास्की कांड पोलैंड में घरेलू हिंसा का पहला हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि पियास्की लॉ एंड जस्टिस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, जो पारिवारिक मूल्यों और अपने समलैंगिक बयानों की वकालत के लिए जाने जाते थे। मनोवैज्ञानिक हिंसा/दुर्व्यवहार की गंभीरता और पीड़ितों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में यह कांड एक महत्वपूर्ण कदम था। सामान्य तौर पर, सार्वजनिक संस्थानों और अदालतों दोनों ने हिंसा के एक स्वरूप के रूप में मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की उपेक्षा की। हालांकि पियास्की का व्यवहार चरम सीमा पर था, अनेक महिलाओं ने अपने परिवारों में भी ऐसे व्यवहार का अनुभव किया था और अनिवार्य रूप से, इसे असामान्य या अस्वीकार्य व्यवहार के रूप में नहीं देखा जाता था।

इस मामले को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया (स्वतंत्र मीडिया और सोशल दोनों मीडिया में) तथा घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं की विफलता के बारे में लोगों में रोष और बहस उत्पन्न हो गई। साथ ही इसने बोलने के विरूद्ध एक कठोर सामाजिक निषेध को भी तोड़ दिया करोलिना पियास्की ने स्पष्ट किया कि जनता के बीच जाने के उनके निर्णय में दूसरी महिलाओं की मदद करने की इच्छा छिपी थी जो दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं, उन्हें कोठरी से बाहर आने के लिए व अपमानजनक रिश्तों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और बताती है कि घरेलू हिंसा केवल निम्न वर्ग के परिवारों तक ही सीमित नहीं है।

> घरेलू हिंसा तथा लॉ एंड जस्टिस पार्टी : पृथक मामला नहीं है

हालांकि पियास्की कांड ने सत्तारूढ़ दल के भीतर कोई राजनीतिक तूफान पैदा नहीं किया था वास्तविक राजनीतिक प्रभाव उभरना अभी बाकी था। इस तथ्य के बावजूद पियास्की को लॉ एंड जस्टिस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और मई 2017 में उनके विरूद्ध आरोप लगाए गए थे, पार्टी के नेताओं ने समस्या को कम करने के प्रयास जारी रखे। लॉ एंड जस्टिस पार्टी के प्रवक्ता बीटा म्यूर्कक ने कहा कि परिवार के विरूद्ध हिंसा/अतिक्रमण करना अस्वीकार्य है क्योंकि हिंसा का कोई फायदा नहीं होता है। पार्टी के सहयोगियों ने हिंसा की निंदा की, लेकिन यह भी कहा कि एक पारिवारिक नाटक का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष के विरूद्ध किया जाता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि राफल पियास्की का मामला लॉ एंड जस्टिस पार्टी के किसी राजनेता का पहला और एकमात्र मामला नहीं था जिसने अपने पत्नी को प्रताड़ित किया था। वर्ष 2016 में एक सांसद लुकसजबोनिकोवस्की पर भी अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने का आरोप लगा था। हालांकि यह मामला जनता का ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया था। बाद में वर्ष 2017 में, एक अन्य सांसद वाल्डेमेरबोनकोव्स्की पर उनकी पत्नी ने हिंसा, धमकियों और तथाकथित भावनात्मक हिंसा के आरोप लगाए थे और वह कह रहा था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी। जब एक अति–रूढ़िवादी परंपरावादी और चर्च समर्थक राजनीतिक दल ने स्थिति की गंभीरता को दिखाया और बताया कि वास्तव में उसके विभागों में जो लोग अपने परिवारों के प्रति गंभीर रूप से हिंसा करते हैं वह नैतिक श्रेष्ठता और देश पर शासन करने की वैधता के दावों को खतरे में डालते हैं। यह रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी राजनीति की कुटिलता और उसका सच्चा चेहरा दिखाता है जो पितृसत्तात्मक शक्ति और पुरूषत्व के विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए ही काम करता है।

हालांकि वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा के विरोध में कानून अस्तित्व में है, घरेलू हिंसा को पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण पर प्रचलित वार्ता में स्पष्ट रूप से वैध माना जाता है। लॉ एंड जस्टिस पार्टी स्वयं घरेलू हिंसा को वैधता नहीं देती, लेकिन यह कानून व्यवस्था और अधिकारिक वार्ता के माध्यम से पारंपरिक पितृसत्तात्मक परिवार की संरचना और निजी क्षेत्र में महिलाओं पर प्रतिबंध के माध्यम से लागू होता है।

निर्विवाद रूप से करोलिना पियास्की मामले पर अधिक से अधिक सामाजिक जागरूकता को देखते हुए सत्तारूढ़ दल का घरेलू हिंसा की ओर रूख खुलेआम इसे महिला–विरोधी अन्य राजनीति (जैसे कि प्रजनन अधिकारों के संबंध में) के साथ जोड़ता है, भविष्य में पार्टी को और इससे भी अधिक इसकी पितृसत्तात्मक एवं संकीर्ण विचारधारा को अपमानित कर सकता है। यह मामला परिवार के ढांचे में निहित गड़बड़ी की पूछताछ और आलोचना के लिए समाजशास्त्रियों की आवश्यकता को दर्शाता है, जैसे कि वे आज निजी और सार्वजनिक संबंधों के बीच खड़े होते हैं। ■

सीधा संपर्क करे : **मैग्डलेना ग्रेजीब**
<magdalenaagrzyb@gmail.com>

> शून्य हिंसा की तरफ

स्लिविया वाल्बी, यूनेस्को चेयर ऑफ जेण्डर रिसर्च, लंकास्टर विश्वविद्यालय, यू.के., आई.एस.ए. की अर्थव्यवस्था और समाज की शोध समिति (आरसी 02) की बोर्ड सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष (2006–2010)

2014 में लंदन में मिलियन वुमन राइज रैली

सन् 2030 के यू. एन. सस्टेनेबल गोलस (SDGs) में टार्गेट 16.1 : ''सभी प्रकार की हिंसा और सम्बन्धित मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना'' और 5.2 : ''महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा का अंत।''

क्या ये लक्ष्य आदर्शवादी हैं? क्या दुनिया विपरीत दिशा में जा रही है? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक नागरिक समाज समूहों की बहुलता से दुनिया की एक दृष्टि है जिससे संयुक्त राष्ट्र के एस डी जी निकलते हैं। हिंसा से मुक्त दुनिया के इस विजन को अर्जित करने के ज्ञान के आधार को विकसित करना एक ऐसा कार्य है जिसमें समाजशास्त्र लगा हुआ है।

इस विजन की प्राप्ति के लिए परिवर्तन के सिद्धान्त के निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए समाज में हिंसा का सिद्धान्त और लिंग और समाज का सिद्धान्त की आवश्यकता है। इन सिद्धान्तों की जांच और परीक्षण के लिए हिंसा के माप और मजबूत अवधारणा की आवश्यकता है।

> हिंसा को क्या बढ़ाता और घटाता है?

क्या आर्थिक विकास से कोई फर्क पड़ता है? आर्थिक रूप से वंचित लोगों में हिंसा की दरें उच्चतर पाई जाती हैं। लैंगिक समानता में वृद्धि महिलाओं की हिंसा के प्रति लचीलेपन में सहायक होती है। लैंगिक समानता में कैसे सुधार लाया जा सकता है? आर्थिक विकास के द्वारा इसे प्राप्त या प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस बात पर निर्भर है कि आर्थिक विकास अधिक नवउदारवादी या अधिक सामाजिक लोकतांत्रिक रूप लेता है।

लक्षित हस्तक्षेप और सहायता सेवाओं से क्या फर्क आता है? नारीवादियों ने आश्रय स्थलों और हैल्पलाइन से लेकर विशेषज्ञ सलाहकार और अदालतों जैसे कई हस्तक्षेपों का नवाचार किया है। सेवाओं में वृद्धि हिंसा में कमी से जोड़ा जाता है चूंकि वे पीड़ितों और संभावित पीड़ितों की तन्यकता में वृद्धि करते हैं। लेकिन वे महँगे हैं और उनके संसाधन व्यापक लैंगिक असमानताओं के साथ जुड़े हुए हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली कितनी महत्वपूर्ण है? महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कानून में परिवर्तन दुनिया भर में फैल गये हैं। लेकिन अधिक कानूनों के परिणामस्वरूप महिलाओं ने आवश्यक रूप से अधिक न्याय को अनुभव किया है।

लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है? मेरे अपने कार्य वैश्वीकरण और असमानताओं में, मैंने पाया कि उन देशों में जहां संसद में महिलाओं की संख्या उच्चानुपात में है, वहां बालिका भ्रूण हत्या की दर कम होती है। लैंगिक लोकतंत्र की गहनता से फर्क पड़ता है : लैंगिक लोकतंत्र में वृद्धि महिलाओं के

> >

खिलाफ हिंसा में कमी से जुड़ा है। लैंगिक राजनैतिक समानता में परिवर्तन महत्वपूर्ण है न सिर्फ लैंगिक आर्थिक समानता।

वैश्विक उत्तर पर केन्द्रित हाल ही के वित्तीय और आर्थिक संकट ने लैंगिक आर्थिक असमानता में और मित्तव्ययता की राजनीति में वृद्धि की है जिसने सामान्य और विशेष कल्याण सेवाओं के प्रावधानों को घटाया है। संभावित तौर पर, यह काल इस थीसीस का परीक्षण है कि उच्चतर लैंगिक असमानता और मित्तव्ययता एवं सेवा प्रावधानों में कमी लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि करती है।

ऐसे सिद्धान्तों की जांच के लिए, यह जानना आवश्यक है कि क्या हिंसा बढ़ रही है या कम हो रही है और हिंसा की दर कैसे स्थान और सामाजिक समूहों में भिन्न होती है। इसके लिए हिंसा की दरों की लैंगिक आयामों सहित, मजबूत माप की आवश्यकता है जिसकी अत्यधिक कमी है।

> हिंसा को कैसे मापें?

माप महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, नागरिक समाज की गतिविधियों के बावजूद, आधिकारिक आंकड़ों में लगभग अदृश्य ही है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग और अपराध के आफिस द्वारा विकसित सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए अपराध का नया अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण हिंसा के शिकार के लिंग के आँकड़े संग्रहण को अनिवार्य नहीं बनाता है। इस प्रकार वह जेण्डर को द्वितीयक और वैकल्पिक लेबल के रूप में मानते हैं। इसके अलावा, लिंग आधारित हिंसा के अधिकांश पीड़ित अपने अनुभवों को पुलिस को नहीं बताते हैं। इस मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए अपराध सर्वेक्षण को विकसित किया गया है : हिंसा की पीड़ितों द्वारा पुलिस के बजाय सर्वेक्षण में अपने अनुभवों का खुलासा करने की संभावना अधिक है। ऐसे सर्वेक्षणों में जहां पीड़ित के लिंग के बारे में सूचना नियमित रूप से एकत्रित की जाती है, हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति की संख्या हमेशा दर्ज नहीं की जाती है, या यदि दर्ज किया जाता है तो हिंसा के आधिकारिक अनुमानों में हमेशा पूरी तरह से गिना नहीं जाता है।

ऐतिहासिक रूप से, अमरीकी और यू. के. सहित अधिकांश राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षणों ने राष्ट्रीय अनुमानों में सम्मिलित उनके यहां के दर्ज अपराधों की संख्या पर सीमा लगा दी। इससे आंकड़ों में लिंग पूर्वाग्रह पैदा होता है क्योंकि घरेलू हिंसा, जो असंगत रूप से महिलाओं के विरूद्ध होती है, एक पुनरावृत्ति वाला अपराध है। इंग्लैंड और वेल्स के अपराध सर्वेक्षण के कच्चे आंकड़ों की पुनः जांच करते हुए हमने (जूड टावर्स, ब्रियान फ्रांसिस और मैंने) पाया कि जब कैप को हटा दिया गया और सभी दर्ज अपराधों को अनुमानों में सम्मिलित किया गया, तो न केवल हिंसक अपराध की समग्र दर 60% अधिक थी बल्कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 70% वृद्धि हुई और घरेलू संबंधों द्वारा हिंसा भी 70% बढ़ गई।

इस नई पद्धति को काम में लेते हुए वाल्बी, टावर्स और फ्रांसिस ने पाया कि 2008 में प्रारम्भ आर्थिक संकट के बाद इंग्लैंड और वेल्स में हिंसक अपराध बढ़ गये। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई लेकिन पुरूषों के विरूद्ध हिंसा में नहीं। यह घरेलू हिंसा में वृद्धि के साथ जुडा हुआ था जो असंगत रूप से महिलाओं के खिलाफ है। पुरानी कार्यप्रणाली का उपयोग करते समय इन परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता है जो दोहराई जाने वाली हिंसा के महत्व को असंगत रूप से घटाता है। जब दोहराए जाने वाले हिंसक अपराधों (असंगत रूप से महिलाओं के विरूद्ध) को जाहिर किया जाता है, हिंसक अपराधों में वृद्धि पाई जाती है; जब पुरानी कार्यप्रणाली–जो एक ही पीड़ित के खिलाफ हुए पुनरावर्ती हिंसक अपराध को व्यवस्थित ढंग से कम गिनती है–को प्रयोग में लेते हैं तो कोई वृद्धि नहीं मिलती है। हिंसा में परिवर्तन को लैंगिक आयामों को सम्मिलित किये बिना समझा नहीं जा सकता है। यू. के. से प्राप्त ये निष्कर्ष उन सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं जो अर्थव्यवस्था के साथ हिंसा के साथ जोड़ते हैं वह जुड़ाव लैंगिक है।

समय, स्थान और सामाजिक समूह पर हिंसा की दर में भिन्नता की तुलना करने के लिए एक मजबूत माप ढांचें का विकास करने के लिए हिंसा और इसकी मापन श्रेणियों की सुसंगत परिभाषा के साथ साथ इन श्रेणियों को काम में लेने वाली सुसंगत डाटा संग्रहण पद्धतियों की आवश्यकता है। दो विषम उपागम पाये जाते हैं (जो एस डी जी 16 और 5 में चित्रित है), जिसमें से कोई सी भी हिंसा के लैंगिक आयाम पर व्यवस्थित रूप से डाटा एकत्रित नहीं करता है : एक हिंसा पर आंकड़े एकत्रित करता है लेकिन पीड़ित स्त्री है या पुरूष इस पर नहीं, न ही पीड़ित और अपराधी के मध्य संबंध पर, दूसरा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर ही आंकड़े एकत्रित करता है (महिलाएं और पुरूष नहीं)। लैंगिक आयाम (पीड़ित का लिंग, अपराधी का लिंग, अपराधी और पीड़ित के मध्य सम्बन्ध, हिंसा में क्या यौन तत्व है) को मुख्यधारा के डाटा संग्रह में सम्मिलित करने का समय आ गया है। एक दर्जन विद्वानों के साथ हमारे हालिया काम ने महिलाओं और पुरूषों के विरूद्ध हिंसा के लिए एक नये मापन फ्रेमवर्क की पेशकश की है जो इस विकास को समर्थन देगा और इस प्रकार मजबूत आंकड़ों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करेगा।

> संकट और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में वृद्धि

यू. के. में संकट वित्त से अर्थव्यवस्था से राजकोष से मित्तव्यत्तता तक गिर गया है और अब यह हिंसा में फैल रहा है। हिंसा में यह वृत्ति सामान्य नहीं है बल्कि विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध है और ज्ञात अपराधियों द्वारा हिंसक अपराधों की पुनरावृत्ति से जुड़ी हुई है। आर्थिक संकट लैंगिक है, उसका राजकोषीय प्रभाव लैंगिक है और हिंसा के परिणाम भी लैंगिक हैं।

नई विवेचनात्मक समाज विज्ञान सुरक्षा के अर्थ को चुनौती दे रहा है; सुरक्षा में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के मर्म में हिंसा को सम्मिलित करना और काफी हद तक इसे कैसे मापा जाए को दोहराना। यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समाज विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र है और किस तरीके से समाजशास्त्र सभी प्रकार की हिंसा को कम कर सतत विकास लक्ष्यों में योगदान दे सकता है। ■

सीधा संपर्क करे : **स्लिविया वाल्बी**
<s.walby@lancaster.ac.uk>

> मार्क्स के 200 वर्ष

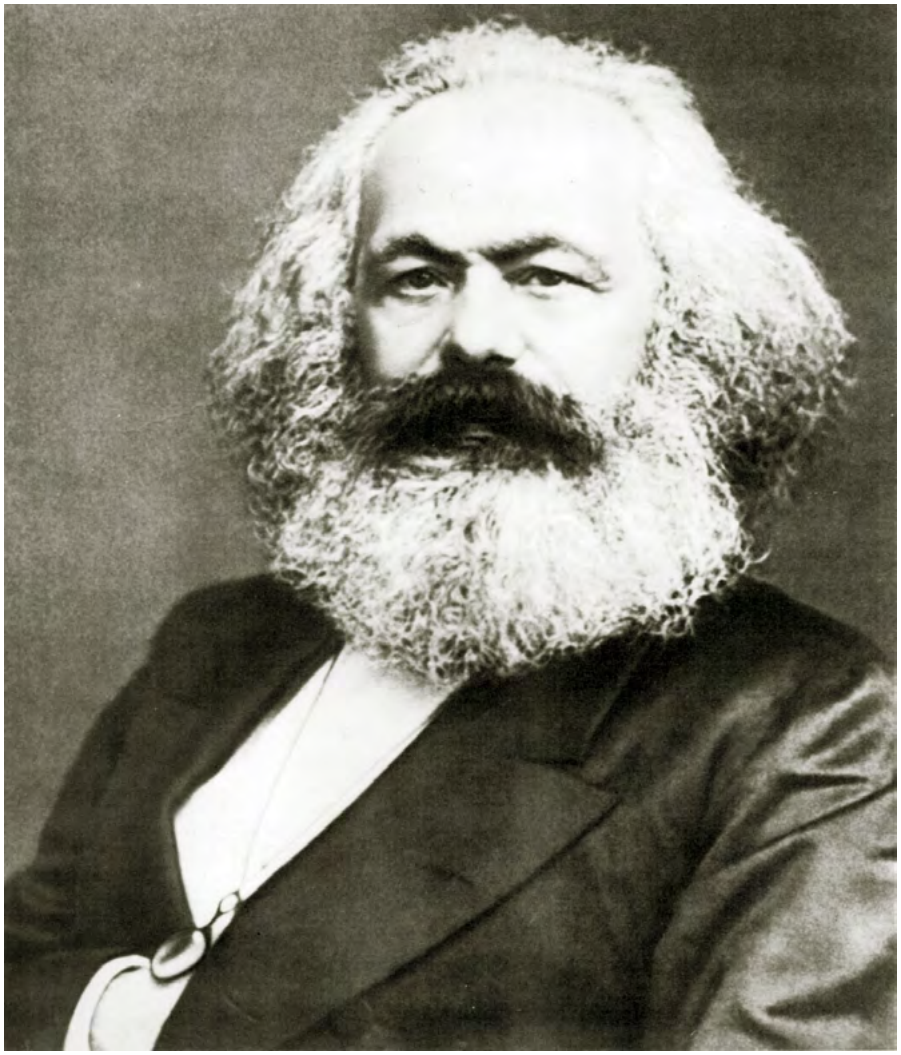

1875 में कार्ल मार्क्स। विकिमीडिया कामन्स/पब्लिक डोमेन

दुनिया के कुछ हिस्सों में 2008/9 के वित्तीय संकट ने मार्क्स एवं उनके साथी फ्रेडरिक एंगेल्स की कृतियों में पुनः दिलचस्पी को भड़काया। विशेष तौर पर द कैपीटल पूंजीवाद के संकट पूर्ण विकास एवं समकालीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उनके प्रभाव जैसे सामाजिक असमानताओं में वैश्विक वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, अनिश्चितता और गरीबी के साथ पारिस्थितिक आपदाओं को समझने एवं व्याख्या करने के लिए पूर्ण रूप से फिट प्रतीत होती है। लेकिन जहां इस तरह के अत्यावश्यक मुद्दे समाजशास्त्रियों के साथ मीडिया या समाज के व्यापक हिस्सों को पूंजीवाद के अपने विश्लेषण को पुनः खोजने का अवसर देते है, मार्क्सवादी सिद्धान्त विवादास्पद रहती है और दुनिया भर में मार्क्स पर शोध का समृद्ध पूंज उपलब्ध है। कार्ल मार्क्स के 200वां जन्मदिवस ने वैश्विक संवाद को दुनिया भर से सहयोगियों को इस परिसंवाद में मार्क्स, मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र, उनके पीछे परंपराओं और आज उनकी प्रासंगिकता पर चिंतन के लेखों को प्रकाशन हेतु देने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। परिसंवाद का प्रारम्भ मार्क्सवादी सिद्धान्त के साथ कैसे कार्य किया जाए या इनमें क्या नामौजूद है पर चिंतन और बहस से आगे बढ़ने से पहले इसकी दार्शनिक जड़ो को मुड़कर देखने से होता है। यह हमें, श्रम, राज्य, कानून, सामाजिक असमानताओं और अन्य मुद्दों के बारे में मार्क्स के लेंस के माध्यम से क्या देख सकते हैं, के बारे में बताता है। ■

> मार्क्स और समाजशास्त्र, 2018

जी. एम. तमास, मध्य यूरोपीय विश्वविद्यालय, हंगरी

करलोवी बारी, चेक गणराज्य में मार्क्स की मूर्ति

मेक्स वेबर ने अपनी जनरल इकोनोमिक हिस्ट्री (1919–20) में यह स्थापित किया कि रोजमर्रा की मानवीय जरूरतों को पूरा करने की एक विस्तृत व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद, पश्चिम के लिए विशिष्ट था, यह कि सभी बड़े उपक्रमों के मामले में आदर्श रूप से उसकी पूर्व शर्त पूंजी की तर्कसंगत गणना (परम्परागत रूप से दुहरी प्रविष्टि वाली बहीखाता पद्धति) थी और विशेष रूप से : 1. उत्पादन के सभी साधन स्वतन्त्र निजी उपक्रमों के बीच स्वतन्त्र प्रयोज्य सम्पत्ति के रूप में वितरित किये जाने चाहिए; 2. ''तर्कहीन'' सीमाओं जैसे कि जाति भेद के बिना मुक्त बाजार की आवश्यकता है; 3. यहां तर्कसंगत, यानि कि जो पूरी तरह से उत्पादन, व्यापार और यातायात के मामले में पूरी तरह से गण्य, मशीनीकृत प्रौद्योगिकी हो, की आवश्यकता है; 4. एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली होनी चाहिए जो पूर्वानुमेय और पारदर्शी हो; और 5. मुक्त श्रम उपलब्ध होना चाहिए यानि कि वे लोग जो अपनी श्रम–शक्ति को कानूनी तौर पर बेचने के बलात् हकदार है और वे आर्थिक कारणों के कारण बाजार में बेचने को मजबूर है।

मार्सेल मॉस (1901 में पॉल फाऊकोननेट के साथ विश्वकोश में लिखा गया एक लेख) ने इसी प्रकार स्थापित किया कि कोई भी नहीं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्तिगत कामगार या व्यापारी सामाजिक जीवन के स्वरूप जो उनके मस्तिष्क के बाहर है जैसे ऋण, ब्याज, मजदूरी, विनिमय या धन का आविष्कार नहीं कर सकता है। सामाजिक और आर्थिक जीवन के तत्व जैसे परिश्रम, किफायत, विलासिता या साहस कर्म का स्वाद कंगाली का डर और ''उद्यम की भावना'' भी निजी विविधताओं के बावजूद पूर्णरूप से व्यक्तिपरक नहीं है अपितु सामान्य रूप से वे ''सामाजिक संस्कृति'' के ''वस्तुपरक'' उत्पाद हैं जो कि पश्चिमी पूंजीवाद की सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है।

इन सब में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिससे समकालीन मार्क्सवादी (या, शायद मार्क्स स्वयं) असहमत होगा। यह इस तथ्य से भिन्न है कि समाजशास्त्र पर, मार्क्स के बाद में आने के कारण उनकी छाप है यद्यपि यह आंशिक रूप से उनकी विरासत के विरोध में निर्देशित है।

> आधुनिक समाज का ''बुर्जुआ या मार्क्सवादी विश्लेषण?

तो, ''बुर्जुआ समाजशास्त्र (आनुभाविक सामाजिक शोध से लेकर राजनैतिक दर्शन तक सामाजिक जांच की सभी शाखाएं) और आधुनिक समाज के विश्लेषण का मार्क्सवादी विश्लेषण के मध्य मूलभूत अंतर क्या है? इस दीर्घ झगड़े की व्याख्या क्या है, जो शायद ऐतिहासिक रूप से उतना महत्वपूर्ण है जितना ज्ञानोदय का तत्वमीमांसा और धर्मशास्त्र के साथ लड़ाई?

सरलीकृत रूप से : अरस्तू, ऑगस्तिनी एवं थॉमिस्त कॉस्मिक निष्पक्षता से ज्ञानोदय का स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के रूप में इच्छा की संप्रभुता का शुभारंभ करने वाली भौतिक व्यक्तिपरकता की तरफ झुकाव हो गया। जिसे फ्रांस में नैतिक और राजनीतिक विज्ञान कहा गया।

वह ग्रीक के समय से ''पश्चिम चिंतन'' (जिसमें बाइजेनटाइन, यहूदी और इस्लामिक सम्मिलित थे)पर हावी पुराने सिद्धान्तों के दिखावटी वृत्त खण्ड की कांत द्वारा की गई अंतिम आलोचना का परिणाम है।

स्पिनोजिस्ट और कांतवादी नैतिक दर्शन, उनके मध्य काफी मतभेद के बावजूद, मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी के रूप में पहचानता था। ऐसा वे उनके द्वारा चट्टानों और मछलियों और उनके दिमाग–जुनून और खुद के संरक्षण के प्रयासों द्वारा सीमित–नैतिक चयन के मामले में स्वतन्त्र लेकिन पूर्ण, वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और व्यापक ज्ञान और समझने में असमर्थ, बाधाएँ जो तार्किक और मनोवैज्ञानिक दोनों हैं के मध्य कारकीय निर्धारण के द्वारा करते हैं। यदि ईश्वर का ज्ञान, जिसे आवश्यक माना जाता है, व्यक्तिपरक है–धर्म सिद्धान्त इसे विश्वास कहते हैं–तो ''नैतिक विज्ञान'' अवश्य व्यक्तिपरक होंगे। पुनर्जागरण, उद्धार और ज्ञानोदय की समान अंतर्दृष्टि यह हो सकती है कि ज्ञान और आजादी दोनों के मान दण्डों की विवेक द्वारा व्यक्तिपरकता से जांच की जाती है, जो अंत में तर्क और गणित द्वारा आकारित होता है।

>>

निश्चित रूप से इसके पीछे छिपी धारणा थी कि इस तरह से सर्वे किया गया ''यथार्थ'' अंतर्ज्ञान के लिए उपलब्ध था जिसकी बाद में विवेक द्वारा पुनः जांच की गई और द्वन्द्वात्मक रूप से व्याख्या की गई अर्थात् इसके विरोधाभासों का प्रदर्शन करके।

हीगल की ऐतिहासिक भूमिका यह दिखाना थी कि ''आत्मा'' जिसे व्यक्तिपरक माना गया, वह वास्तव में वस्तुपरक थी। यह कि कांत द्वारा वर्णित मस्तिष्क निर्माण अवधारणाएं (बाहरी दुनिया से निगमन करने की बजाय) हमारी व्यक्तिपरक गुण नहीं थी जो ज्ञानमीमांसीय निरोधों से सीमित होती और काफी निर्णायक रूप से अज्ञानता के लिए निंदित होती लेकिन इसके विपरीत वे वास्तव में ज्ञान और आजादी के वास्तव स्त्रोत (तत्व या सबस्ट्रेट) थी।

मामले को और जटिल बनाते हुए हीगल आगे प्रस्तावित करते हैं कि वस्तुपरकता दो भेष में आती है : यथोचित ''वस्तुगत आत्मा'' – जिसे हम आज ''संस्थाएं'' कहते हैं – जिसे वे अपने युवा समय में दूसरे नाम सकारात्मक से बुलाते थे : ''झुठी वस्तुपरकता'' (सरल अर्थ में आजादी के बिना विवेक) और ''स्वछंद आत्मा'' (आजादी के रूप में विवेक : दर्शन)।

यह वह ''वस्तुपरक आत्मा'' है जिसे समाजशास्त्र के सच्चे संस्थापक इमाइल दुर्खीम ने ''समाज'' कहा, दूसरे शब्दों में, एक मानवीय दुनिया जो मानवीय इरादों, विकल्पों इच्छाओं इत्यादि, दोहराए जाने वाले या स्थाई परिणाम प्रदान करने वाली संरचनाओं की दुनिया से बिल्कुल अनजानी है। चूंकि सभी मानवीय आकांक्षाएं संस्थागत संरचनाओं को ढालने की बजाय प्रतिबिंबित और व्यक्त करती हैं। ये संरचनाएं–जिन्हें ''तथ्य'' कहा जाता है–बिना खिड़कियों की इकाई है, उनका परिवर्तन दैवाधीन है जो अप्रत्याशित संयोजनों या बाहरी घटनाओं के कारण है।

मार्क्स के हीगल के आगे निकलने और कांत पर वापिस जाने के कारण, अनुभवजन्य और अतींद्रिय के मध्य की द्विविधिता पुनः दिखाई देती है। जिसे एक ''तथ्य'', एक ''संरचना'' या एक ''वस्तु'' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह एक आभास है जिसके पीछे व्यक्तिपरकता छुपी हुई है सुविदित रूप से मूल्य (पूंजीवादी प्रक्रिया का मार्गदर्शक सिद्धान्त) के पीछे श्रम (मानव उत्पादक गतिविधि); यह श्रम ही है जिसे 'वस्तु' के बुत में जड़ दिया गया है। चीजें नहीं अपितु मानवीय व्यक्तिपरक गतिविधियां।

वह चीज, संस्थागत ''वस्तुपरक आत्मा'' एक मुखौटा है, इसलिए समाज का सम्पूर्ण संस्थागत तर्क (जिसमें अर्थव्यवस्था, राज्य और ''नागरिक समाज'' अब अलग नहीं है) भी एक मुखौटा है। लेकिन वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के दृष्टिकोण से, श्रम भी विभाजित है : मूर्त श्रम और अमूर्त श्रम एक जैसे नहीं हैं। जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से आता है वह हमेशा मृगतृष्णा है, जो कुछ भी आवश्यक है – जैसा तत्व होना चाहिए – वह संगुप्त है (पूंजीवाद में, झूठी उपस्थिति वस्तुनिष्ठता का लवाजमा ओढ़ती है)। इसे सिद्धान्त (विवेचनात्मक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, दर्शनशास्त्र, जो भी) के द्वारा ढँका जाना चाहिए (अवधारणात्मक रूप से नष्ट) ताकि व्यक्तिनिष्ठ मानवीय गतिविधि की सहजता को पुनः प्राप्त किया जा सके जहां जरूरतें मूल्य से अधिशासित नहीं होती हैं।

शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखने पर, मुख्य बात यह प्रतीत होती है : ''निरपेक्ष आत्मा'' किस प्रकार ''वास्तविक/वस्तुनिष्ठ आत्मा'' को चलाती है अर्थात् मूल्य जो करता है उसके फलस्वरूप किस प्रकार की सामाजिक संस्थाएं प्रकट होती है, या वर्ग के उद्भव, इतिहास और प्रकार्य क्या हैं? चूंकि समाजशास्त्र मानव समूहों को ''वस्तुओं'' (स्थायी या कम से कम टिकाऊ अमूर्ताएं) के रूप में मानता हैं, इसकी रूचि इसमें है कि मानव समूहों को कैसे आकार दिया जाता है और वितरण कैसे होता है, सम्पूर्ण समाज के बड़े परिदृश्य में उनका स्थान क्या है, और उनका राज्य, जो सुविचारित सामाजिक–राजनैतिक परिवर्तन का स्थान है, के साथ क्या सम्बन्ध है।

> मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य : वर्ग और शोषण

विशेष तौर पर मार्क्स जवाब नहीं देते हैं। प्रारंभिक कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र के विरोधाभास में वे और उनके पदचिन्हों पर चलने वाला, तथाकथित ''पश्चिमी मार्क्सवाद'' – यह नहीं सोचते कि पूंजीवाद के पहले और बाद में वर्ग हैं (वर्ग ऐतिहासिक है) वर्ग मूल्य और पूंजी का उपोत्पाद है : ''वर्ग संस्कृतियां'', ''वर्ग जीवन शैली'' और ''वर्ग संगठन'' इस उपोत्पाद के उपफल है।

मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण वर्ग सर्वहारा वर्ग है, जो सच्चे हीगेलियन के विधान में, एक ऐसे वर्ग के रूप में निर्मित होता है जो समाज (खुद का) का हिस्सा नहीं है। (एक भाग जो सम्पूर्ण का भाग नहीं है) यह उस वर्ग का खंडन है जो ''बुर्जुआ'' समाज विज्ञान (अर्थशास्त्र, राजनीति) द्वारा वर्णित समाज के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं, जो समान मानवता को साझा करने वाले लोगों के बीच अकी अंतक्रिय है, के बाहर है। लेकिन स्थूलीकरण इसकी अनुमति नहीं देता है।

यह सर्वहारा वर्ग की मुख्य गतिविधि है जो उन्हें वस्तु बनाती है, इसलिए यह वर्गों के बीच अंतक्रिया नहीं है अपितु पूंजी का एक गुण है। बुर्जुआ जानबूझ कर शोषण नहीं कर रहे हैं : अतिरिक्त मूल्य को पूंजी संग्रहण के गृहीत किया जाता है, न कि श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई भी राज्य शोषण का दमन या समाधान नहीं कर सकता है, इसलिए यह एक ''राजनैतिक समस्या'' नहीं है, जैसा कि सामाजिक डेमोक्रेट सोचने के लिए अभ्यस्त हैं। यह असमानता नहीं है।

असमानता एक समाजशास्त्रीय समस्या है लेकिन शोषण नहीं है। स्थूलीकरण, वस्तु जडासक्ति, असमानता में शोषण (अतः क्रमिक सुधार में सक्षम ''राजनीतिक समस्या'') का रूपांतरण, एक मार्क्सवादी के लिए बेतुका है। यही कारण है, आम तौर पर समाजशास्त्रीय प्रश्नों का मार्क्सवादी सिद्धान्त और इसके विपरीत क्रम में जवाब नहीं दिया जा सकता है। ■

सीधा संपर्क करे : **जी. एम. तमास** <gmtamas@gmail.com>

> बढ़ते हुये पूंजीवाद के लिये मार्क्सवादी परंपरा की निरंतर प्रासंगिकता

ऐरिक ओलिन राइट, विकोनसिन–मेडिसन विश्वविद्यालय, यू. एस. ए.

मार्क्स के जन्म के 200 वर्ष उपरान्त उनकी तरफ उत्तर के लिए देखना। मारको गोम्स द्वारा चित्र साओ पाउलो, ब्राजील

मार्क्स के कार्यों के साथ कोई भी विचार इतना गहरा संबंध नहीं रखता है जितना कि यह दावा कि पूंजीवाद की स्वाभाविक गतिकि अपने अन्दर गहन विरोधाभासों को समाहित रखती है जो अंततः उसको आत्म विनाश की ओर अग्रसर करते हैं और इससे ज्यादा यह है कि ये गतिकियां धीरे धीरे ऐसे परिस्थितियां बनाती है, जो समाज के एक ऐसे वैकल्पिक प्रकार को बनाने में सहायक होती है जो मानव प्रगति के लिये ज्यादा अनुकूल है। तर्क का पहला भाग पूंजीवाद के भाग्य के संबंध में महत्व पूर्ण भविष्यवाणी करता है : लम्बे समय में पूंजीवाद एक अरक्षणीय सामाजिक संगठन है एवं अवश्य ही इसका अन्त होगा। दूसरा भाग कम निर्णायक है–गतिकि जो पूंजीवाद को नष्ट करती है वो नवीन ऐतिहासिक संभावनाओं के द्वार खोलती है (विशेषतः उत्पादन ताकतों एवं मानव उत्पादकता में विकास के कारण)।

साथ ही यह एक सामूहिक एजेंट श्रमिक वर्ग का निर्माण करता है – जिसमें उन सम्भावनाओं का फायदा लेने की काबिलियत है, जो क्रांति के द्वारा एक बन्धनमुक्त विकल्प का निर्माण करेगी। यह काबलियत वास्तव में इस विकल्प को ला पायेगी या नहीं आकस्मिक प्रक्रिया की श्रंखला पर निर्भर करता है : क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार सुदृढ़ एकता का उद्भव, ऐसे राजनीतिक संगठन के विकास पर जो संघर्ष को संसक्त करे, आदि। पूर्णता में, यह सिद्धांत पूंजीवाद के निश्चित विनाश के संबंध में किये गये नियतात्मक दावों एवं पूंजीवद से परे भविष्य के संबंध में अनियतात्मक दावों के बीच परस्पर क्रिया को समाहित करता है।

नियतात्मक एवं अनियतात्मक दावों की इस द्विविधता, ने मार्क्स के सैद्धान्तिक विचारों को राजनीतिक आन्दोलन का आधार बनाया है। गैर–निर्धाराणात्मक तत्व उद्देश्यपूर्ण सामूहिक एजेंसी की आवश्यकता एवं बेहतर विश्व के निर्माण हेतु संघर्ष में व्यक्तियों की स्वैच्छिक भागीदारी को वैद्य मानते है। निर्धारात्मक तत्व सकारात्मकता के कारण प्रदान करते है : जब क्रांति के अवरोध भयभीत करते प्रतीत हो, पूंजीवाद विरोधी ताकतें मानती है ''इतिहास

> >

हमारे पक्ष में है'' और अंततः परिस्थितियां क्रांति के विस्फोट के लिये तैयार हो जायेंगी।

हम अब एक ऐसे संसार में रहते है, जो उससे काफी भिन्न है जिसमें मार्क्स ने अपने सैद्धान्तिक विचारों का निर्माण किया। मार्क्स की कुछ भविष्यवाणियां पूर्णतया सही रही हैं : पूंजीवाद एक वैश्विक व्यवस्था बन गया है, जो विश्व के दूर दराज के कोनों तक फैल गया है : उत्पादन की शक्तियां अविश्वसनीय तरीके से विकसित हुयी है; पूंजीवादी बाजार, जीवन के अधिकतर पहलुओं को गहराई तक प्रभावित करते है; भीष्ण आर्थिक विपदा पूंजीवादी समाजों का निरंतर कायम रहने वाला लक्षण है। परन्तु उनकी अन्य भविष्यवाणियां, जो बढ़ते हुये पूंजीवाद की महत्वकांक्षा के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अभी तक फली नहीं हैं : श्रमिक वर्ग धीरे–धीरे ज्यादा समरूप बनने की अपेक्षा, अधिक खण्डित एवं सभी तरह से विविधतापूर्ण हो गया है। यह उस एकता को अवरोधित करता है जो पूंजीवाद के विरोध में सामूहिक क्रिया के लिये आवश्यक है। पूंजीवाद अपने नवीन संचय वाले तरीकों के साथ विपदा का प्रत्युत्तर देने में ज्यादा सक्षम सिद्ध हुआ है। पूंजीवाद राज्य लोकप्रिय माँगों को आत्मसात करने में ज्यादा लचीला सिद्ध हुआ है, परन्तु जहां पर आवश्यकता पड़ी है वहां उसने दमन का भी प्रयोग किया है और अंततः उन प्रयासों का दुखद इतिहास, जो पूंजीवाद के विकल्प का निर्माण कर रहे थे। समाजवादी क्रांतियों के परिणामों ने उस सकारात्मकता को खोखला कर दिया जो यह मानती है कि विपदा एक न्यायपूर्ण एवं मानवतावादी विकल्प के निर्माण हेतु क्रांतिकारी राजनीतिक शक्तियों के अवसर प्रदान करती है।

21वीं शताब्दी में, यह अब संभव नहीं है, कि ''पूंजीवाद के गतिकी के नियम'' को हम आवश्यक रूप से पूंजीवाद के नष्ट होने की प्रक्रिया के रूप में देखें साथ ही उससे बन्धनमुक्त विकल्प के निर्माण की अनुकूल परिस्थितियों को भी बनाते जाये। इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि मार्क्सवाद ने अपना औचित्य खो दिया है। विशेषतः मार्क्सवाद के चार महत्वपूर्ण प्राक्कथन समकालीन समाज को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिये एवं एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिये हमेशा आवश्यक रहेंगे :

1. पूंजीवाद मानव की समृद्धि की संपूर्ण परिस्थितियों को सदैव अवरोधित करेगा। इसका सबसे सटीक लक्षण है प्रचुरता के मध्य व्याप्त सतत् निर्धनता। परन्तु पूंजीवाद के नुकसान भौतिक क्षय से भी परे जाकर उन मूल्यों तक जाते हैं जो मानव समृद्धि के लिये आवश्यक है : समानता, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समुदाय। पूंजीवाद की इन हानियों का स्त्रोत आखिरकार वर्ग संरचना है। पूंजीवाद के वर्ग संबंध विभिन्न तीरकों से नुकसान करते है : शोषण, प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति का राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा के विनाशकारी रूप एवं बाजारों का इस प्रकार से विस्तार जो समुदाय एवं परस्पर क्रिया को खोखला करता है। मार्क्सवादी परम्परा पर चल रहे अनुसन्धान ने इन हानियों को प्रलेखित किया है।

2. पूंजीवाद की गतिकी तात्विक रूप से विरोधाभास है। पूंजीवाद वह स्थायी साम्य नहीं प्राप्त कर सकती है जिसमें सभी तत्व प्रकार्यात्मक रूप से एक समग्र के रूप में जुड़ पाये। अगर पूंजीवाद में ऐसी कोई मूलभूत प्रवृत्ति नहीं भी है, जो पूंजीवाद को अरक्षणीय बनाने के लिये पूंजीवादी विरोधाभासों की तीव्रता को बढ़ाये, तब भी वो सतत् रूप से नवीन अवसर एवं परिवर्तन हेतु संघर्ष के द्वार सदैव देती है।

3. दूसरा विश्व संभव है। मार्क्सवाद का सबसे मौलिक विचार यह है कि पूंजीवाद का बन्धनमुक्त विकल्प संभव है एवं उसका रूप है एक ऐसी अर्थ व्यवस्था जिसमें पूंजीवादी वर्ग का निवेश और उत्पादन पर नियंत्रण उग्र आर्थिक प्रजातंत्र से विस्थापित कर दिया गया हो। इसने मार्क्सवाद को पूंजीवाद के एक आलोचक मात्र से बन्धनमुक्त समाजविज्ञान में परिवर्तित कर दिया। यह कहना कि एक बन्धनमुक्त विकल्प संभव है, इसको कहने से ज्यादा प्रभावी है, कि महज एक विकल्प कल्पनीय है। विकल्प वांछनीय, व्यवहारिक प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। इस प्रकार मार्क्सवादी दावा करते हैं कि उग्र आर्थिक प्रजातंत्र पूंजीवाद से बेहतर बंधनमुक्त मूल्य ला सकता है। अगर यह संस्थागत होगा तो यह वहनीय होगा एवं कई मुमकिन ऐतिहासिक परिस्थितियां है जिसमें इसको प्राप्त करना संभव है।

4. परिवर्तन के लिये केवल प्रतिरोध नहीं बल्कि निर्माण का वर्ग संघर्ष चाहिए। पूंजीवाद का आर्थिक प्रजातंत्र में परिवर्तित करने के लिये सामूहिक क्रिया एवं जागृति की आवश्यकता है जो कि जमीनी स्तर से हो। अभिजात वर्ग महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है परन्तु सामाजिक परिवर्तन महज बौद्धिक अभिजात वर्ग के बीजारोपण से नहीं आयेगा। बन्धनमुक्त परिवर्तन, को लाने के लिये सिर्फ पूंजीवाद की हानियों का विरोध करना ही आवश्यक नहीं है, इसके लिये आवश्यकता है ऐसी संस्थाओं के निर्माण की जो इन मुक्त आदर्शों को समाहित करते हों। मार्क्स के मौलिक सिद्धान्त में, निर्माण में परिवर्तन सिर्फ पूंजीवाद के विनाश से ही संभव बताया गया है जो क्रांति द्वारा लाया जा सकता है। श्रमिक वर्ग एक बार सत्ता में आ गया तो नवीन समाज का निर्माण कर लेगा। 21वीं शताब्दी में, अब यह विचार संभावित रणनीति नहीं है। अगर पूंजीवाद के उपरान्त, उग्र आर्थिक प्रजातंत्र भविष्य है, तो उन समाजों के भीतर से निर्माण कार्य शुरू होना चाहिये जो अभी भी पूंजीवाद के प्रभुत्व में हैं।

यह चार प्राक्कथन 21वीं शताब्दी में बन्धनमुक्त समाजविज्ञान की मार्क्सवादी परम्परा के विकास की नींव रखते हैं। ■

सीधा संपर्क करे : **ऐरिक ओलिन राइट** <wright@ssc.wisc.edu>

> नारीवाद मार्क्सवाद का सामना करता है

एलेक्सजेंड्रा शीले, बीलेफेल्ड विश्वविद्यालय, जर्मनी एवं **स्टीफेनी वोहल,** व्यावहारिक विश्वविद्यालय बी एफ आई वियना, ऑस्ट्रिया

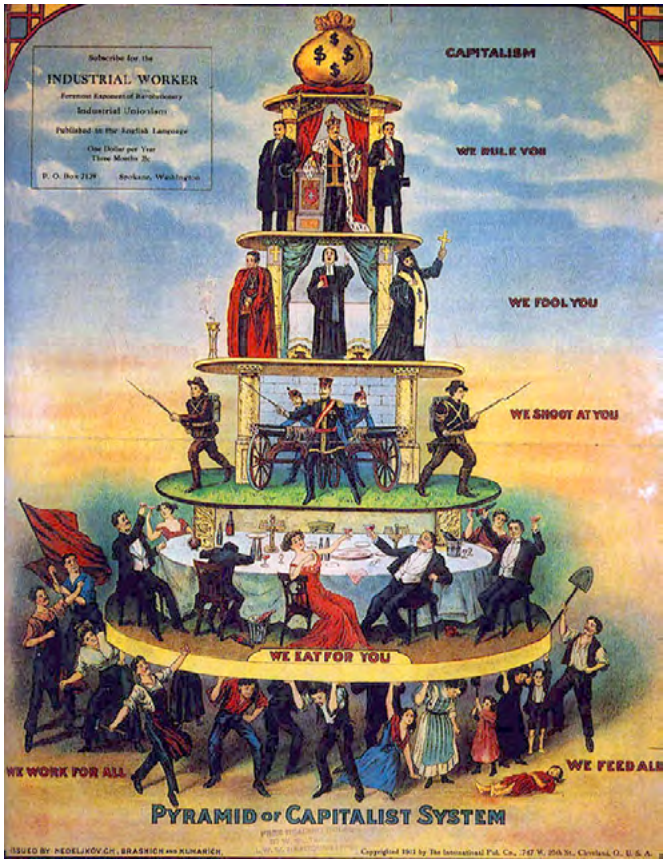

पूंजीवादी व्यवस्था का पिरामिड़

काफी वर्षों से, जर्मनी में एवं अन्य स्थानों पर मीडिया ''मार्क्स के नवजागरण'' के संबंध में बात कर रहा है। इसका अर्थ है कि कार्ल मार्क्स के कार्य साम्यवाद एवं वित्तिय विपदा का विश्लेषण करने में शायद सक्षम रहे है। यह कदाचित इस तथ्य द्वारा समझाया जाता है कि 2008 के वित्तिय एवं आर्थिक विपदा ने दिखा दिया कि साम्यवाद की वैश्विक जीत, सामाजिक उथल पुथल, पर्यावरण विपदाओं एवं अर्थव्यवस्था के स्व विनाश की प्रवृत्ति से जुड़ी है। इस पृष्ठभूमि में मार्क्स का विश्लेषण अब पुनः सार्थक प्रतीत होता है।

> मार्क्स नवजागरण में लुप्त होता नारीवाद अन्तराल

हालांकि मार्क्स एवं उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आलोचना में बढ़ती हुयी नवीन जन रूचि मार्क्स के नारीवादी अभिनंदन से कम या बिल्कुल ही संबंध नहीं रखती है। यह नारीवादी विश्लेषण कभी भी वास्तव में मार्क्स से संबंधित वामपंथी चचौओं का भाग नहीं रहे हैं क्योंकि यह वाद विवाद के किसी भी पक्ष में स्थित नहीं है। एक तरफ, नारीवादी मार्क्स समर्थक एक ऐसे आलोचनात्मक उपागम का विकास करना चाहते थे जो सामाजिक प्रश्नों को समझ सके एवं लैंगिक मुद्दों से उसे अलग न करे; एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो संसाधनों का पूंजीवादी शोषण एवं उससे सम्बन्धित वैश्विक स्तर पर संबंधित जीविकाओं के विनाश का विश्लेषण करे; एवं एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो न केवल शक्ति एवं प्रभुत्व की प्रक्रिया को संचयी शासनों के रूप में विश्लेषित करे, अपितु उनकी पितृसत्तात्मक नींव को भी पहचानें। दूसरी तरफ, नारीवाद–मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य उस मार्क्स के पूर्व एवं वर्तमान अभिनंदन की विवेचना करते है जो असमानता एवं शोषण की सभी परिस्थितियों को बदलने का लक्ष्य रखता था, परन्तु शायद ही कभी यह मानते थे कि लैंगिक संबंध इन परिस्थितियों के भाग थे। इसके उपरान्त, उत्पादन एवं पुनर्उत्पादन में विभाजन, एवं श्रम का लैंगिक विभाजन, जिसका मार्क्स ने कम से कम जिक्र तो किया था, मुश्किल से पुनः विश्लेषण के विषय थे। परन्तु इनको नजरअंदाज किया गया।

> नारीवादी स्थिति

कार्ल मार्क्स की 200 वें जन्मदिवस पर यह द्वि आलोचना भी चर्चा का विषय रही है : पितृसत्ता एवं पूंजीवाद में क्या संबंध हैं? किस हद तक उत्पादन का पूंजीवादी प्रकार न केवल एक लैंगिक व्यवस्था है अपितु एक नस्लवादी व्यवस्था भी है? दमन के सांस्कृतिक–सांकेतिक प्रकार किस प्रकार राजनीति एवं अर्थशास्त्र में दमन के अन्य प्रकारों से अन्तःक्रिया करते है? आगे हम, इन चर्चाओं के सामयिक उद्भव की हम समीक्षा करेंगे।

> उत्पादन एवं प्रजनन

उत्पादन एवं प्रजनन के मध्य संबंध नारीवादी चर्चाओं में विशेषतः महत्वपूर्ण रहा है। महिलाएं आज भी दुनिया भर में घर का और देखरेख का अवैतनिक ज्यादातर कार्य करती है। लैंगिक श्रम विभाजन को प्राकृतिक श्रम विभाजन के रूप में वर्गीकृत करना इस तथ्य को अस्पष्ट करता है कि यह पूंजीवादी उत्पादन का एक निर्माणात्मक भाग है फिर भी जिसका मूल्य व्यवस्थित रूप से कम आंका गया एवं जिसे खंडित किया गया। रम का वैश्विक विभाजन जो कि श्रम एवं प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के साथ जुड़ा है नारीवाद चर्चाओं का महत्वपूर्ण संदर्भ बिन्दु रहा है। वैश्विक दमन एवं शोषण के उत्तर उपनिवेशवादी एवं सामाजिक नारीवादी आलोचक वैश्विक दक्षिण में नारी की निम्न स्थिति पर विशेषतः केन्द्रित रहते हैं एवं उनका वैश्विक उत्पादन एवं देखरेख करने वाली श्रृंखलाओं में एकीकरण की आलोचना करते हैं। साथ ही, किराये की कोख वाले मातृत्व को न केवल प्रजनन की नवीन तकनीक के

> >

महिलाओं की ट्रेड यूनियन लीग, खील सेन्टर द्वारा चित्र, कोरनेल विश्वविद्यालय

रूप में देखा जाता है अपितु अंतराष्ट्रीय श्रम विभाजन एवं शोषण के प्रकारों के रूप में भी देखा जाता है। इस संदर्भ में, नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक प्रजनन की परिस्थितियों को संरचित करने के साथ, यह भी विश्लेषित करता है कि राज्य किस प्रकार, कार्य एवं सैक्सुएलिटी के क्षेत्र में, संरचनात्मक शक्ति संबंधों को बनाये रखता है। वो इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि सामाजिक प्रजनन को उसके वैश्विक संदर्भ में देखा जाना चाहिये क्योंकि यह वैश्विक बाजार, वित्तिय एवं स्थानांतरगमन व्यवस्था की गतिकी से काफी नजदीकी तरीके से संबंधित है। इस प्रकार, वैश्विक आर्थिक विदा एवं संबंधित वित्तिय प्रक्रिया उन परिस्थितियों को प्रभावित करती है, जिनमें सामाजिक प्रजनन सेवायें प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिये, यह तब हुआ था, जब 2008 के वित्तिय विपदा के दौरान सामाजिक आधारभूत संरचना परिवार की पहुंच से दूर हो गयी या उन्हें यूरोप एवं यू. एस. ए. से बलपूर्ण निष्कासन के विरूद्ध लड़ना पड़ा। नेन्सी फ्रेसर के साथ, हम यह मान कर चलते हैं कि ''विपदा जो सामयिक पूंजीवादी परिस्थिति का लक्षण है आवश्यक रूप से तीन उलझी हुयी समस्याओं द्वारा निर्धारित होती है : प्रथम, उत्पादक एवं प्रजनन श्रम के मध्य संबंध; दूसरा, प्रकृति का शोषण; एवं तीसरा, वैश्विक पूंजीवाद में राज्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन। राज्य क्षमता के परिवर्तन के संबंध में इन संघर्षों के साथ, पूंजीवाद में वस्तुकरण के सैद्धांतिक आयाम, अनूठे नारीवाद विश्लेषण के लिये एक औचित्यपूर्ण विषय बन जाते हैं। इस संदर्भ में, यह प्रश्न कि किस प्रकार एवं क्या उत्पादकता एवं सामाजिक प्रजनन विविध मूल्यात्मक के रूप में अवधारित किया जा रहा है, की चर्चा आगे करनी होगी।

> विकल्प एवं बची हुयी चुनौतियां

विवादास्पद प्रश्न, हालांकि, रहते है : विकल्पों को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? कौन है या कौन ''क्रांतिकारी विषय'' (जब तक इस प्रकार की अवधारणा का त्याग नहीं किया जायेगा) होगा, एवं बंधनमुक्त होने की शक्ति कहां से आती है? उदाहरण के लिये, यह समझने योग्य है कि जो अवधारणायें मार्क्स के सिद्धांत का लक्षण है वो तात्कालिक समस्याओं को समझने में भी सक्षम है क्या? क्या अब हमें जैसा कि इंग्रिड कार्त–शैरफ सुझाव देती हैं, एक तरफ पूंजीवाद की गहरी समझ की एवं दूसरी ओर राजनीतिक अर्थव्यवस्था व्यापक समझ की आवश्यकता है ताकि गैर वस्तुनीत कार्य के क्षेत्र को दृष्टिगोचर बनाया जा सके? अंततः शायद साम्यवादी तर्क से परे जाकर ये क्षेत्र प्रकृति एवं मानव श्रम के शोषण का अंत करने के लिये सशक्त बने। ''देखरेख क्रांति'' परिप्रेक्ष्य जो गेबरिले विनकर एवं अन्य द्वारा लाया गया, का उद्देश्य है कि देखरेख के क्षेत्र को सामूहिक रूप से संचालित करना चाहता है, इस प्रकार के पूंजीवादी तर्क हटाते हैं एवं वैतनिक एवं अवैतनिक श्रम के मध्य विभाजन खत्म होगा।

उत्तर उपनिवेशवाद एवं नारीवादी परिप्रेक्ष्य, ज्यादा व्यापक विषय परिप्रेक्ष्य के लिये आवाज दे रहे है, क्योंकि श्वेत, पश्चिमी, पुरूष वर्ग विषय जिन पर मार्क्स ने बल दिया था अब परिवर्तित परिप्रेक्ष्य के वाहक नहीं बने रह सकते हैं।

> शिक्षण में नव उदारवाद एवं आलोचनावाद

नव उदारवादी ज्ञान उत्पादन के दौर में, सामान्य तौर पर विवेचनात्मक ज्ञान उत्पादन एवं विशेषतः नारीवादी आलोचना के लिये परिस्थितियां काफी मुश्किल हो गयी है, जो शिक्षा के क्षेत्र पर भी असर डाल रही हैं। नव–उदारवादी व्यक्तिकरण की प्रक्रिया में, यह प्रश्न किया जा सकता है कि किस प्रकार भिन्न विषय, परिवर्तन (या क्रांति) के लिये आम सहमति बनायेंगे। विश्वविद्यालयों में, नारीवादी आलोचकों को निरंतर पुरूष केन्द्रिता से जूझना पड़ रहा है एवं अब, जैसा कि दूसरे विज्ञानों में भी है, यह भी उपयोगिता एवं मुनाफे के पैमाने पर अनाश्रित है।

इस पृष्ठभूमि में, नारीवादी मार्क्सवाद परिप्रेक्ष्य को और विकसित करना एक चुनौती है। बहु–आलोचनावाद जो इसकी आधारशिला है, भी इसके अधिक हाशियेकरण का स्त्रोत है। इसको शिक्षा के क्षेत्र में एवं मार्क्स के वाम अभिनंदन उनके जिसने पुरूष केन्द्रित भेदभाव परावर्तित नहीं किया है, में अवलोकित किया जा सकता है। ■

सीधा संपर्क करे :
एलेक्सजेंड्रा शीले <alexandra.scheele@uni-bielefeld.de>
स्टीफेनी वोहल <stefanie.woehl@fh-vie.ac.at>

> मार्क्स और राज्य

बॉब जैसप, लैनकस्टर विश्वविद्यालय, यूके

मार्क्स ने वर्ग प्रभुत्व के एक अंग के रूप में राज्य और राजनैतिक प्रक्रिया के रूप में राज्य की शक्ति की एक व्यापक आलोचना नहीं लिखी। इसके अलावा, यद्यपि उनकी परियोजना उतनी ही राजनैतिक थी जितनी कि सैद्धांतिक, उन्होंने ऐसे विषयों जैसे संगठनात्मक रूप में राजनैतिक दल; राष्ट्र राष्ट्रवाद और राष्ट्र देशों; क्रांतिकारी रणनीति और तरीकों (समाजवाद की ओर संसदीय राह के दायरे को सम्मिलित करते हुये); ''सर्वहारा की तानाशाही'' के स्वरूप; या कैसे शक्तिशाली राज्य ''नष्ट'' हो सकता है; का कोई सुसंगत विश्लेषण प्रदान नहीं किया।

इसका अर्थ यह नहीं है कि मार्क्स (या उनके जीवनपर्यंत सहयोगी एगेंल्स) ने ऐसे मुद्दों को अनदेखा कर दिया। इसके विपरीत, उन्होंने राज्य का अनेक तरीकों से अन्वेषण किया। इसमें शास्त्रीय और अशिष्ट राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक श्रेणियों की मार्क्स की आलोचना के अनुरूप राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना; विकास, बदलती वास्तुकला, और विशिष्ट राज्यों का वर्ग चरित्र का ऐतिहासिक विश्लेषण; विशिष्ट राजनीतिक काल और/या महत्व पूर्ण घटनाओं का संयोजित विश्लेषण; पूंजीवादी प्रकार के राज्य के रूप का विश्लेषण; तथापि प्राथमिक रूप से संचयन के स्वरूप और तर्क के साथ संगति के संदर्भ में; यूरोप और अमेरिका से दूर समकालीन समाजों में राज्य के स्वरूपों और पूर्व–पूंजीवादी वर्ग–आधारित उत्पादन की प्रणालियों में राज्य का ऐतिहासिक विश्लेषण; और बदलते संकटों के अधिक रणनीतिक रूप से उन्मुख, राजनीतिक रूप से प्रेरित विवरण जिन्हें श्रमिक आंदोलनों में राजनीतिक बहसों को आकार देना चाहिये, शामिल है। इनका विश्लेषण अंतर्राज्यीय संबंधों, उपनिवेशवाद, सेनाओं का अंतर्राष्ट्रीय संतुलन, और शांति और युद्ध की राजनीति तक विस्तृत था।

एक संक्षिप्त टिप्पणी में मामलों को सरल करने के लिये, हम मार्क्स के कार्य में तीन प्रमुख विवरणों की पहचान कर सकते हैं। एक प्रचारात्मक पठन राज्य को आर्थिक, शोषण और राजनीतिक नियंत्रण के लिये आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग द्वारा कमोबेश सफल वर्ग शासन के एक साधन के रूप में देखता है। यह विचार खुले तौर पर व्यक्त किया गया है–परंतु तत्काल प्रचारात्मक और रणनीतिक प्रभाव के लिये–कम्यूनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र में, जो घोषणा करता है कि पूरे बुर्जुआ के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिये कार्यकारी तंत्र एक समिति है। इसके प्रचारात्मक मूल्य के अलावा, यह दावा उस समय के यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सीमित मताधिकार के प्रकाश में सही लगता है। 1870 के दशक में मताधिकार का प्रसार मुद्दे को जटिल बना देगा और समाजवाद के लिये एक संसदीय राह को कार्यसूची पर ला देगा। एक अधिक ऐतिहासिक पठन राज्य को संभावित रूप से स्वायत्त सत्ता के रूप में देखता है जो जनता के हित में वर्ग संघर्ष को विनियमित कर सके या राजनीतिक स्तर के निजी लाभ में हेरफेर कर सके। यह विचार 1850 के दशक में लुइस बोनापार्ट के तले फ्रांस के मार्क्स के विश्लेषण में सबसे अधिक प्रसिद्ध रूप से–और प्रेरणा के तौर पर–दिखाई देता है। दरअसल, उन्होंने एक बार सुझाव दिया था कि बोनापार्ट ने एक राज्य स्थापित किया था, जिसमें सेना बोनापार्ट के नेतृत्व में थी, ने स्वयं को समाज के एक हिस्से के खिलाफ दूसरे हिस्से के लिये काम करने की बजाय समाज के खिलाफ दर्शाना करना शुरू कर दिया। कुछ टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि प्रथम विचार वर्ग संघर्ष के सामान्य कालों को चिन्हित करता है और बाद का विचार उन असाधारण कालों को जब वर्ग संघर्ष में गतिरोध आ गया और/या सामाजिक विनाश के लिये चेतावनी देता है। यह सुझाव प्रचारात्मक विवरण को एक

>>

गंभीर सैद्धांतिक विश्लेषण के लिये ले (गलती) लेता है जिसे उसके बाद ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ सामंजस्य कर लेना चाहिये।

इस सुझाव की समस्या को तीसरे पठन में देखा जा सकता है जो कि हीगल के मार्क्स के शुरूआती आलोचनाओं में जड़े जमाये हुये है, जिस पर मार्क्स ने जीवनभर फिर से कार्य किया, और 1871 के पेरिस कम्यून पर उनकी टिप्पणी में फिर से स्पष्ट रूप से कहा गया। यहां राज्य राजनीतिक संगठन का अलगाववादी स्वरूप है जो कि शासकों और शासित के विभाजन पर आधारित है। यह विभाजन विभिन्न वर्ग–आधारित उत्पादन की प्रणालियों में, पूंजीवादी विकास के विभिन्न कालों और पूंजीवादी गठन के विभिन्न प्रकारों में विभिन्न स्वरूप ले लेता है। बहरहाल, जैसा कि मार्क्स ने सिविल वॉर इन फ्रांस (1871) के दूसरे मसौदे में लिखा था, राज्य शक्ति ''हमेशा सामजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये शक्ति है अर्थात् मौजूदा व्यवस्था इसलिये हड़पने वाले वर्गों द्वारा उत्पादक वर्गों का उत्पीड़न और शोषण।'' हालांकि, जैसा कि कैपिटल III, संप्रभुता और राजनीतिक प्रभुत्व का स्वरूप शोषण के स्वरूप से जुड़ा है। पूंजीवादी उत्पादन की प्रणालियों में, इसमें जनसंख्या पर संप्रभु राज्य का एक अव्यैक्तिक वर्चस्व होता है : यह प्रभु वर्गों के द्वारा प्रत्यक्ष शासन को शामिल नहीं करता है। इस प्रकार का राज्य संभव है क्योंकि शोषण श्रम बाजार में औपचारिक रूप से मुक्त आदान–प्रदान की मध्यस्थता के माध्यम से होता है (श्रम प्रक्रिया में तानाशाही के बावजूद) ताकि वर्गों का निर्धारण अतिरिक्त–आर्थिक दवाब या बाध्यकर सामाजिक संबंधों से मुक्त उत्पादन के संबंधों से हो। यह संवैधानिक राज्य की सीमाओं के भीतर राजनीतिक वर्ग संघर्ष और बाजार संबंधों की सीमाओं के भीतर चल रहे आर्थिक वर्ग संघर्ष के साथ उत्पीड़न और शोषण के आर्थिक और राजनीतिक क्षणों के संस्थागत विभाजन को संभव बनाता है।

यह फिर भी एक नाजुक संबंध है और विशिष्ट वर्ग समझौते के संस्थाकरण पर निर्भर करता है। वास्तव में क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1848–1850 के लेखन में, मार्क्स ने लोकतांत्रिक संविधान में व्यापक विरोधाभास की पहचान की। जबकि यह सर्वहारा वर्ग, किसानों और छोटे पूंजीपतियों जिनकी सामाजिक दासता को संविधान बनाता है, को सार्वभौतिक मताधिकार देता है, यह निजी संपत्ति अधिकारों की गारंटी के द्वारा बुर्जुआ की सामाजिक शक्ति को कायम रखता है। राजनीतिक स्थिरता के लिये आवश्यकता है कि दलित वर्गों को राजनीतिक से सामाजिक उत्थान की ओर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये; और यह कि बुर्जुआ को राजनीतिक बहाली पर जोर नहीं देना चाहिये। आर्थिक और राजनीतिक के संस्थागत विभाजन और इससे जनित विरोधाभास व्याख्या करते हैं कि क्यों मार्क्स विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास और विशिष्ट राजनीतिक नीतियों के सामग्री को स्पष्ट करने के लिये सीधे आर्थिक तर्कों का सहारा शायद ही कभी लेते हैं। इसके लिये वह तत्काल आर्थिक परिस्थितियों के बजाय राजनीतिक संघर्षों की विशिष्ट गत्यात्मकता पर निर्भर होते हैं। तदानुसार, यद्यपि वह आर्थिक परिस्थितियों, संकटों और विरोधाभासों का अध्ययन करते हैं, मार्क्स के अधिक मूर्त विश्लेषण भी ध्यान से राज्य स्वरूपों, राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संभाषणों, राजनीतिक ताकतों के संतुलन, इत्यादि का विचार करते हैं।

मार्क्स का दूसरा और तीसरा दृष्टिकोण परस्पर सुसंगत हैं और वर्तमान अनुसंधान और राजनीतिक विश्लेषण के लिये सबसे अधिक उपयोगी है। जाहिर है, एक लंबे लेख में विशिष्ट मामले और साथ ही बढते विश्व बाजार के एकीकरण पर मार्क्स की टिप्पणियों को शामिल करने की जरूरत होगी। परंतु पूर्ववर्ती टिप्पणियां यह दिखाने के लिये पर्याप्त हैं कि मार्क्स के विश्लेषण से आगे कैसे जायें। ■

सीधा संपर्क करे : **बॉब जैसप** <b.jessop@lancaster.ac.uk>

> पूंजीवादी विजय

कानून की प्रति एक नया मार्क्सवादी दृष्टिकोण

गुइलटर्मे लेत गोन्साल्व्स, रियो द जेनेरियो स्टेट यूनिवर्सिटी (यूइआरजे), ब्राजील

मूल कलाकृति (20 x 30 चित्रण बोर्ड पर वाटर कलर, 2011, फिलीपोनो चित्रकार बॉय डोमिंग्वेज द्वारा चित्र। ग्रीन ग्रेबिंग, जे पी एस विशिष्ट अंक 39 (2), अप्रेल 2012। जेम्स फेयरहेड, मेलिसा लीच एवं इयान स्कून्स द्वारा संपादित

> मार्क्सवाद और कानून

जितना भी हम कानून की मार्क्सवादी धारणा के बारे में जानते हैं वह एव्गेनी बी पाचुकानिस के कानूनी स्वरूप की आलोचना में बसा है। इसका प्रारंभिक बिंदु मार्क्स का तर्क है कि पूंजीवादी समाज में सामाजिकता मूल्य का रूप ले लेता है, जिसका अर्थ है कि मूर्त श्रम को वस्तुओं के आदान–प्रदान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। यह वस्तुओं के प्रत्येक मालिक की स्वायत्ता और समान इच्छा को मानता है। ऐसा सिर्फ एक कानूनी स्वरूप में मौजूद होगा। कानूनी स्वरूप, बदले में, असमानता को आत्म–प्रजनन का मुखौटा पहनाते हुये, मूर्त श्रम के विभिन्न स्वरूपों के मध्य एक अमूर्त समानता उत्पन्न करता है। कानून इस प्रकार एक बुत चरित्र प्राप्त कर लेता है।

कानूनी स्वरूप की पारंपरिक आलोचना कानून की संरचना का विश्लेषण करती है सिर्फ जब पैसा पूंजी में रूपांतरित हो जाता है और अधिशेष मूल्य का उत्पादन होता है। यह बताता है कि क्यों प्रभुत्व अमूर्त प्रभुत्व का रूप ले लेता है, कैसे तात्कालिक उत्पादक के श्रम के विनियोग को अदृश्य बनाया जाता है, और कैसे समकक्षों के मध्य आदान–प्रदान असमानता पैदा करता है। परंतु क्या पूंजीवाद स्वयं को इस चक्र तक नीचे लाता है?

> संचयन और विजय

पूंजी बनाये रखने के लिये, पूंजी को हमेशा स्थिर होना चाहिये। इसके लिये आवश्यकता से अधिक श्रम की जरूरत होती है, जो अधिशेष मूल्य और पूंजी का उत्पादन करती है। इस असीम प्रक्रिया को निर्मित मूल्य की प्राप्ति के लिये संभावित सामाजिक स्थितियों से निपटना होगा। तब वहां, अति संचयन जो कि मुनाफे को कम करता है, होता है। इस स्तर पर, अधिशेष मूल्य के प्रवाह के लिये पूंजी को अन्य सामाजिक स्थानों को रोकना चाहिये, जो मूल्यस्थिरीकरण के एक नये चक्र को शुरू करता है। ये गत्यात्मकतायें समकक्षों के आदान–प्रदान के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, परंतु (पुनः) मूल्यस्थिरीकरण के अनुसार ऐसे स्थानों को रोकने की क्षमता के अनुरूप हैं यह एक चल रहे आदिम संचयन का एक रूप है।

मार्क्स के कार्य में, आदिम संचयन पूंजीवादी उत्पादन की प्रणालियों के शुरूआती बिंदु के रूप में समझा जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादक को उत्पादन की साधनों से अलग करती है, जिसका परिणाम सामाजिक समूहों की हिंसात्मक बेदखली होता है और यह अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिये मुक्त लोगों का सृजन करती हैं। रोसा लक्समबर्ग का तर्क है कि यह पूंजीवाद के स्वयं के विकास के लिये एक कारक है; जैसा कि उत्पादन की स्थान प अधिशेष मूल्य के सिर्फ एक सीमित हिस्से में हेरफेर किया जा सकता है, व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवहारिक बनाने के लिये हमेशा बाहरी गैर–पूंजीवादी में बदल जाना चाहिये। ऐसी एक प्रक्रिया स्पष्ट हिंसा से चिन्हित होती है। डेविड हार्वे आगे विश्लेषण करते हैं कि कैसे पूंजी बेदखली के द्वारा संचयन के माध्यम से अति संचयन के संकट से उबरती है। इस तर्क से, क्लॉस डोरर ने विजय की प्रमेय को विकसित किया है : पूंजीवादी विस्तार अभी तक गैर–वस्तुकरण बाहरी के स्थायी और हिंसात्मक वस्तुकरण के रूप में।

विजय चरण में, पाचुकानिस के द्वारा वर्णित कानून का एक अलग चरित्र है। जैसा कि लक्समबर्ग कहते हैं, समकक्षों के आदान प्रदान में, ''शांति, संपत्ति और समानता, आकारों के रूप में, शासन करते हैं,'' जिसका अर्थ है कि ''किसी अन्य की संपत्ति का विनियोग संपत्ति के अधिकार में बदल जाता है; और वर्ग प्रभुत्व, समानता में।'' वैकल्पिक रूप से, गैर–पूंजीवादी स्थानों के विनियोग में, लक्समबर्ग पुष्टि करते हैं कि ''औपनिवेशिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रणाली, निजी ब्याज नीति और युद्ध नियम। यह वह जगह है जहां हिंसा, धोखाधड़ी, उत्पीडन और लूटपाट स्पष्ट हो जाती है।'' संक्षेप में, कानून स्पष्ट कानूनी हिंसा के और असमानता के तीव्रगामी नुस्खे के रूप में कार्य करता है।

> >

विजय इस प्रकार मौजूदा संपत्ति संबंधों में एक हिंसक परिवर्तन को उकसाने के लिये राज्य के माध्यम से विकसित किया गया है। यह मॉडल कानूनी सुधारों का एक परिणाम है जिनका लक्ष्य सामूहिक और आम संपत्ति को निजी में बदलने का है।

इसके अलावा, विजय में स्थानिक पुनर्निर्माण निहित है : स्थानीय जनसंख्या को निष्कासित कर दिया जाता है और, एक बार अपने सामान्य या आम स्थान से हटाये जाने पर, ये मुक्त दैनिक मजदूर बन जाते हैं और उत्पादन श्रंखला में अपनी नयी भूमिका में अनुशासित हो जाते हैं। इस प्रकार, सार्वजनिक और आम क्षेत्रों के विनियोग के साधन, कानून भी विनियोजित के नियंत्रण को सहज बनाता है।

> विजय और कानून

विजय का सामाजिक–कानूनी प्रजनन तीन चरणों में होता है:

1. कानूनी अनियमन

कानूनी अनियमन एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, जो गैर–पूंजीवादी बाहरी का विचलित और हीन अन्य के रूप में विवादित चरित्रांकन करता है। प्रमुख साधन मानवाधिकार है।

मानवाधिकारों का सार्वभौमिक चरित्र मानव प्रकृति के लिये स्वाभाविक मूल्यों के अस्तित्व की पूर्वकल्पना करता है, यह दावा करते हुये कि सभी लोगों से समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिये और कि मानवीय मूल्यों का कानूनी संरक्षण सार्वभौमिक है। इस प्रकार, अगर यह सच है कि व्यक्तियों को मानवता अपने अंदर लेकर चलना चाहिये, परंतु उनके कार्य प्रासंगिक हैं और मानवाधिकारों को स्वयं ही विरोध कर सकते हैं, यह मानवाधिकारों का कर्तव्य है कि वे विचलन से लडाई करें। यह न्याय की कसौटी को तय करने की प्रस्तावना है, जो कि सामाजिक प्रथाओं को आंकने के लिये उपयोग की जाती है।

वैश्विक पूंजीवाद में, यह वार्ता स्थानिक पदानुक्रम की रचना करता है : एक तरफ, आधुनिक तार्किकीकरण के साथ सभ्य स्थान; दूसरी ओर, अन्याय के खंड और अतार्किक मानदंड। परंतु यह अंतर, वास्तव में, समाज में मौजूदा शक्ति संबंधों को दर्शाता है। इस अर्थ में, न्याय का मानदंड शासक वर्ग के वर्ल्डव्यू का सार्वभौमिकरण है, जो अपने विशेष हितों को थोपने के लिये इसका उपयोग करता है। मानववादी संभाषण इस प्रकार बाहरी हस्तक्षेप और उपनिवेश का इंजन बन जाता है।

2. निजीकरण के कानूनी उपकरण

एक बार बाहरी का चित्रांकन अन्य के रूप में हो, वस्तुकरण हो सकता है। इस प्रक्रिया को आगे बढाने के लिये, कानून सार्वजनिक, सामूहिक और आम संपत्ति को निजी कर्ताओं के लिये हस्तांतरित को सक्षम करने के लिये उपकरण विकसित करता है। ये उपकरण अनियमन, निजीकरण और वैश्विक बाजार में दिये गये क्षेत्र खोलने के सुगम बनाते हैं। ये विभिन्न संस्थागत डिजाइनों के अंतर्गत दिखते हैं; संपत्तियों, सार्वजनिक कंपनियों, या क्षेत्रों की बिक्री; निजी कंपनियों को सार्वजनिक सेवा के प्रशासन या संपत्ति की हसतांतरण; आदि। ये सभी डिजाइन कानूनन चोरी के रूप में काम करते हैं, जिसमें राज्य, सार्थकता को बढ़ावा देने के औचित्य के तहत, लोगों को उनकी जमीन से हटाते हैं और मूल्य के सृजन के लिये भूखण्ड की पुनर्रचना करते हैं।

3. दंड विधि का उपयोग

''खूनी कानून'' के अपने विश्लेषण में, मार्क्स ने दंड संहिता के उपयोग को किसानों से उनकी जमीनों के स्वामित्वहरण के समांतर संचालित करने के रूप में बताया है। जैसा कि किसानों को निष्कासित कर दिया गया था और वे पूंजीपतियों को अपना श्रमबल बेचने के लिये मुक्त हो गये थे, उन्हें औद्योगिक अर्थव्यवस्था के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं किया गया। ये किसानों, अन्य प्रथाओं में समाजीकृत, श्रम के नये प्रतिमानों और जीवन जीने के तरीकों के अनुरूप नहीं थे। उन्हें स्वेच्छाचारिता के विरूद्ध दमनकारी कानूनों के माध्यम से नयी स्थितियों के अनुशासन से समायोजन करने के लिये विवश किया गया।

दंड विधि का यह कार्यात्मक स्वरूप विजय की प्रक्रियाओं में स्वयं को दोहराता है। कानूनी तकनीकों को अक्सर स्थानों के निजिकरण को सुगम बनाने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है, और सामाजिक समूहों और स्थानीय जनसंख्या की सामूहिकता ओर सांप्रदायिकता का टूटना–उनको अपनी श्रमशक्ति बेचने के लिये मुक्त कर रहा है। एक बार जब वे ''मुक्त'' हो जाते हैं, दंड विधि कर्मचारियों को अनुशासित करने के लिये उपयोग की जाती है। वर्तमान संदर्भ में, इसका मतलब अनिश्चित और लचीले कार्य संबंधों को अनुशासित करना है। यह गरीबी के अपराधीकरण की पद्धतियों के माध्यम से, लोगों को दैनिक श्रमिक के अनिश्चित व्यवस्था में प्रवेश करने के लिये विवश करके होता है।

> निष्कर्ष

पूंजीवाद के सामाजिक–कानूनी प्रजनन में दो उलझे हुये पहलू हैं। समकक्षों के आदान प्रदान के चक्र में, कानून अमूर्त समानता और स्वतंत्रता के रूप में काम करता है, जो कि वस्तुओं कर अंधभक्ति से जुड़ा हुआ है। पूंजीवाद की विस्तारवादी चक्र में, यह स्पष्ट कानूनी हिंसा के रूप में दिखाई पड़ता है, जैसा कि उपर्युक्त तीन चरणों में होता है। यह देखते हुये कि समकक्षों के आदान प्रदान का चक्र अतिसंचयन के गठन के लिये ले जाता है, यह हमेशा तंत्रिकागत बिंदु तक पहुंचता है, जो अभी तक गैर–वस्तुकरण बाहरी के नये स्वामित्वहरणों की सक्रियता की मांग करता है। इस प्रकार, पूंजीवाद का सामाजिक–कानूनी प्रजनन निरंतर अंधभक्त कानूनी स्वरूप और स्पष्ट कानूनी हिंसा के बीच में अदलबदल के माध्यम से व्यवहारिक रूप में उत्पन्न होता है। ■

सीधा संपर्क करे : **गुइलर्मे लेत गोन्साल्व्स** <guilherme.leite@uerj.br>

> भारत में मार्क्स और समाजशास्त्र

सतीश देशपांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत

लगभग बीसवीं सदी के मध्य से, ये सिर्फ एंग्लो–अमेरिकन पश्चिम में ही है कि अकादमिक मार्क्सवाद राजनीतिक मार्क्सवाद से अधिक छाया हुआ था। अधिकांश दुनिया में (सिर्फ पूर्वी यूरोप या पूर्व सोवियत रूस ही नहीं), मार्क्सवाद एक अकादमिक अनुनय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा रही है। यही कारण है, पश्चिम के बाहर के स्थानों के बारे में लिखते हुये, ''मार्क्स और समाजशास्त्र'' पर चर्चाओं के एक वृहद् सामाजिक संदर्भ में रखी जाने की जरूरत है।

1920 और 1925 के मध्य स्थापित, भारतीय कम्यूनिस्ट दल (सीपीआई) 1952, 1957 और 1962 के पहले तीन राष्ट्रीय चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, यद्यपि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जीती गयी 360 से अधिक सीटों के मुकाबले में 30 से कम सीटें जीती थी। हालांकि सीपीआई ने 1957 में केरल के दक्षिण राज्य (वर्तमान जनसंख्या 33 मिलियन) में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चयनित कम्यूनिस्ट सरकार का गठन कर विशिष्टता प्राप्त की। सीपीआई–मार्क्सवादी, या सीपीएम (1964 में एक विभाजन के बाद गठित) पश्चिम बंगाल (जनसंख्या 91 मिलियन) के पूर्वी राज्य में 34 वर्षों (1977 से 2011 तक) तक निरंतर चुने गये। परंतु कम्यूनिस्म की चुनावी महत्ता घट चुकी है और आज केंद्रिय भारत के वन क्षेत्रों के जनजातीय लोगों पर आधारित माओवादी समूहों के एक गठबंधन और भारतीय राज्य के बीच चल रहे सैन्य संघर्षों के माध्यम से इसका प्रभाव महसूस किया जाता है, मुख्यतः छत्तीसगढ़ (जनसंख्या 26 मिलियन) राज्य में। प्रभाव का एक अधिक सीमित स्त्रोत मार्क्सवादी दलों और आंदोलनों के प्रति निष्ठा वाले छात्र संगठनों के माध्यम से है।

मार्क्सवाद भारतीय अकादमी में भी महत्वपूर्ण रहा है, परंतु इसका प्रभाव समाजशास्त्र की तुलना में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अधिक है। समाजशास्त्र के अंदर तीन विद्व ानों का सबसे अधिक प्रभाव रहा है; सभी ने भारतीय समाजशास्त्रीय समाज (या इसके पूर्ववर्तीयों) के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है।

इनमें सबसे पहले धुर्जटी प्रसाद मुकर्जी (1894–1961) थे, एक प्रभावशाली बुद्धिजीवी जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में 1922 से 1954 तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संयुक्त विभाग में पढ़ाया था। मुकर्जी प्रमुखतः मार्क्सवादी पद्धति में रूचि रखते थे, जो कि उनकी पुस्तक ऑन इंडियन हिस्टरी : अ स्टडी इन मैथड (1945) का विषय था। वह मार्क्सवाद और इसकी सैद्धांतिक प्रवृत्तियों के बारे में अपने संदेहों के कारण स्वयं को मार्क्सवादी की बजाय ''मार्क्सोलोजिस्ट'' कहते थे जो इसकों भारतीय संदर्भों की विशिष्टताओं को संबोधित करने से रोकती है।

अक्षय रमणलाल देसाई (1915–1994) यकीनन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्र के विकास के लिये सबसे अधिक काम किया। उन्होंने राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और अंत में ट्रॉटस्कीवादी राजनीतिक संगठनों (जिनमें उन्होंने आजीवन सदस्यता बनाये रखी) के लिये पूर्णकालिक आयोजक के रूप में काम करने के बाद, शिक्षण में देरी से प्रवेश किया। बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रस्तुत समाजशास्त्र में उनकी डॉक्टोरल थीसीस 1948 में द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिस्म के रूप में प्रकाशित हुयी जो बारह रिप्रिंटस्, छः संस्करणों और अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद के बाद आज भी चिरकालिक श्रेष्ठ पुस्तक बनी हुयी है। यह पुस्तक उपनिवेशवाद से उत्पन्न आर्थिक रूपांतरण को सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़ने के लिये ''इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा'' का उपयोग करती है जिसने अंततः राष्ट्रवाद का निर्माण किया। देसाई का तर्क था कि औपनिवेशिक काल में पहले ही शुरू हो चुका पूंजीवादी विकास, सीपीआई और सीपीएम की पार्टी लाइन के उलट चला गया जो जोर देता था कि भारतीय समाज अभी भी ''अर्ध–सामंती'' है। राष्ट्रवाद के अलावा, उन्होंने किसानों और कृषक संघर्षों पर भी पुस्तकें प्रकाशित की और साथ ही मानव अधिकारों और राज्य द्वारा उनके उल्लंघन पर पुस्तक जितनी लंबी चर्चाये की। देसाई 1951 में बॉम्बे के समाजशास्त्र विभाग से जुड़ गये और 1969 में इसके अध्यक्ष बन गये। उनका समग्र योगदान भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्र के विकास के लिये एक स्पष्ट प्रयास करने और इस दृष्टिकोण को अपने विद्यार्थियों और अन्य विद्वानों जिनको उन्होंने परामर्श दिया, के बीच बढ़ावा देने में है।

> >

“दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, मार्क्सवाद शैक्षणिक प्रेरणा के अपितु राजनैतिक विचारधारा के रूप में कहीं अधिक महत्वपूर्ण रहा है।”

दत्तात्रेय नारायण धनाग्रे (1936–2017) ने सॅसेक्स विश्वविद्यालय में ब्रिटिश मार्क्सवादी समाजशास्त्री टॉम बोटोमोर के साथ अध्ययन किया और अपना अधिकांश कॅरियर पूना विश्वविद्यालय में शिक्षण करते हुये बिताया। धनाग्रे का सबसे अधिक जाना जाने वाला कार्य सामाजिक आंदोलनों पर है, खासकर पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया (1983) और पॉपुलिस्म एंड पॉवर (2015)। अपने लेखनों और अपने स्नातक छात्रों के माध्यम से, धनाग्रे ने भारतीय समाजशास्त्र में वर्ग विश्लेषण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य इतिहास (जहां वे प्रमुख हैं) और अर्थशास्त्र (जहां वे एक महत्वपूर्ण अल्प हैं) में अधिक प्रसिद्ध रहा है। मार्क्सवादी विद्वता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उदाहरण इन विषयों में तथाकथित ''उत्पादन की प्रणाली की बहस'' और दलित अध्ययन स्कूल के कार्यों में पाये जाते हैं।

उत्तर 1960 के दशक से शुरूआती 1980 के दशक तक, विद्वानों की एक पूरी पीढ़ी (अधिकांश अर्थशास्त्री) औपनिवेशिक काल के बाद से कृषक भारत में उत्पादन के तरीकों को चिन्हित करने के व्यापक प्रयासों में लगी हुयी थी। यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद में रूपांतरण पर मौरिस डॉब–पॉल स्वीजी बहस से संकेत लेकर, भारतीय उत्पादन के तरीके पर बहस ने सामंती–औपनिवेशिक कृषक प्रणाली में परिवर्तन की विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसने कृषि में पूंजीवाद को परिभाषित करने के प्रश्न को सैद्धांतिक परिष्कार के नये स्तर पर समृद्ध अनुभवजन्य विस्तार विषयों में संबोधित करके उठाया जैसे कि: मजदूरी बनाम परिवार श्रम; अधिशेषों का उत्पादक बनाम अनुत्पादक उपयोग; पूंजी–श्रम संबंध में अतिरिक्त–आर्थिक दवाब की भूमिका; ''उत्पादन का एक औपनिवेशिक तरीके'' की व्यवहार्यता; और पूंजी द्वारा श्रम के औपचारिक और वास्तविक सबसम्पशन के बीच मार्क्स के विभेदन का अर्थ।

शुरूआती 1980 के दशक से 2000 के दशक तक अधीनस्थ अध्ययनों के शीर्षक के अंदर कार्य कर रहे विद्वानों का समूह मार्क्सवादी इतिहासविद्या के मौजूदा संस्करण और प्रमुखतः भारतीय राष्ट्रवाद के इसके व्यवहार की आलोचना के एक प्रयास के लिये साथ आया। यह तर्क देते हुये कि यह इतिहास अभिजात वर्ग पर ध्यान केंद्रित करता है और अधीनस्थ वर्गों को नजरअंदाज करता है, इस सामूहिकता ने ''देश के लिये भारतीय बुर्जुआ की आवाज उठाने की असफलता'' से चिन्हित ''प्रभुत्व के बिना प्रधानता'' के एक शासन के रूप में और अधीनस्थ लामबंदी की कमजोरी के साथ साथ अभिजात राष्ट्रवाद की ग्राम्शीयन विवेचना प्रस्तुत की। अधीनस्थ इतिहासकारों ने सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास और प्रतिरोध और लामबंदी के लोक रूपों पर जोर दिया। सामूहिकता को भंग कर दिया गया, हालांकि इसके सदस्य सक्रिय शिक्षाविद् और बुद्धिजीवी बने हुये हैं।

अंत में, मार्क्सवाद भारतीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञानों (अर्थशास्त्र के अलावा जो कि हाल ही में) का एक नियमित भाग है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भारत में उनकी महत्ता को बरकरार रखते हैं, परंतु व्यापक वैश्विक रूझानों को प्रतिबिंबित करते हुये अधिक विस्तृत और संकर बन जाते हैं। ■

सीधा संपर्क करे : **सतीश देशपांडे** <sdeshpande7@gmail.com>

> इक्कीसवीं सदी में मार्क्स

मिशेल विलियमस्[1], विटवाटरस्रेंड विश्वविद्यालय, दक्षिणी अफ्रीका और अर्थव्यवस्था और समाज (आरसी 02) और श्रमिक आंदोलन (आरसी 44) पर आईएसए शोध समिति के सदस्य

मार्क्सवादी सिद्धान्त में प्रजाति और वर्ग के मध्य प्रतिच्छेदन पर पुनर्विचार

पूंजीवाद के उद्धारकारी और दमनकारी आयामों के बारे में मार्क्स के विचारों ने 150 वर्षों में विश्वभर के विद्वानों, राजनीतिज्ञों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है और मार्क्सवाद के नाम से जानी जाने वाली एक संपूर्ण बौद्धिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। शायद ऍडम स्मिथ, चार्ल्स डार्विन, महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद और बुद्ध की अलावा कुछ भी बुद्धिजीवीयों और अतिवादी कर्ताओं ने ऐसा प्रभाव डाला है।

मार्क्सवाद ने पूंजीवाद को समझने और समझाने और इसका प्रतिरोध करने और दुनिया को बदलने की साथ साथ कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में, मार्क्सवाद का योगदान दोहरा है: (1) पूंजीवाद के गत्यात्मकता के बारे में विश्लेषणात्मक विचारों के एक समूह के रूप में; और (2) राजनीतिक आंदोलनों की एक विचार धारा और मार्गदर्शक के रूप में। बींसवी सदी दुनिया के बड़े क्षेत्रों को समाहित करते हुये मार्क्सवादी आंदोलनों, समूहों और राज्यों से भरी हुयी थी।

> मार्क्स के विचारों का असर

मैं मार्क्स के विचारों के प्रभाव से शुरू करता हूं। उनके विचारों ने आधुनिक सामाजिक सिद्धांत को प्रभावित किया है, जहां वह पूंजीवादी आधुनिकता की प्रकृति के बारे में सामाजिक अध्ययन की शुरूआत करते हैं। उनका प्रभाव समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, मीडिया, दर्शनशास्त्र, नृविज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ प्राकृतिक और कठिन विज्ञानों (भूगोल और सूचना प्रौद्योगिकी सहित) और मानविकी (कला, अलंकार और साहित्यक अध्ययन और शिक्षा) तक विस्तृत है। 2008 के आर्थिक संकट के बाद, मुख्यधारा के अर्थशास्त्री भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि पूंजीवाद के मार्क्स के विश्लेषण ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मार्क्स पूंजीवाद का एक सबसे अधिक परिष्कृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, परंतु यह सिर्फ पूंजीवाद का विश्लेषण नहीं है जिसने वाम कल्पना को बांधा है। भावी उत्तर–पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में मार्क्स की अवधारणा और अंतर्निहित सुझावों ने बींसवी सदी में समाजवाद के बारे में कुछ बहुत विपुल और सैद्धांतिक तौर पर परिष्कृत सोच को प्रेरित किया है और इक्कीसवीं सदी के समाजवाद के बारे में सोचने के लिये प्रेरित कर रही है, उदारण के लिये लैटिन अमेरिका में।

मार्क्स के प्रभाव का दूसरा पहलू राजनीतिक आंदोलनों पर उनके विचारों का प्रभाव है। पूंजीवाद के लिये अधिकांश बींसवी–सदी के विकल्प मार्क्स की भावी उत्तर–पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में विचारों में अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इतिहास मार्क्सवाद–प्रेरित आंदोलनों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, परंतु दुर्भाग्य से इन प्रयोगों में से कई के पास सत्तावादी, उत्पीड़न, शोषण और यहां तक कि नरसंहार का लज्जाजनक इतिहास है। व्यवहार में मार्क्सवाद का यौनवाद, नस्लवाद और औपनिवेशिक संबंधों के समर्थन करने का इतिहास भी है। आज हम यह भी देखते है कि चीन और वियतनाम ''राज्य

>>

समाजवाद'' के नाम पर बाजार पूंजीवाद की ओर बढ़ गये है। हम इन इतिहासों को नजरअंदाज या इनमें इनकार नहीं कर सकते।

फिर भी, मार्क्स और मार्क्सवाद ने असाधारण आंदोलनों को प्रेरित किया है और दुनियाभार के लोगों को साथ लाकर खड़ा किया है। रूसी क्रांति में सोवियत संघ, उपनिवेश–विरोधी आंदोलन और दक्षिणी अफ्रीकी मुक्ति आंदोलन के साथ क्यूबा की एकजुटता और अंगोला में उनकी रंगभेद शासन के साथ क्रूर और घातक लड़ाई, ऐसे ही उदाहरण हैं। मार्क्स की विरासत सबसे गंभीर रूप से उन तरीकों में व्यक्त होती है जिनमें उनके विचारों ने लोगों को उत्तर–पूंजीवादी संसार के लिये सोचने और लड़ने के लिये प्रेरित किया–एक दुनिया जो अधिक समानतावादी, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और शोषण व उत्पीड़न के सभी प्रकारों से मुक्त हो।

आज, इसके शक्ति के मार्क्सवाद–विरोधी विचारों के साथ उत्तर–आधुनिकता के उदय, सामाजिक अलगाव, अनिश्चितता, असमानता और सीमांतीकरण ने मार्क्सवादी विश्लेषण के महत्व को पुनः प्रज्वलित कर दिया है। मार्क्सवादी का हाल का पुनरूत्थान सामान्य तौर पर सिर्फ उन्नींसवी–और–बींसवी–सदी की मार्क्सवाद की समझ की वापसी नहीं है। मार्क्सवाद के टिके रहने के लिये, पुस्तकों को सैद्धांतवादी और शुद्ध तरीकों से नहीं पढ़ा जा सकता, और राजनीतिक प्रथाओं को अग्सेना से आगे बढ़ना होगा। मार्क्स की विरासत हमारे निरंतर पुनरूत्थान और सिद्धांत के नवीनीकरण के माध्यम से बनी रहेगी ताकि हमारी यह दुनिया, जिसमें हम रहते हैं, पर प्रकाश डालने से लगातार हमारी मदद करता रह सके। जैसा कि नारीवाद ने 1970 के दशक में मार्क्सवाद पर पकड़ बनायी और सामाजिक पुनरूत्पादन, अन्तरअनुभागीयता, और उत्पीड़न के कई रूपों के विचारों का सैद्धांतिकरण किया, हमें मार्क्स और मार्क्सवाद के विचारों को नस्ल, लिंग, यौन उन्मुखीकरण, उद्धारकारी परियोजनाओं के लिये लोकतंत्र के महत्व और पारिस्थितिकीय सीमाओं और पूंजीवाद के वैश्विक संकट के समकालीन मुद्दों पर उपयोग करने की जरूरत है।

> दक्षिण अफ्रीका का मामला

दक्षिण अफ्रीका में, हमारी एक सबसे बड़ी चुनौती मार्क्सवाद को रंगभेद के बाद जाति और नस्लवाद के चारों ओर उत्पादक कामों में लाना था। जाति के मुद्दे को संबोधित करने में मार्क्सवाद की असफलता इस तथ्य से निकलती है कि शुरूआती मार्क्सवादीयों ने जाति को एक सामाजिक बनावट और असत्य चेतना के एक प्रतिबिंब के रूप में देखा। जाति का मुद्दा पूरी बींसवी सदी के दौरान ब्रिटिश शासन के निधन, रूसी क्रांति, अउपनिवेशवाद, और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के जैसे संदर्भों में राष्ट्रीय प्रश्न बहसों में बार बार उठा। जैसा कि मार्क्सवादीयों ने जाति के मुद्दे को उठाना शुरू किया, प्रायः जाति को वर्ग तक और जातिवाद को पूंजीवादी संचयन के भीतर इसकी कार्यक्षमता तक सीमित करते हुये, वे जाति और वर्ग के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। मार्क्सवादीयों ने यह तर्क दिया कि जातिवाद श्रमजीवी वर्ग को विभाजित करता है और श्रमजीवी वर्ग में एकजुटता की राजनीति के माध्यम से इसे चुनौती दिये जाने की जरूरत है। मार्क्सवाद श्रमजीवी वर्ग पहचान में सार्वभौमिकता को जातिवाद की विशिष्टता को चिढ़ाते हुये देखता है।

एक अधिक परिष्कृत सैद्धांतिक विश्लेषण ऐतिहासिक प्रासंगिकता के साथ–साथ उत्पादन के पूर्व–पूंजीवादी और पूंजीवादी प्रणालियों के बीच संचोजनों पर रोशनी डालते हुये जाति और वर्ग के प्रतिच्छेदन की जांच करता है। दक्षिण अफ्रीका में, जाति और वर्ग के मध्य स्पष्टता रंगभेद राज्य की प्रणालीगत जाति–आधारित राजनीतिक उत्पीड़न, जो पूंजीवादी शोषण के साथ मिलकर, के साथ एक विशेष अतिआवश्यकता लाती है। हालांकि, रंगभेद के अंत के बावजूद, एक पूंजीवाद जिसमें दोनों अपक्षरित और पुनरूत्पादित रूपों का नस्लीय उत्पीड़न है के माध्यम से नस्लीय उत्पीड़न के स्वरूप समकालीन दक्षिण अफ्रीका में निरंतर बने हुये हैं। वैश्विक पूंजीवाद में नस्लीय उत्पीड़न की निरंतरता को समझने के लिये, दक्षिण अफ्रीका में और दुनियाभर में कई अन्य स्थानों में एक नये मार्क्सवादी विश्लेषण की आवश्यकता है, जो उभरना शुरू हो रहा है।

> निष्कर्ष

मार्क्स और मार्क्सवाद के विचार इक्कीसवीं सदी में केवल तभी गूंजते रहेंगे यदि हम इन्हें हमारे वर्तमान समय में संलग्न करने, परिवर्तन करने और पुनः सूत्रबद्ध करने के लिये पर्याप्त साहसी होंगे। नये पूंजीवाद–विरोधी आंदोलन उत्तर–सेनाग्र मार्क्सवाद को पूंजीवाद–विरोधी परंपराओं जैसे कि नारीवाद, पारिस्थितिकी, अराजकतावाद, नस्लवाद, विरोधी, और लोकतांत्रिक और स्वदेशी परंपराओं के साथ लाने के माध्यम से पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। ये आंदोलन उनको लेकर चलने के लिये एक सुसंगत वैचारिक खाके I एक अग्सेना अभिजात की तलाश नहीं कर रहे हैं, परंतु यह विश्वास साझा करते हैं कि लोकतंत्र, समानतावाद, पारिस्थितिकी, और आम लोगों द्वारा बनाये गये पूंजीवाद के प्रणालीगत विकल्पों के माध्यम से ''दूसरी दुनिया संभव है''। यह मार्क्स की स्वयं के अनु–संधान की आत्मा में है! ■

[1]ये विचार दो लेखों पर आधारित हैं: Satgar, V. and Williams M. (2017) "Marxism and Class" in Kathleen Korgen (ed.) The Cambridge Handbook of Sociology. Cambridge : Cambridge University Press; Williams, M. (2013) "Introduction" in Michelle Williams and VishwasSatgar (eds.) Marxisms in the 21st Century: Crisis, Critique & Struggle, Johannesburg: W its University Press.

सीधा संपर्क करे : **मिशेल विलियम्स** <michelle.williams@wits.ac.za>

> मार्क्स एवं वैश्विक दक्षिण

राजू दास, यॉर्क विश्वविद्यालय, कनाडा आई एस ए की अर्थव्यवस्था एवं समाज की शोध समिति (आरसी 02) के सदस्य एवं **डेविड फेसनमेस्ट,** वेन राज्य विश्वविद्यालय, यू. एस. ए., अर्थव्यवस्था एवं समाज (आरसी 02). पर आई एस ए शोध समिति के कोषाध्यक्ष

कार्ल मार्क्स यूरोप में 150 वर्ष पूर्व रहते थे, जहां उन्होंने राजनीति में भाग लिया एवं यूरोप के संबंध में लिखा। विद्वानों ने गणना की है कि उनके द्वारा लिखे हजारों पृष्ठों में से केवल 400 पृष्ठ यूरोप के बाहर के समाजों से सम्बन्धित है। इनमें से अधिकांश भारत, चीन एवं ऑटोमान साम्राज्य पर ब्रिटिश घरेलू नीति के दृष्टिकोण से लिखे गये थे। फिर, किस प्रकार उनके विचार समकालीन वैश्विक दक्षिण (अब से, दक्षिण), विश्व में अधिकांश आबादी वाले देशों का घर जो यूरोप और औद्योगिक उत्तर से आर्थिक रूप से कम विकसित हैं, के लिए औचित्यपूर्ण हैं?

उन प्रश्नों को परे रखकर कि मार्क्स ने कब लिखा या पूंजीवादी विकास का भौगोलिक केन्द्र क्या है, हम दक्षिण के लिये प्रासंगिक मार्क्स के द्वंद्वात्मक विचार के औचित्य पर बहस करेंगे। परन्तु पहले दो खतरों को टालने की आवश्यकता है : विश्व–क्षेत्रीय अपवाद (दक्षिण को पूर्णतः विशिष्ट बनाना) एवं यूरोप केन्द्रित सार्वभौमिकरण (उनके विचारों को इस प्रकार लागू करना जैसे दक्षिण के क्षेत्र गर्म यूरोप है या महज ''देर से यूरोप'' है)। हम इस दावे को खारिज करते हैं कि मार्क्स का औचित्य अपने समय एवं क्षेत्र तक सीमित है एवं इसलिए वह दक्षिण के लिये महत्वपूर्ण नहीं है – उत्तर उपनिवेशवादियों एवं उत्तर आधुनिक सिद्धान्तकारों नेल का दृष्टिकोण जो यह मानते हैं कि दक्षिण के क्षेत्र यूरोप से काफी अलग हैं। साफ तौर पर, मार्क्स पूर्ण रूप से दक्षिण के लिये औचित्यपूर्ण नहीं है परन्तु उसका काफी भाग है।

मार्क्स का विश्लेषण यूरोप पर केन्द्रित है, जहां पूंजीवाद ने व्यवस्था के रूप में अपनी जड़े रखी। न कि इस संदर्भ में कि यूरोप के अनुभव विशिष्ट थे या विशेषाधिकृत थे। हम यह काफी आराम से कह सकते हैं कि मार्क्स के विश्लेषण एवं लेखन एशिया एवं पूरे तीसरे विश्व में पूर्ण रूप से अपनाये गये एवं व्यावहारिक रूप से विकसित किये गये।

मार्क्स के विचारों को सामाजिक संबंध एवं भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया, उनके अमूर्त विचार सभी प्रकार के वर्ग समाज चाहे वो पूंजीवादी वर्ग समाज हो या पूंजीवादी के उन्नत रूपों के तहत वर्ग समाज के बारे में है। दूसरे में, जहां उनके कुछ विचार विकसित पूंजीवाद के लिये विशिष्ट है क्योंकि यह उन्नीसवीं सदी के यूरोप में उभरा। उस सीमा तक कि पूंजीवादी संबंध दक्षिण में विकसित होते हैं, यूरोप में विकसित पूंजीवाद के संबंध में विचार कुछ प्रासंगिकता रख सकते हैं।

मार्क्स के विचार पूर्ण रूप में, एक बौद्धिक कार्य के रूप में प्रतिबिंबित करते है एवं उग्र–प्रजातंत्र एवं सभी प्रकार के वर्ग–समाज का पूंजीवादी विरोधी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें महिलाओं एवं अल्पसंख्यीय जातियों जैसे दलित समूहों के प्रति समाज के गहन पूर्वाग्रह और भौतिक रीतियों को बदलना सम्मिलित है। मार्क्स की पूंजीवादी समाज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था, राज्य, संस्कृति एवं पारिस्थितिक परिवर्तन का ध्यान रखता है एवं क्रांतिकारी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में विचार रखती है।

जीवन की भौतिकता पर मार्क्स का केन्द्रित होना वैश्विक दक्षिण के लिये औचित्यपूर्ण है, जहां अधिकतर लोगों की आवश्यकतायें अपूर्ण रह जाती है। उनका भौतिकवादी द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य हमें दक्षिण को उसकी अहम् भौतिक समस्याओं भोजन, आश्रय, कपड़े आदि की कमी, उसके विभिन्न विरोधाभासों, साम्राज्यवादी व्यवस्था से उसके आंतरिक संबंध एवं इसी तरह अन्य संदर्भ में देखने की अनुमति देता है। उस सीमा तक कि दक्षिण का अध्ययन उत्तर उपनिवेशवाद/उत्तर आधुनिकवाद द्वारा आकारित है और ये परिप्रेक्ष्य मार्क्स को संदेह से देखते है। दक्षिण के उत्तर उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य की विलोचना, मार्क्स के स्वयं के दार्शनिक विचारों पर आधारित हो सकती है और होनी चाहिये। मार्क्स के अनुसार, प्रकृति के भाग के रूप में मानव की भौतिक के साथ सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानवको प्रकृति के एवं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करनी पड़ती है। वे उत्पादन के सामाजिक संबंधों के सन्दर्भ में, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, प्रकृति से निकलने वाले उत्पादन के साधनों के साथ अपने श्रम को जोड़ते हैं। उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ अधिशेष उत्पादित होता है और इसके साथ इस अधिशेष के लिए संभावित असमानता और वर्ग संघर्ष विकसित होता है। वर्ग समाज में चाहे वो दक्षिण उत्तर का हो, अधिकतर मुक्त एवं पराधीन श्रमिक अतिरिक्त श्रम करते हैं।

जैसा कि मार्क्स ने कैपिटल के खण्ड । में लिखा है :

''जहां भी समाज का एक हिस्सा उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार रखता है, श्रमिक चाहे वो मुक्त हो या पराधीन, उसको अपने श्रम समय में जो उसके स्वयं के अस्तित्व के लिये आवश्यक है, के साथ अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त समय में करना पड़ता है, ताकि मालिक जिनके पास उत्पादक साधन है का अस्तित्व बना रहे, वह

>>

“हम इस दावे को खारिज करते हैं कि मार्क्स की प्रासंगिकता उनके काल एवं स्थान तक सीमित है और इसलिए यह दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।”

मालिक चाहे [.....] एक दास मालिक, [....] एवं आधुनिक जमींदार हो या एक पूंजीपति हो।'' (मार्क्स, विन्टेज प्रेस, 1977 : 344)

यद्यपि मार्क्स के आनुभाविक उदाहरण यूरोप से आये थे, पूंजीवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण मूलतः वैश्विक या अंतराष्ट्रीय था। विश्व व्यापार पूंजीवाद की पूर्वधारणा थी, जब मार्क्स ने इंगित किया कि वस्तु उत्पादन एवं परिसंचरण पहले और जैसे–जैसे ज्यादा विकसित होता है अंतराष्ट्रीय वाणिज्य एवं व्यापार के लिये आधार बनता है। पूंजी का आधुनिक इतिहास, के विश्वव्यापी वाणिज्य और विश्वव्यापी बाजार के निर्माण से प्रारम्भ होता है। प्रभावी रूप से, व्यापार की वैश्विक–भौगोलिकी पूंजीवाद की पूर्वशर्त है जो पूंजीवाद को वैश्विक घटना बनाती है।

दक्षिण के देशों को मूलभूत रूप से मार्क्सवादी अर्थों में वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए, उन देशों के रूप में जिन्होंने असफल लोकतांत्रिक क्रांति या सामंती सम्बन्धों के खिलाफ कृषक आंदोलन, निष्फल राष्ट्रीय (या साम्राज्यवाद–विरोधी) आंदोलनों और निष्फल या असफल पूंजीवादी विरोधी क्रांति की पीड़ा झेली है। दक्षिण का पूंजीवाद, साम्राज्यवाद से गहरी तरह से प्रभावित है एवं ऐसे सामाजिक संरचना के साथ उसका अस्तित्व है जिसमें सामन्तवाद एवं वस्तु उत्पादन के अवशेष सम्मिलित हो सकते हैं जो मजदूरी श्रम के बजाय स्वदेशी सामूहिक परम्पराओं वाले अन्य सम्बन्धों पर आधारित होते हैं।

समापन में, वैश्विक दक्षिण, उत्तर–सोवियत समाज एवं अन्य उभरती हुयी बाजार अर्थ–व्यवस्था में मार्क्स के विचार भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य से विकसित किये गये। यह सामाजिक परिवर्तन को यूरोपियन केन्द्रित तरीके से समझने के विरोध में एवं पूंजीवाद का प्रतिरोध करने के लिये विकसित किये गये। यह तथ्य कि कई प्रकार के क्षेत्रीय मार्क्सवाद है जैसे अफ्रीकन मार्क्सवाद, एशियन मार्क्सवाद, लेटिन अमेरिकी मार्क्सवाद, भारतीय मार्क्सवाद एवं चीनी मार्क्सवाद (जिनका अब चीन के मुख्य विश्वविद्यालयों में मार्क्सवाद के विभिन्न स्कूलों में बढ़ावा दिया जा रहा है।) अंतराष्ट्रीय विकास पर मार्क्सवादी अध्ययन साम्राज्यवाद, कृषक परिवर्तन इत्यादि के संदर्भ में समृद्ध हो रहा है। इससे प्रतीत होता है कि मार्क्स उन मुद्दों के लिये औचित्यपूर्ण है जो दक्षिण से संबंधित है। यह इससे भी इंगित होता है कि दक्षिण या सामान्य तौर पर दक्षिण पर कार्य कररही मार्क्सवादी शोध पत्रिकाओं में मार्क्स के विचारों का संस्थानीकरण हो रहा है। ■

सीधा संपर्क करे :
डेविड फेसनमेस्ट <david.fasenfest@wayne.edu>
राजू दास <rajudas@yorku.ca>

> चीन में वर्गीय असमानता एवं सामाजिक संघर्ष

जेनी चान, हांगकांग पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय तथा श्रमिक आंदोलनों की आई एस ए की शोध समिति (आरसी 44) की सदस्य

चीन में पार्सल डिलीवरी व्यवस्था पर कार्य करते हुए। जेनी चान द्वारा चित्र

18 नवम्बर 2017 की रात को बीजिंग के दक्षिणी बाहरी इलाके में लगी आग में 19 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें 8 बच्चे थे। बेसमेंट (तलघर) के साथ यह दो मंजिला इमारत अनेक छोटे–छोटे कमरों में विभाजित थी और इसमें सस्ते किराये पर किरायेदार रहते थे। बचे हुए जीवित लोगों एवं आग से प्रभावित लोगों को आपातकालीन सहायता देने की बजाय सरकार ने हजारों लोगों को जो कि निम्न वर्ग (Low-end) के थे, छांटना शुरू किया। चीन की राजधानी में प्रशासनिक शब्दावली में निम्नवर्गीय (Low-end) लोगों को अपमानजनक भाषा को संबोध प्राप्त है। इस खतरनाक आग के लगने के बाद समूचे शहर में सुरक्षा संबंधी जांच का अभियान चलाया गया, किराये के इमारतों की संरचना जो कि अवैध थी, व्याख्यानों, भण्डार गृह, थोक बाजार, विद्यालयों, भोजनालय एवं दुकानों को तोड़ दिया गया जिसके कारण हाशिए पर खड़े अनेक लोगों एवं परिवारों का जीवन अचानक विखण्डन का शिकार हो गया। व्यापक पैमाने पर खाली कराये जाने वाले ऐसे अभियान न तो पहली बार हैं और न ही संभवतः यह आखिरी बार है। इन अभियानों का नागरिकीय समाज ने विरोध किया परंतु विरोध करने वालों की आवाज मुख्यधारा के राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जल्दी ही दबा दी गई। जैसे–जैसे चीन वैश्विक, मानचित्र पर विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, निम्न आय समूह के नागरिक एक शिष्ट जीवन प्रणाली एवं कार्य स्थितियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह इसलिए हुआ है क्योंकि विकसित होते नगरों (High-end-city) में यह समूह हाशिए पर आ रहे हैं। चीन का राज्य अनिवार्य रूप से अपनी वैचारिकी एवं उन कार्य प्रणालियों का परीक्षण कर रहा है जो कि चीन के सपनों को पूरा कर सके और उन लोगों को जो कि विषम स्थितियों के शिकार हैं, को बाहर किया जा सके।

> चीनी ग्रामीण अप्रवासियों के मध्य उत्पादन एवं सामाजिक पुनरूत्पादन की प्रक्रिया

पिछले चार दशकों से चीन में तीव्र गति से पूंजी संकेद्रण का एक मुख्य कारण वह अप्रवासी श्रम शक्ति थी जो गांव से नगरों में आयी वास्तव में पूंजी संकेद्रण इन पर वृहद् पैमाने पर आश्रित था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 282 मिलियन ग्रामीण अप्रवासी उत्पादन उद्योग, सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं और इनकी उपस्थिति देश भर के कस्बों एवं नगरों में देखी जा सकती है। 2009 के उपरांत आर्थिक बहाली के कारण लगभग 50 मिलियन श्रमिकों की संख्या की वृद्धि हुई है और यह चीन की कुल जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा है। नगरीय सरकारों ने ग्रामीण अप्रवासियों को सहायता के रूप में 'संकेत प्रणाली' (Points System) को

> >

चीन में जमीनी संचालन।
जेनी चान द्वारा चित्र।

अपनाया है हालांकि यह सभी ग्रामीण अप्रवासियों के लिए नहीं है, यह प्रणाली बड़े उद्यमियों के लिए विशेष रूप से है। इसके अंतर्गत आवास खरीदने की योग्यता, विशेष कुशलता से संबंधित रोजगार एवं शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर नगरों में घरों का नामांकन किया जाता है। इस सबके बावजूद अनेक वर्षों से नगरों में काम करने के उपरांत भी सामान्य रूप से पढ़े हुए शैक्षणिक अप्रवासियों की जनसंख्या का बड़ा भाग एवं उनके बच्चे दोयम दर्जे के नागरिक बने हुए हैं। उन्हें आज भी ग्रामीण आवासीय प्रस्थिति प्राप्त है और सार्वजनिक शिक्षा, रियायती स्वास्थ्य सेवा, सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि में उनकी बराबर की साझेदारी नहीं है जिससे श्रम की कीमत का शोषण संभव हो जाता है।

निम्न आय प्राप्त अप्रवासी श्रमिक सामान्यतः 'शयनघर' (dormitory) में रहते हैं जो कि नियोक्ता के लिए निवेश की दृष्टि से सस्ते होते हैं और साथ ही यह भी संभव हो जाता है कि श्रमिक उन घंटों का, जिनमें वह कार्यरत नहीं है, इस्तेमाल अगली पारी के काम की तैयारी के लिए कर सके। कार्य एवं श्रम के मध्य की सामाजिक एवं स्थानिक दूरी कम हुई है अथवा लगभग समाप्त हो गई है और इसके कारण नियोक्ता को वे श्रमिक मिल जाते हैं जो अतिरिक्त घंटे काम कर समय–सीमा के अंदर उत्पादन को सुनिश्चित कर सके। प्रारम्भ के औद्योगिक जिलों में एक स्थान पर लगभग सभी की उपलब्धता, उत्पादन कार्यशालाओं के बहुल प्रकार्यातामूलक शिल्प, भंडारण गृह एवं आवासीय स्थलों की लगभग ऐसी ही स्थिति थी जैसे आज समकालीन नगरों में हैं जहां अप्रवासी श्रमिकों का संकेद्रण ज्यादा है।

अपने निजी जीवन में एक सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज ने श्रमिक प्रबंधन के द्वारा संचालित सामूहिक शयनगृहों को छोड़कर निजी आवासीय स्थलों में किराये पर रहना चाहते थे बशर्ते वे ऐसे आवासीय गृहों को लेने में सक्षम हैं ये किराये के कमरे सामान्यतः कम कीमत के होते हैं, इनमें या तो कोई खिड़की नहीं होती है या केवल एक छोटी खिड़की होती है ताकि बाहरी विश्व के साथ इनका न्यूनतम संपर्क रह सके। कुछ आवासीय परिसरों में मच्छर, चूहे एवं कांकरोंच बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। विभिन्न सुविधाओं एवं संपत्ति प्रबंधन के शुल्कों में काफी भिन्नता पायी जाती है। निजी आवासों की कीमतें महानगरों में चूंकि बहुत ज्यादा हो चुकी है इसलिए आय अथवा कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूस्वामियों के पास चला जाता है।

शारीरिक श्रम अथवा निम्न श्रेणी के काम करने वाले अप्रवासीय अपने श्रम को खाद्य–सामग्री लाने–ले जाने, विभिन्न पैकेट्स को लाने–ले जाने, पैकेजिंग के काम में, कार सफाई करने वाले एवं घरों में काम करने वाले कामों के लिए बेचते हैं। यह तो कुछ ही उदाहरण है परंतु इन सब श्रम क्रियाओं से चीन की जी डी पी (सकल घरेलू उत्पाद) में काफी वृद्धि हुयी है। यह उदाहरण दर्शाते हैं कि उत्पादन संबंधी कार्यों से सेवा संबंधी कार्यों की तरफ तीव्र गति से बदलाव हो रहा विस्तार के कारण लाखों की संख्या में नये लचीले प्रकृति के रोजगार उत्पन्न हुआ हैं, जिन्हें विभिन्न प्लेटफार्म एवं एप्पस् ने उत्पन्न किया है। स्वतंत्र संविदा कर्मियों से जुड़े अनेक ठेकेदार हैं परंतु इन लचीले कामों में संलग्न लोगों अथवा संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय श्रम कानून का पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं है। परिणाम स्वरूप न तो इनके पास नौकरी संबंधी सुरक्षा है और न ही स्थायी आय का एक उपयुक्त माध्यम है। गैर–लाइसेंस शुदा कार्य स्थलों एवं गैर–पंजीकृत शयनकक्षों को भयंकर आग लगने के बाद बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप अनौपचारिक सेवाओं से जुड़े श्रमिकों, उनके बच्चों तथा साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के सामने अनेक संकट उत्पन्न हो गए। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अनेक लोगों को अस्थायी आवास का बहुत अधिक किराया देना होता है, जबकि अनेक श्रमिकों को इन विषम परिस्थितियों के कारण स्थान एवं नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा।

एक बहुत लंबे समय से चीन के आंतरिक अप्रवासी नगरीय सरकारों के द्वारा संचालित 'बाहर निकालो' अभियान से प्रताड़ित हो रहे हैं। विकास एवं आर्थिक रूपांतरण की तीव्र गति के कारण नगर से लेकर गांव तक नगरों के द्वारा गांव की कृषक भूमि एवं समूचे गांव पर अतिक्रमण की प्रक्रिया तीव्र हुयी है। अनेक ग्रामीण निवासी विस्थापित हो गए हैं और गांव की जमीन पर खेती करने अथवा घर वापिस लौटने की शक्ति खो बैठे हैं। अपने गृह गाँव के अंदर आवास के भूखंडों पर उनकी पहुंच समाप्त हो चुकी है जिसके कारण उन पर दबाव और बढ़ा है। नियोक्ता इन गांव वासियों, जिन्होंने अपने स्वामित्व की जमीन को खो दिया है, नौकरी पर नहीं रखना चाहते। यह खोयी हुई जमीन ही उनके जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम थी। नियोक्ता जिन लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं, के पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं कर रहे। ग्रामीण परियोजना से जुड़े हुए ठेकेदार विशेषतः निर्माण क्षेत्र के ठेकेदार अपने स्थानीय नेटवर्क को मजबूत कर उन कृषक मजदूरों को जो भूमि से वंचित हो गए हैं, नौकरी देने से इंकार कर देते हैं क्योंकि इनके श्रम का पारिश्रमिक देने के पहले इन ठेकेदारों को इन श्रमिकों के आधारभूत जीवनयापन के लिए उपयुक्त राशि प्रदान करनी होती है। जबकि पारिश्रमिक की राशि परियोजनाओं को पूरा करने के उपरांत ही वे प्रदान करने के इच्छुक होते हैं। एक तो रोजगारहीनता की स्थिति है और दूसरे सबसे न्यूनतम पारिश्रमिक संस्कृति एवं श्रम दोनों ही पूंजी संकेद्रण के आधार है। पूंजी संकेद्रण की तीव्र गति के लिए आवश्यक है कि प्रकृति एवं सस्ते श्रम का अधिक से अधिक दोहन किया जाए। भूमि से विस्थापन एवं सर्वहाराकरण की प्रक्रिया बीजिंग एवं उसे परे के क्षेत्रों में पूंजी संकेद्रण एवं उसके विकास के साथ जारी है। प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों के तत्वावधान में शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ग्रामीण एवं कृषक भूमि का और इसके साथ–साथ ग्रामीण एवं नगरीय श्रम का लाभ अर्जन करने के लिए बड़ी मात्रा में उपयोग किया है और इसलिए स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय आतंक के बावजूद श्रमिक संघर्ष तीव्र हुए हैं जो कि हर स्तर पर चीनी राज्य एवं वैश्विक पूंजी की शक्तियों के साथ संघर्षरत है।

अल्पकालिक प्रकृति के विरोधों जो कि स्थानीय एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में अर्थात् तटीय एवं आंतरिक चीन में तीव्र गति से उभर कर आए हैं जो कि वर्तमान दौर की विशेषता है, आवश्यकता इस बात की है कि इन आंदोलनों में अंतरावर्गीय एवं अंतःवर्गीय दृष्टि एवं ग्रामीण–नगरीय विभाजन के परे की एकता सम्मिलित हो, तभी यह आंदोलन व्यापक सामाजिक आंदोलन बन सकेंगे। बुद्धिजीवियों एवं सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के रूप में हमारा दायित्व है कि हम दमन का शिकार होने वाले श्रमिक वर्ग एवं अन्य सामाजिक वर्गों की जनसंख्या हेतु संघर्ष करें जो कि श्रम अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के लिए हो। एक सुरक्षित कार्य स्थल एवं न्यूनतम सुविधाओं वाले उपयुक्त आवासों की प्राप्ति के लिए एक कठिन संघर्ष आवश्यक हो जाता है। ■

सीधा संपर्क करे : **जैनी चान** <jenny.wl.chan@polyu.edu.hk>

> भारत में सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन

निहारिका जायसवाल, नई दिल्ली, भारत

विश्वविद्यालयों का बाजारीकरण भारत और दुनिया भर में सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है।

भारत में नव–उदारवादी नीतियों के आगमन, ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास एवं निजी शिक्षा दाताओं के समावेश से वैश्विक नेटवर्क एवं निजी क्षेत्र, यह बताने के लिये कि ''औचित्यपूर्ण ज्ञान'' क्या हैं समर्थ हैं। ''लोक हित'' के रूप में शिक्षा के विचार का स्थान इस विचार ने ले लिया है कि शिक्षा एक ''निजी वस्तु'' है। विश्वविद्यालयों का ''ब्रांड'' के रूप में विपणन किया जाता है जो ''विपणन योग्य पाठ्यक्रमों'' की वकालत करते हैं। इस विमर्श ने उदारवादी कलाओं को ''अनुत्पादक'' कहा गया है, जो समाजशास्त्र जैसे विषयों को पुनः गढ़ने के लिये विवश कर रहा है ताकि वो अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकें।

जहां, बाजारीकरण की तरफ इस व्यापक प्रवृत्ति को काफी स्वीकारा जा रहा है, जिसे कम ज्ञात है वो यह है कि सरकारी एवं निजी दोनों विश्वविद्यालय एक जैसी कार्य प्रणालियों की तरफ मुखित हो रहे हैं। यह अभिसरण उदार, निजी एवं वैश्विक प्रजातांत्रिक समाज में 'लोक' के अर्थ पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। मेरा तर्क दो सरकारी विश्वविद्यालयों–दिल्ली विश्वविद्यालय (डी. यू.) एवं अम्बेडकर विश्वविद्यालय (ए. यू. डी.) एवं एक निजी विश्वविद्यालय, शिव नादर विश्वविद्यालय, जो दिल्ली में स्थित है, में पढ़ाये जाने वाले स्नातक स्तर के समाजशास्त्र पाठ्यक्रम की संरचना और सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन से समर्थित है।

> >

डी. यू. की स्थापना 1922 में हुयी थी। 2012 से उसने अपने शैक्षणिक कार्यक्रम को निरन्तर संशोधित किया है। जो काफी महत्वपूर्ण है। वे वार्षिक व्यवस्था से सेमेस्टर व्यवस्था की तरफ, फिर चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की तरफ एवं अंततः 2015 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) की तरफ बढ़े हैं। ए. यू. डी. एक राज्य विश्वविद्यालय है जो 2010 में सिर्फ समाजविज्ञान एवं मानविकी के लिये स्थापित हुआ, जबकि एस. एन. यू. 2011 से कार्य कर रहा है। यद्यपि यह तीन विश्वविद्यालय अलग अलग समय, अलग अलग शैक्षणिक एजेंडा के साथ स्थापित हुए, उनकी कार्यप्रणाली समान प्रतीत होती है।

प्रथम, तीनों ही विश्वविद्यालय ''नवीनतम'', ''चुनाव'' एवं बेहतर रोजगार अवसरों के मूल्यों पर आधारित अध्ययन के एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं। एफ. वाई. यू. पी. एवं सी. बी. सी. एस. में ''वैकल्पिक'' के रूप में ज्यादा चुनाव करने की व्यवस्था है। जो लोकप्रिय विषयों जैसे विकास, मीडिया, पर्यावरण, विजुअल संस्कृतियां आदि पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एफ. वाई. यू. पी. स्कीम का ''एप्लाइड कोर्स'' अथवा सी. बी. एस. स्कीम के ''कौशल बढ़ाने वाले कोर्स ''अथवा ए. यू. डी. एवं एस. एन. यू. दोनों में ही यह विकल्प कि 'मुख्य' के साथ 'लघु' कर सकते है, यह सभी छात्रों के रोजगार के अवसर एवं स्वरोजगार के कौशल को बढ़ाते है।

दूसरा, कोर्स के अंतविषयी एवं सामयिक औचित्य को हाइलाइट किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एफ. वाइ. यू. पी. एवं सी. बी. सी. एस. में और ए. यू. डी. के समाजशास्त्र के प्रोग्राम में अंतविषय इस प्रकार लाया गया है कि विद्यार्थी के पास दूसरे विभाग से विषय को चयन करने का विकल्प होता है। एस. एन. यू. में ''लघु'' विषय एवं ''स्वतंत्र अध्ययन समूहों'' का चयन इसी प्रकार के अभिमुखन को दर्शाता है। अंतविषय परंपरा को इतिहास राजनीति विज्ञान या साहित्य में से कोर्स को ''वैकल्पिक'' या ''बुनियादी कोर्स'' के रूप में समावेशित करके लाया गया है। हालांकि, मुख्य समाजशास्त्र कोर्स में अन्य परिप्रेक्ष्य की उपस्थिति पाठ्यक्रम पाठन के द्वारा केवल ए. यू. डी. में ही समायोजित की गयी है। प्रोग्रामों का समकालीन औचित्य भी पठ्न एवं अनुसन्धान के विषयों द्वारा स्पष्ट किया गया है। सी. बी. सी. एस. एवं एफ. वाई. यू. पी. ने ''वैकल्पिक'' एवं ''बुनियादी कोर्स'' में कई नये विषयों को जैसे ''युद्ध का समाजशास्त्र'' ''एथिनपोग्राफिक फिल्म निर्माण'' आदि को प्रारम्भ किया है। इसके अतिरिक्त 1990 के प्रकाशित साहित्य स्पष्ट रूप से इन पाठ्यक्रमों की पाठन सूची में हावी है। उदाहरण के लिये, ए. यू. डी. के ''जेण्डर एवं समाज'' पाठ्यक्रम में 35 पुस्तकों में से 30, 1990 के दशक के बाद प्रकाशित हुई है। इस प्रकार, अध्ययन की नये विषयों, ज्ञान एवं विद्वता के स्त्रोतों के साथ ही अंतविषयी अन्तःक्रिया जो कि छात्रों के ज्ञान के आधार एवं कौशल को बढ़ाती है को शुरू करने का प्रयास किया गया है।

तीसरा, हर प्रोग्राम में विश्वविद्यालय–औद्योगिक संबंधों को ताकतवर बनाया गया है। सी. वी. सी. एस. में क्रेडिट व्यवस्था नियोक्त के लिये आकलन के मानक निर्धारित करती है। ''ऑरगेनाइजेशन एक्सपोजर'' अथवा ''वर्कशॉप ऑन एक्सप्रेशनस''। जैसे ए. यू. डी. में चलने वाले पाठ्यक्रम एवं एस. एन. यू. के ''रिसर्च एक्सपेरिमेंटल एंड एपलाइड लर्निंग'' ने विद्यार्थियों को विभिन्न एन. जी. ओ. एवं अनुसंधान संस्थाओं से रूबरू करवाया है। इसके अतिरिक्त नृवंशविज्ञान, मौलिक शोध, शोध प्रबंध लेखन या क्षेत्रीय अध्ययन पर स्नातक स्तर पर बल देना एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत में कम होती रूचि ''शैक्षिक'' अध्ययन की अपेक्षा व्यवहारिक शोध को प्रोत्साहित करती है।

चौथा, विश्वविद्यालय, विपणन व्यूहरचना के रूप में विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ वैश्विक साझेदारी कर रहे है। उदाहरण के लिये, ए. यू. डी. एवं एस. यू. डी. ने येल, सांइसिस पो., स्टेनफोर्ड, बर्कले आदि के साथ सहयोग स्थापित किया है ताकि छात्रों के बीच वो अपना स्थान बना पाये।

इस प्रकार समाजशास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञानों को अंतविषयी, सामयिक एवं एकीकृत विषयों के रूप में पैक किया गया है, जो अपने छात्रों को बेहतर जीवन अवसर एवं वैश्विक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। हालांकि सामाजिक विज्ञान का सार–उसका महत्व एवं रचनात्मकता अभी जोखिम में है।

डी. यू., ए. यू. डी. एवं एस. एन. यू. के मध्य समानता बताती है, कि ये सभी उस ज्ञान उत्पादन के एक समान ''पेराडिगम'' का प्रत्युत्तर दे रहे है जो नव–उदारवादी सिद्धांतों ने जारी किया है। यह परिवर्तन सरकारी विश्वविद्यालयों की भूमिका एवं प्रस्थिति पर असर डालता है क्योंकि, सरकारी संस्थानों के रूप में उनकी यह जिम्मेदारी है, कि वो शिक्षा का उपयोग सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में करें। परन्तु विश्वविद्यालय को वैश्विक बाजार में स्थापित करने की बढ़ती आवश्यकता ने इसे कमजोर बना दिया है। क्या बाजार–चलित शिक्षा अपने आपको ''लोक हित'' के रूप में बनाये रख सकती है? क्या हम प्रेक्टिशनर की भूमिका को ''शिक्षार्थियों'' अथवा ''उपभोक्ता'' के रूप में पहचानते हैं?

जो मुद्दा दांव पर है, वो है ''जन'' की दार्शनिक पुनः अवधारणा को स्थापित करना जिसे शिक्ष के नव–उदारवादी 'पैरोडिगम' ने दबा रखा है। निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका पर बहस की जड़े स्वामित्व के परिवर्तन में निहित नहीं है; अपितु वे जन क्षेत्र जन भूमिका, मूल्य एवं प्रेरणा के अर्थ में परिवर्तन से उपजी है। जन–क्षेत्र की विशिष्टता उसके सदस्यों के मध्य समानता, विमर्श की आलोचना, उसकी सभी सुझावों को समावेश करने की प्रवृत्ति एवं उसकी संवैधानिक अधिकारों एवं नागरिकता के क्षेत्र से वैद्य संगति है। इस प्रकार, समाज कल्याण राज्य शिक्षा, जल, सड़क या रोजगार तक जन सामान्य की पहुंच को जन जीवन के भाग के रूप में जिसकी रक्षा सरकारी संस्थायें करती है के रूप में सुनिश्चित करता है।

नई अवधारणा में, यह अपील कि, ''सरकारी'' एवं ''निजी'' विश्वविद्यालयों के सभी अन्तर को विलय कर दिया जाय ताकि ''वैश्विक विश्वविद्यालय'' का निर्माण हो सके, समानता, गहन सोच एवं जन सामान्य की पहुंच जो कि राष्ट्रो एवं प्रजातंत्रों के इतिहास द्वारा स्थापित की गई थी, को कमजोर करता है। भारत में सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक जनादेशों, ने सार्वजनिक क्षेत्र को खोखला कर दिया है। निष्कर्ष में, हालांकि विश्वविद्यालयों ने शायद वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर ली है, ''वैश्विक'' पैमानों को मान कर जिसे ''गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा'' के रूप में देखा जाता है परन्तु विभिन्न संदर्भों में विशिष्ट शक्ति राजनीति की उपेक्षा एवं ''जन'' को उनके प्रजातांत्रिक विषय वस्तु से रिक्त कर देना, सरकारी विश्वविद्यालयों के सार को रिक्त करता है। ■

सीधा संपर्क करे : **निहारिका जायसवाल** <niharika.27j@gmail.com>

> वैश्विक संवाद की नई एवं 'इतनी नई भी नहीं' संपादकीय टीम

इस अंक के साथ वैश्विक संवाद की संपादकीय टीम बदल गयी है। ब्रिगिटे ऑलेनबोकर एवं क्लास डोरे ने माईकल बुरावे से संपादन जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कई देशों के सहयोगियों की टीम द्वारा तैयार एवं 17 भाषाओं में अनुवादित हो कर वैश्विक संवाद विश्व भर से समाजशास्त्रियों के लेखों का वैश्विक शैक्षिक एवं अशैक्षणिक दर्शकों के लिये प्रकाशन करता है। लेखकों, अनुवादकों और समर्थकों के इतने व्यापक नेटवर्क से जुड़ना, सम्मानीय एवं चुनौतीपूर्ण है। यह नई एवं 'इतनी नई नहीं टीम' इस महत्वपूर्ण पत्रिका को मजबूत बनाने के लिये विश्व भर से समाजशास्त्रियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

ब्रिगेट ऑलेनबाकर, समाजशास्त्र की प्रोफेसर है एवं जोहान्स केपलर विश्वविद्यालय, लिंज, ऑस्ट्रिया में समाज का सिद्धान्त एवं सामाजिक विश्लेषण विभाग की अध्यक्ष हैं। इन्होंने वियना में 2016 में तृतीय आई. एस. ए. फोरम ऑफ सोशियोलॉजी का सह–आयोजन किया और स्थानीय आयोजक समिति की उपाध्यक्ष थी। उनके अनुसन्धन क्षेत्र में समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, जेंडर एवं अतः प्रतिच्छेदन अध्ययन एवं कार्य एवं देखभाल का समाजशास्त्र सम्मिलित है। वर्तमान में उनका अनुभवजन्य केन्द्रित है। अध्ययन 24 घंटे देखभाल एवं विश्वविद्यालय के बाजारीकरण पर **कलॉस डोरे,** फ्रेडरिच शिलर विश्वविद्यालय, जेना, जर्मनी में, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, जहां वो श्रम, औद्योगिक एवं आर्थिकी समाजशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष हैं। उनके शोध क्षेत्रों में, पूंजीवाद का सिद्धांत, वित्तिय पूंजीवाद लचीले एवं अनिश्चित रोजगार, श्रम संबंध एवं सामरिक संघवाद के साथ अन्य सम्मिलित है। फिलहाल वे जर्मन रिसर्च फाउनडेशन द्वारा वित्त पोषित पोस्ट ग्रोथ समाजों के शोध समूह के सह निदेशक (हार्टमुट रोजा के साथ) हैं।

नये संपादकों को एक नये सह संपादक **अर्पणा सुंदर** एवं दो सहायक संपादक जोहाना ग्रबनर एवं क्रिस्टीन शिशकरट का सहयोग प्राप्त हैं। अर्पणा सुंदर ने अपनी पी. एच. डी. राजनीति विज्ञान में टोरन्टो विश्वविद्यालय, कनाडा से प्राप्त की। उन्होंने रायरसन विश्वविद्यालय, टोरंटो में सहायक आचार्य के रूप में कार्य किया एवं 2016 तक अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय, बैंगलोर में सह आचार्य के रूप में कार्य किया जहां वो अभी भी विजिटिंग फैकल्टी हैं। **जोहान ग्रबनर** ने समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री ली है। वो जोहान्स केपलर, विश्वविद्यालय, लिंज, ऑस्ट्रिया में शोध कर रही हैं एवं उनके शोध के क्षेत्र हैं नारीवादी सिद्धान्त एवं जेंडर अध्ययन जो शरीर एवं गुणात्मक तरीकों पर केन्द्रित हैं। उनकी पी. एच. डी., विश्वविद्यालयों में लैंगिक असमानता पर केन्द्रित है। **क्रिस्टीन शिशकरट** के पास अमेरिकन अध्ययन में एम. ए. की डिग्री है एवं समाजशास्त्र 'लघु विषय' के रूप में है। वे शिलर विश्वविद्यालय, जेना, जर्मनी में समाजशास्त्र विभाग में पोस्ट–ग्रोथ समाज पर शोध समूह को प्रशासनिक निदेशक के रूप में कार्य करती हैं।

ब्रिजेट ऑलनबाकर

क्लाउस डोरे

किस्टिन शीकर्ट

जोहाना ग्रबनर

>>

अपर्णा सुंदर

लोला बुसुतिल.

अगस्त बागा

GLOBAL DIALOGUE

भाग्यवश, वैश्विक संवाद अपने लम्बे समय से रहे सहयोगियों पर भरोसा कर सकता है—बारसिलोना, स्पेन में स्थित वैश्विक संवाद के प्रबंध संपादक **लोला बुसुतिल** एवं **अगस्त बागा** (उर्फ अरबू) अपना कार्य जारी रखेंगे। उसी प्रकार क्षेत्रिय संपादक एवं अनुवादक भी विश्व भर में अपना कार्य जारी रखेंगे। लोला एवं अरबू ने माइकल के साथ 2010 में प्रथम अंक के प्रकाशन से सहयोग किया। लोला, जो कि एक पेशेवर अनुवादक एवं संपादक हैं हर अंक की समग्र गुणवत्ता का निरिक्षण करती हैं। अरबू जो एक पेशेवर ग्राफिक डिजाइनर एवं चित्रकार है वैश्विक संवाद की डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं।

जहां सभी क्षेत्रीय संपादक एवं अनुवादक दल नई एवं 'इतनी नई नहीं' टीम के साथ अपना सहयोग जारी रखेंगे, माइकल एक सहयोगी सलाहकार के रूप में रहेंगे, जिससे ग्लोबल डायलॉग का आराम से एवं प्रभावी रूप से विस्तरण हो सके एवं भविष्य में उसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। अंतिम परंतु काफी महत्वपूर्ण, आई. एस. ए. की प्रकाशन समिति के साथ सहयोग जारी रहेगा। सलाहकार संपादक के रूप में कार्यकारी समिति के सदस्य एवं आई. एस. ए. की कार्यकारी सचिव इजाबेला बारलिंसका एवं मेडरिड में उनकी टीम जिनके सहयोग से ग्लोबल डायलॉग जैसा प्रयास सफल हो पाया है। सलाहकार संपादक के रूप में रहेंगे।

ऐसी संपादकीय टीम के साथ जिसके सात लोग चार अलग अलग देशों में रहते हैं एवं क्षेत्रीय संपादक और छात्रों, युवा विद्वानों एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों की अनुवादक टीम जो 17 देशों से है, के साथ कार्य करना, चुनौतीपूर्ण एवं आकर्षक है। यह हमें अवसर देता है कि वैश्विक संवाद को एक ऐसे साधन के रूप में लाये, जो व्यापक प्रकार के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को आवाज देने एवं स्थानीय दृष्टि को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह सामाजिक एवं वैज्ञानिक विकास पर जीवंत विरोधाभास एवं उत्पादक बहस के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह स्थापित एवं युवा विद्वानों को एक समान मंच प्रदान करता है और इस प्रकार यह समाजशास्त्रियों का वैश्विक स्तर पर नेटवर्क बनाता है जो अपने समय के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा और विमर्श करते हैं।

टीम के रूप में, हम उन सभी लोगों से संपर्क की आशा करते हैं, जो एक समान वैश्विक संवाद में रूचि रखते हैं। ■